चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

मूल्य 5 रुपये

1986 से प्रकाशित | 01 सितंबर-07 सितंबर 2014 | Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

इतिहास फिर से क्यों लिखा जाना चाहिए

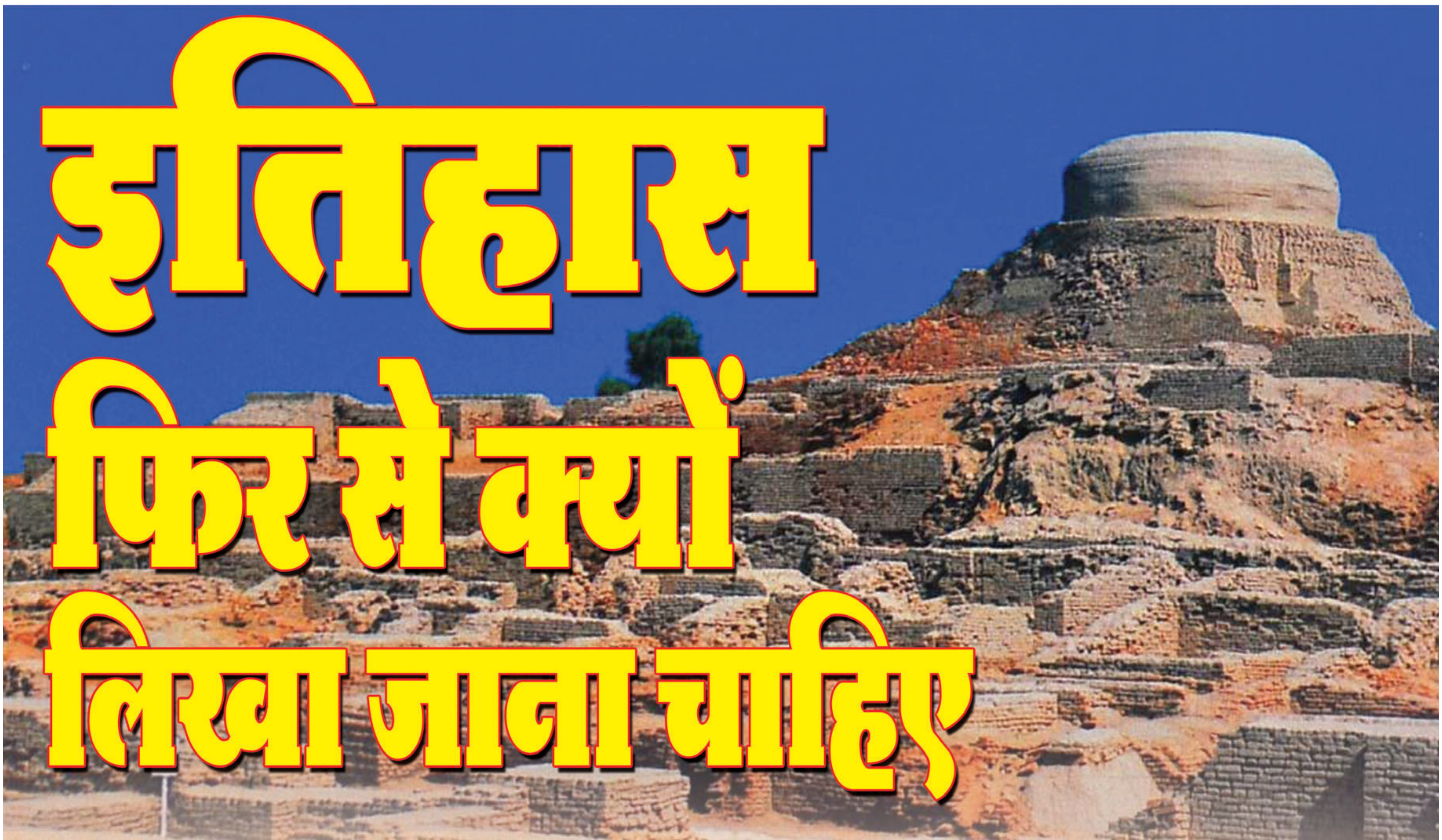

आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की भारी-भरकम जीत के साथ ही यह तय हो गया था कि अब देश में इतिहास को लेकर विवाद उठेगा. भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतिहास को फिर से लिखने की कोशिश करेगी, जिसका विरोध भी होगा. सरकार के अभी सौ दिन पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन यह विवाद भी शुरू हो गया और विरोध का बिगुल भी फूंक दिया गया. जब अटल जी की सरकार बनी थी, तब भी इतिहास को फिर से लिखने की कोशिश की गई थी. सबसे पहले एनसीईआरटी की किताबें बदली गईं. लेकिन तत्कालीन मानव संसाधन मंत्री मुरली मनोहर जोशी ने यह काम ऐसे लोगों के हाथों में दे दिया, जो इतिहास की किताबें लिखने में अपरिपक्व साबित हुए. वे मजाक के पात्र बन गए. जब अटल जी की सरकार चली गई, तो उन किताबों को भी कूड़ेदान में फेंक दिया गया. फिर से मार्क्सवादी इतिहासकारों ने अपना कब्जा जमा लिया. पहला सवाल यह है कि क्या इतिहास को फिर से लिखना उचित है? दूसरा सवाल यह है कि देश के इतिहास का आधार और औचित्य क्या होना चाहिए? तीसरा सवाल यह कि पुनर्लेखन के नाम पर मिथकों को सच बताना क्या इतिहास है?

मनीष कुमार

भारत दुनिया का शायद अकेला ऐसा देश होगा, जहां के आधिकारिक इतिहास की शुरुआत में ही यह बताया जाता है कि भारत में रहने वाले लोग यहां के मूल निवासी नहीं हैं. भारत में रहने वाले अधिकांश लोग भारत के हैं ही नहीं. ये सब विदेश से आए हैं. इतिहासकारों ने बताया कि हम आर्य हैं. हम बाहर से आए हैं. कहां से आए? इसका कोई सटीक जवाब नहीं है. फिर भी बाहर से आए. आर्य कहां से आए, इसका जवाब ढूंढने के लिए कोई इतिहास के पन्नों को पलटे, तो पता चलेगा कि कोई सेंट्रल एशिया कहता है, तो कोई साइबेरिया, तो कोई मंगोलिया, तो कोई ट्रांस कोकेशिया, तो कुछ ने आर्यों को स्कैंडेनेविया का बताया. आर्य धरती के किस हिस्से के मूल निवासी थे, यह इतिहासकारों के लिए आज भी मिथक है. मतलब यह कि किसी के पास आर्यों का सुबूत नहीं है, फिर भी साइबेरिया से लेकर स्कैंडेनेविया तक, हर कोई अपने-अपने हिसाब से आर्यों का पता बता देता है. भारत में आर्य अगर बाहर से आए, तो कहां से आए और कब आए, यह एक महत्वपूर्ण सवाल है. यह भारत के लोगों की पहचान का सवाल है. विश्वविद्यालयों में बैठे बड़े-बड़े इतिहासकारों को इन सवालों का जवाब देना है. सवाल पूछने वाले की मंशा पर सवाल उठाकर इतिहास के मूल प्रश्नों पर पर्दा नहीं डाला जा सकता है.

भारत की सरकारी किताबों में आर्यों के आगमन को आर्यन इन्वेजन थ्योरी कहा जाता है (देखिए बाक्स-1). इन किताबों में आर्यों को घुमंतू या कबीलाई बताया जाता है. इनके पास रथ था. यह बताया गया कि आर्य अपने साथ वेद भी साथ लेकर आए थे. उनके पास अपनी भाषा थी, स्क्रिप्ट थी. मतलब यह कि वे पढ़े-लिखे खानाबदोश थे. यह दुनिया का सबसे अनोखा उदाहरण है. यह इतिहास अंग्रेजों ने लिखा था. वर्ष 1866 में भारत में आर्यों की कहानी मैक्समूलर ने गढ़ी थी. इस दौरान आर्यों को एक नस्ल बताया गया. मैक्स मूलर जर्मनी के रहने वाले थे. उन्हें उस जमाने में दस हज़ार डॉलर की पगार पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने वेदों को समझने और उनका अनुवाद करने के लिए रखा था. अंग्रेज भारत में अपना शासन चलाना चाहते थे, लेकिन यहां के समाज के बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी. इसी योजना के तहत लॉर्ड मैकॉले ने मैक्स मूलर को यह काम दिया था. यह लॉर्ड मैकॉले वही हैं, जिन्होंने भारत में एक ऐसे वर्ग को तैयार करने का बीड़ा उठाया था, जो अंग्रेजों और उनके द्वारा शासित समाज यानी भारत के लोगों के बीच संवाद स्थापित कर सकें. इतना ही नहीं, मैकॉले कहते हैं कि यह वर्ग ऐसा होगा, जो रंग और खून से तो भारतीय होगा, लेकिन आचार-विचार, नैतिकता और बुद्धि से अंग्रेज होगा. इसी एजेंडे को पूरा करने के लिए उन्होंने भारत में शिक्षा नीति लागू की, भारत के धार्मिक ग्रंथों का विश्लेषण कराया और सरकारी इतिहास लिखने की शुरुआत की. आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भारत के शासक वर्ग ने लॉर्ड मैकॉले के सपने को साकार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी. इतिहासकारों ने भी इसी प्रवृत्ति का परिचय दिया.

अंग्रेजों की एक आदत अच्छी है. वे दस्तावेज़ों को संभाल कर रखते हैं. यही वजह है कि वेदों को समझने और उनके अनुवाद के पीछे की कहानी की सच्चाई का पता चल जाता है. मैक्स मूलर ने वेदों के अध्ययन और अनुवाद के बाद एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने साफ़-साफ़ लिखा कि भारत के धर्म को अभिशप्त करने की प्रक्रिया पूरी हो गई है और अगर अब ईसाई मिशनरी अपना काम नहीं करते हैं, तो इसमें किसका दोष है. मैक्स मूलर ने ही भारत में आर्यन इन्वेजन थ्योरी को लागू करने का काम किया था, लेकिन इस थ्योरी

(शेष पृष्ठ 2 पर)

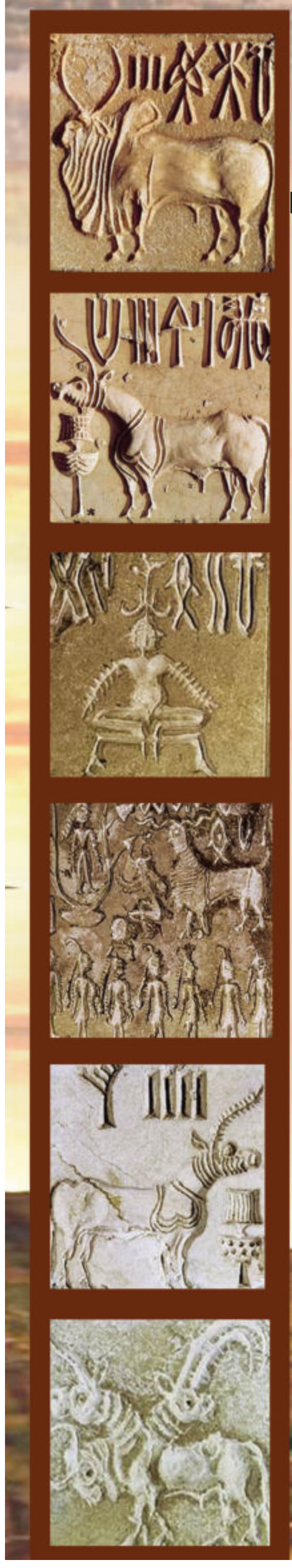

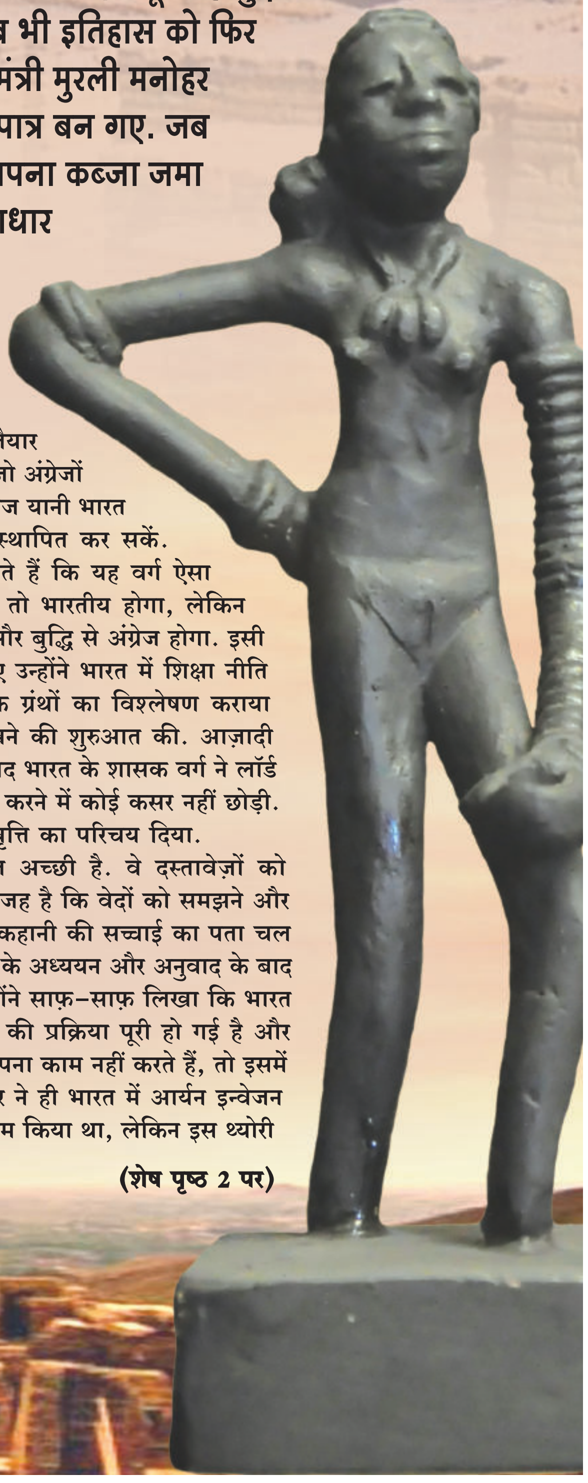

आर्यन इन्वेजन थ्योरी का सच
पृष्ठ 2 पर

आधुनिक इतिहास का कांग्रेसीकरण
पृष्ठ 2 पर

वामपंथ बनाम दक्षिणपंथ
पृष्ठ 2 पर

अनगिनत फाइलें खुलवाने वाले की फाइल बंद 03

जोड़-तोड़ और गठजोड़ का नया दौर 05

हाशिमपुरा नरसंहार सुनवाई जारी है... 06

साई की महिमा 12

इतिहास फिर से क्यों लिखा जाना चाहिए

पृष्ठ एक का शेष

को सबसे बड़ी चुनौती 1921 में मिली. अचानक से सिंधु नदी के किनारे एक सभ्यता के निशान मिल गए. कोई एक जगह होती, तो और बात थी. यहां कई सारी जगहों पर सभ्यता के निशान मिलने लगे. इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाने लगा. यहां की खुदाई से पता चला कि सिंधु नदी के किनारे कई शहर दबे पड़े हैं. इन शहरों में सड़कें थीं, हर जगह और घरों से नालियां निकल रही थीं. पूरे शहर में एक सुनियोजित ड्रेनेज सिस्टम था. बाज़ार के लिए अलग जगह थी. रिहाइशी इलाक़ा अलग था. इन शहरों में स्वीमिंग पूल थे, जिनका डिजाइन भी 21वीं सदी के बेहतरीन स्वीमिंग पूल्स की तरह था. अनाज रखने के लिए गोदाम थे. नदियों के किनारे नौकाओं के लिए बंदरगाह बना हुआ था. जब इन शहरों की उम्र का अनुमान लगाया गया, तो पता चला कि यह दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता है. यह आर्यों के आगमन के पहले से है. अब सवाल यह उठ खड़ा हुआ है कि जब आर्य बाहर से आए थे, तो यहां कौन रहते थे. सिंधु घाटी सभ्यता के शहर सिर्फ़ ज़मीन में धंसे हुए शहर नहीं थे, बल्कि इतिहास के सुबूतों के भंडार थे. अंग्रेज इतिहासकारों ने इतिहास के इन सुबूतों को दरकिनार कर दिया और अपनी आर्यों की थ्योरी पर डटे रहे. होना तो यह चाहिए था कि सिंधु घाटी सभ्यता से मिली नई जानकारी की रौशनी में इतिहास को फिर से लिखा जाता, लेकिन अंग्रेजी इतिहासकारों ने सिंधु घाटी सभ्यता का इस्तेमाल आर्यन इन्वेजन थ्योरी को सही साबित करने में किया.

यह इतिहास के साथ सबसे बड़ा धोखा था, लेकिन किसी ने सवाल नहीं उठाया. उन्होंने लिख दिया कि आर्य बाहर से सिर्फ़ आए ही नहीं, बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश भी किया. भारत के मार्क्सवादी इतिहासकारों की सबसे बड़ी चूक यही है कि किसी ने आर्यन इन्वेजन थ्योरी को नए प्रमाणों की रौशनी में नहीं परखा. इस भ्रामक थ्योरी पर सवाल खड़ा नहीं किया. अंग्रेजों ने जो लिख दिया, उसे सत्य मानकर बैठ गए. आज़ादी के बाद भी इतिहासकारों ने इसे बदलने की कोशिश नहीं की. इतिहास में नए तथ्यों या प्रमाणों के आधार पर बदलाव नहीं किया गया, तो कुछ सवाल उठने लाजिमी हैं. यह कैसे संभव है कि खानाबदोश आर्यों के पास रहने के लिए अपना घर न हो, लेकिन वेद जैसा ग्रंथ हो. अपनी भाषा हो और अपनी स्क्रिप्ट भी. और, जो लोग सुनियोजित शहरों में रह रहे थे, जो स्वीमिंग पूल में नहाते थे, अपना अनाज गोदामों में रखते थे, जो व्यापार करते थे, उनके पास न तो कोई भाषा थी, न स्क्रिप्ट थी और न कोई धर्म ग्रंथ था. और वे इतने कायर और कमज़ोर थे कि खानाबदोश लोगों ने उन्हें उनके शहर से मार भगाया. भारतीय इतिहासकारों ने इन्हीं अंग्रेजों के लिखे इतिहास पर आर्यों और द्रविड़ों का भेद किया. बताया कि सिंधु घाटी में रहने वाले लोग द्रविड़ थे, जो यहां से पलायन कर दक्षिण भारत चले गए. अब यह सवाल भी उठता है कि सिंधु घाटी से जब वे पलायन कर दक्षिण भारत पहुंच गए, तो क्या उनकी बुद्धि और ज्ञान सब ख़त्म हो गया. वे शहर बनाना भूल गए, स्वीमिंग पूल बनाना भूल गए, नालियां बनाना भूल गए. और, बाहर से आने वाले आर्य, जो मूल रूप से खानाबदोश थे, कबीलाई थे, वे वेदों का निर्माण कर रहे थे. दरअसल, वामपंथी इतिहासकारों ने देश के इतिहास को मजाक बना दिया.

भारत का प्राचीन इतिहास विवादों से घिरा है. इस विवाद की जड़ में इतिहास लेखन प्रणाली है. भारत का इतिहास मूल रूप से भाषाई अध्ययन पर लिखा गया है. भारत जैसे देश में जहां पुरातात्विक अवशेषों और स्थलों का भंडार है, वहां के इतिहास लेखन में पुरातत्व को नज़रअंदाज़ किया जाए, यह उचित नहीं है. दरअसल, यह राजनीति का हिस्सा है. देश की सभी इतिहास लेखन संस्थाओं, विश्वविद्यालयों और अनुसंधानिक संस्थाओं पर वामपंथी इतिहासकारों का क़ब्ज़ा है. एक सिर्फ़ पुरातत्व विभाग है, जहां वामपंथियों का क़ब्ज़ा नहीं हो सका है. यही वजह है कि भारत के नामी-गिरामी इतिहासकार पुरातात्विक सुबूतों को सुबूत नहीं मानते, अनर्गल दलील देकर उन्हें दरकिनार कर देते हैं. यही वजह है कि प्राचीन भारत का इतिहास आज भी वही है, जो अंग्रेजों द्वारा लिखा गया था. कुछ सतही फेरबदल ज़रूर किए गए हैं, लेकिन उसका चरित्र आज भी मैकॉले द्वारा स्थापित मापदंड पर कायम है. जिसका सार यह है कि भारत में जो कुछ प्राचीन है, वह बुरा है, असभ्य है और शोषक है. यह इतिहास लिखे 150 साल हो गए हैं. इस दौरान विज्ञान का विकास हुआ है, नई खोजें हुई हैं. ऐतिहासिक प्रमाणों के परीक्षण के लिए तकनीक मौजूद है. दुनिया भर में बहु-विषयक दृष्टिकोण के साथ इतिहास लेखन का काम हो रहा है, लेकिन भारत के वामपंथी इतिहासकार भाषाई अध्ययन को ही एकमात्र सत्य मानकर इतिहास का गला घोंट रहे हैं. वे रूढ़िवादी बन गए हैं. जो कोई उनके द्वारा लिखे इतिहास पर सवाल उठाता है, उस पर वे एक गैंग की तरह हमलावर हो जाते हैं.

हक़ीक़त यह है कि देश-विदेश के कई पुरातत्वविदों, भौतिकशास्त्रियों, भूगर्भशास्त्रियों, खगोलशास्त्रियों, वैज्ञानिकों, गणितज्ञों और इतिहासकारों के लिए सिंधु घाटी सभ्यता रुचि का विषय बन चुकी है. भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में अनुसंधान हो रहे हैं, किताबें लिखी जा रही हैं. ऐसा इसलिए, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई से मिली जानकारियां हैरान करने वाली और अविश्वसनीय हैं. इतिहास में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए यह आश्चर्य का विषय है कि जब ग्रीस, रोम और एथेंस का नामोंनिशान नहीं था, तब यहां के लोग विश्वस्तरीय शहर बनाने में कैसे कामयाब हो गए, टाउन-प्लानिंग का ज्ञान कहां से आया और उन्होंने स्वीमिंग पूल बनाने की तकनीक कैसे सीखी? अफ़सोस इस बात का है कि भारत के लोग जब अपने ही इतिहास को पढ़ते हैं, तो उन्हें गर्व की अनुभूति नहीं होती है. इसका कारण यह भी है कि देश के महान इतिहासकारों ने इस ढंग से इतिहास लिखा है कि जो एक बार पढ़ ले, तो उसकी इतिहास से रुचि ही ख़त्म हो जाती है. यह भी एक कारण है कि इतिहास को फिर से लिखा जाना चाहिए. वैसे अब तो और भी नए सुबूत आ गए हैं. सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े 700 से ज़्यादा पुरातात्विक स्थलों की खोज हो चुकी है. भारत में राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब आदि राज्यों में नई खोज हो चुकी है. इनकी वैज्ञानिक जांच होनी चाहिए और जो भी वैज्ञानिक तथ्य सामने आते हैं, उन्हें इतिहास की किताबों में शामिल करना चाहिए. फिर से इतिहास लिखने की ज़रूरत पड़े, तो लिखना चाहिए. इतिहास लिखते समय यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि नया इतिहास बहु-विषयक दृष्टिकोण लेखन प्रणाली से लिखा गया इतिहास हो. विज्ञान द्वारा प्रमाणित साक्ष्यों पर आधारित हो. प्राचीन इतिहास को मिथकों और धार्मिक मान्यताओं से दूर रखने की ज़रूरत है.

इतिहास कोई आसमानी किताब नहीं है, जिसे बदला न जा सके. नए साक्ष्य, नई खोज और नई तकनीक की वजह से हर वक़्त हमें भूतकाल के बारे में नई जानकारियां मिलती हैं. विज्ञान और तकनीकी विकास की वजह से कई राज से पर्दा हटाया जा सकता है. इन साक्ष्य, तकनीक और सुबूतों के आधार पर इतिहास को बदलना ही सही इतिहास का सृजन करना है. भारत में आज़ादी के बाद से इतिहास लिखने का काम शुरू हुआ. लेखकों ने कॉपी और पेस्ट करके पुरानी बातों को नए अंदाज और नई दलीलों के साथ परोस दिया. किताबों को ऐसे लिखा गया कि यदि कोई एक बार पढ़ ले, तो फिर उसकी इतिहास के बारे में जानने की इच्छा ही ख़त्म हो जाए. इतिहासकारों ने भूतकाल के बारे में बताने से ज़्यादा छिपाने का काम किया. जो बताया, उसमें भी राजनीति और विचारधारा का घालमेल कर दिया. इतिहास घृणा करने की वस्तु नहीं है. वामपंथी इतिहासकारों का दोष यही है कि उन्होंने इतिहास को ही घृणित बना दिया. भारत एक राष्ट्र नहीं, राज्य नहीं और न ही किसी ऐसे-वैसे भूखंड का नाम है. यह दुनिया की सबसे पुरातन सभ्यता है. यहां हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध और न जाने कितने धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं. इतिहास ऐसा होना चाहिए, जिससे हर भारतवासी को गर्व हो, जिससे आपस में भाईचारा और एकता का संचार हो और जो हमारा हौसला बुलंद कर सके कि हम मानव विकास के मानदंडों पर दुनिया में अग्रणी रहे हैं. एक ऐसा इतिहास लिखा जाना चाहिए, जो मिथकों या धार्मिक कथा-कहानियों पर नहीं, बल्कि सत्य और सुबूतों पर आधारित हो. भारत में इतिहास को फिर से लिखने की ज़रूरत है. इतिहासकारों को नए साक्ष्य, सुबूतों, विज्ञान और तकनीक का इस्तेमाल इतिहास लेखन में करना चाहिए. मनगढ़ंत बातों के लिए इतिहास में कोई जगह नहीं होनी चाहिए. ■

manishbph244@gmail.com

आर्यन इन्वेजन थ्योरी का सच

यह बहुत कम लोग जानते हैं कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी (आर्य आक्रमण सिद्धांत) की उत्पत्ति की जड़ में ईसाई-यहूदी वैचारिक लड़ाई है. आर्यन इन्वेजन थ्योरी की उत्पत्ति 18वीं शताब्दी में यूरोप, ख़ासकर जर्मनी में हुई. उस वक्त के इतिहासकारों एवं दार्शनिकों ने यूरोपीय सभ्यता को जुडाइज्म (यहूदी) से मुक्त करने के लिए यह थ्योरी प्रचारित की. कांट एवं हरडर जैसे दार्शनिकों ने भारत और चीन के मिथकों तथा दर्शन को यूरोपीय सभ्यता से जोड़ने की कोशिश की. वे नहीं चाहते थे कि यूरोपीय सभ्यता को जुडाइज्म से जोड़कर देखा जाए. इसलिए उन्होंने यह दलील दी कि यूरोप में जो लोग हैं, वे यहूदी नहीं, बल्कि चीन और भारत से आए हैं. उनका नाम उन्होंने आर्य रखा. समझने वाली बात यह है कि चीन और भारत के सभी लोग आर्य नहीं थे. उनके मुताबिक़ , एशिया के पहाड़ों में रहने वाले सफेद चमड़ी वाले कबीलाई लोग आर्य थे, जो यूरोप में आकर बसे और ईसाई धर्म अपनाया. यूरोप में आर्य को एक अलग रेस माना जाने लगा. यह एक सर्वमान्य थ्योरी मानी जाने लगी. आर्यन इन्वेजन थ्योरी की उत्पत्ति मूल रूप से यूरोप के लिए की गई थी. जब अंग्रेजों ने भारत का इतिहास समझना शुरू किया, तो आश्चर्य की बात यह है कि उन्होंने इस थ्योरी को भारत पर भी लागू कर दिया. 1866 से आर्यन इन्वेजन थ्योरी ऑफ इंडिया को भारत के इतिहास का हिस्सा बना दिया गया. बताया गया कि भारत के श्वेत रंग के, उच्च जाति के शासक वर्ग और यूरोपीय उपनिवेशक एक ही प्रजाति के हैं. यह थ्योरी अंग्रेजों के काम भी आई. अंग्रेज बाहरी नहीं है और उनका भारत पर शासन करना उतना ही अधिकृत है, जितना यहां के राजाओं का. अंग्रेजों को भारत में शासन करने के लिए इन हथकंडों की ज़रूरत थी. लेकिन यह बात समझ में नहीं आती कि आज़ादी के बाद भी वामपंथी इतिहासकारों ने इस थ्योरी को जड़-मूल से ख़त्म क्यों नहीं किया? जबकि हमें यह पता है कि इस मनगढ़ंत थ्योरी की वजह से हिटलर जैसे तानाशाह पैदा हुए. वह भी तब, जब यूरोप में विज्ञान के विकास के साथ-साथ रेस थ्योरी को अविश्वसनीय और ग़ैर-वैज्ञानिक घोषित कर दिया गया. पिछले 70 सालों से आर्यन रेस पर कई अनुसंधान हुए. अलग-अलग देशों ने इसमें हिस्सा लिया है, अलग-अलग क्षेत्र के वैज्ञानिकों ने अपना योगदान दिया है. सबने एक स्वर में आर्यन के एक रेस होने की बात को मिथक और झूठा करार दिया है. ये सिर्फ़ वामपंथी इतिहासकार हैं, जो अभी तक इस रेस थ्योरी को पकड़ कर बैठे हैं. 10 दिसंबर, 2011 को एक ख़बर आई कि सेलुलर मोलिकुलर बायोलॉजी के वैज्ञानिकों ने कई महाद्वीपों के लोगों पर एक रिसर्च किया. इस रिसर्च में कई देशों के वैज्ञानिक शामिल थे. यह रिसर्च 3 सालों तक किया गया और लोगों के डीएनए की सैंपलिंग पर किया गया. इस रिसर्च से पता चला कि भारत में रहने वाले चाहे वे दक्षिण भारत के हों या उत्तर भारत के, उनके डीएनए की संरचना एक जैसी है. इसमें बाहर से आई किसी दूसरी प्रजाति या रेस का कोई मिश्रण नहीं है और यह दावे के साथ कहा जा सकता है कि पिछले 60 हज़ार सालों से भारत में कोई भी बाहरी जीन नहीं है. इस रिसर्च की रिपोर्ट में कहा गया है कि डीएनए सैंपलिंग के जरिये यह बिना किसी शक के दावा किया जा सकता है कि आर्यों के आक्रमण की कहानी एक मिथक है. इस रिसर्च की रिपोर्ट को अमेरिकन जनरल ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स में 9 दिसंबर, 2011 को प्रकाशित किया गया. यह एक प्रामाणिक रिसर्च है. इसमें विज्ञान की सबसे उच्च कोटि की तकनीकों का इस्तेमाल हुआ है. कई देशों के वैज्ञानिक इसमें शामिल थे. यह रिपोर्ट आए तीन साल होने वाले हैं. देश के इतिहासकार क्यों चुप हैं? हक़ीक़त यह है कि भारत का इतिहास राजनीति से ग्रसित है. इतिहास की किताबों ने सच बताने से ज़्यादा सच को छिपाने का काम किया है. ■

आधुनिक इतिहास का कांग्रेसीकरण

आधुनिक भारत का इतिहास सन् 1857 की क्रांति से लेकर 1947 तक माना जाता है. प्राचीन इतिहास जहां भारत की पहचान के लिए ज़रूरी है, उसी तरह आधुनिक इतिहास भारत की एकता, अखंडता और प्रजातंत्र को सींचने के लिए महत्वपूर्ण है. अफ़सोस इस बात का है कि आधिकारिक इतिहासकारों ने इसमें वामपंथ और कांग्रेसी विचारधारा का ऐसा घालमेल किया कि कई लोग मुख्य धारा से अलग-थलग हो गए. आधुनिक भारत का पूरा इतिहास गांधी, नेहरू, कांग्रेस और वामपंथी संगठनों तक सीमित कर दिया गया. सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म के चश्मे से लिखा गया वामपंथी इतिहास पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है. इंस्टीट्यूट ऑफ आब्जेक्टिव स्टडीज ने एक किताब प्रकाशित की, जिसमें आज़ादी की लड़ाई में शामिल कई मुस्लिम नेताओं और क्रांतिकारियों के बारे में जानकारी दी गई. ये वे नाम हैं, जिनका मुख्य धारा के इतिहास में न तो कोई जिक्र है और न ही उनके योगदान की चर्चा है. मुस्लिम लीग में शामिल मुस्लिम नेताओं को आधुनिक भारत के इतिहास से निकाल कर बाहर फेंक दिया गया. इतना ही नहीं, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक के योगदान को भी भुला दिया गया, जबकि वे कांग्रेस के नेता भी रहे. दरअसल, वामपंथी लेखन प्रणाली ने आधुनिक भारत का इतिहास सेकुलर-कम्युनल चश्मे से लिखा. इसमें मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा को कम्युनल संगठन बताकर उनके योगदान को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया गया. जबकि हक़ीक़त यह है कि मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा काफी समय तक कांग्रेस का हिस्सा रही. कांग्रेस उस वक्त कोई संगठन नहीं, बल्कि एक आंदोलन था, जिसमें कई संगठन शामिल थे. मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा के ज़मीनी कार्यकर्ता और स्थानीय नेता आज़ादी के आंदोलन में किसी से पीछे नहीं थे. वैसे भी सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म के चश्मे से लिखा गया वर्तमान इतिहास न सिर्फ़ अधूरा है, बल्कि विरोधाभासों से भरा पड़ा है. इसके अलावा इन किताबों को पढ़कर लगता है कि पूरे के पूरे नॉर्थ-ईस्ट की स्वतंत्रता संग्राम में कोई हिस्सेदारी ही नहीं थी. नॉर्थ-ईस्ट के वे कौन लोग थे, जिन्होंने आज़ादी के लिए जानें दीं, आंदोलन किया और अंग्रेजों के डंडे खाए, यह वर्तमान इतिहास में नहीं है. कांग्रेस सरकारों द्वारा चयनित वामपंथी इतिहासकारों ने इतिहास को राजनीति का अखाड़ा बना दिया. उन्होंने इतिहास के नाम पर कुछ झूठ कहा, कुछ सच छिपाए और कई मनगढ़ंत कहानियां गढ़ दीं. ■

वामपंथ बनाम दक्षिणपंथ

यह देश का दुर्भाग्य होगा कि पुनर्लेखन के नाम पर मिथकों और इतिहास का घालमेल कर दिया जाए. आज के युवाओं को यह स्वीकार नहीं होगा कि हमारी किताबों में यह लिखा हो कि स्टेम सेल तकनीक का विकास महाभारत काल में हुआ था और मोटरकार का आविष्कार वैदिक काल में ही हो गया था. 21वीं सदी के भारत को ऐसे इतिहास की ज़रूरत नहीं है, जिसमें यह लिखा जाए कि भारत में महाभारत काल में इस तकनीक का उपयोग होता था. कुंती का बेटा सूर्य के समान तेजस्वी था. गांधारी जब दो साल तक गर्भधारण नहीं कर पा रही थीं, तो उन्होंने गर्भपात कराया. उस दौरान उनके गर्भाशय से बड़ी मात्रा में मांस निकला. ऋषि द्वैपायन व्यास ने उस मांस में औषधियां मिलाकर उसे एक ठंडे टैंक में रख दिया. बाद में उन्होंने उसके 100 टुकड़े किए और हर टुकड़े को घी से भरे 100 अलग-अलग टैंकों में दो साल तक रखा. दो साल के बाद उसी से 100 कौरवों का जन्म हुआ. ऐसी कहानियां कथावाचकों के लिए तो ठीक हैं, लेकिन इतिहास की किताबों में इनकी कोई जगह नहीं है. भारत का प्राचीन इतिहास वैसे ही गौरवशाली है. जो सुबूत उपलब्ध हैं, वही हमें दुनिया की सबसे पुरातन और अग्रणी सभ्यता साबित करने के लिए काफी हैं. इसके लिए यह ज़रूरी नहीं है कि इतिहास की किताबों में यह लिखा जाए कि वैदिक काल में भी मोटरकारें थीं, जिन्हें अनश्व रथ कहा जाता था. सामान्य तौर पर रथ को घोड़े खींचते हैं, लेकिन अनश्व रथ बगैर घोड़ों के दौड़ता था. इसे यंत्र रथ भी कहा जाता था और यही आज की मोटरकार है. या फिर हम पुष्पक विमान के बारे में यह बताएं कि उस जमाने में ही भारत में हवाई जहाज का आविष्कार हो चुका था.

भारत का इतिहास वैसे ही गौरवशाली है. भारत का प्राचीन काल हर दृष्टि से दुनिया में अग्रणी रहा है. ज़रूरत इस बात की है कि इतिहास को प्रामाणिक सुबूतों के साथ लिखा जाए, ताकि उस पर कोई उंगली न उठा सके. अगर संघ और उससे जुड़े कुछ लोग पिछली बार की तरह इतिहास के नाम पर मिथ्या को सच बताने लगेंगे, तो ऐसे इतिहास की वजह से भारत पूरे विश्व में उपहास का पात्र बन जाएगा. ■

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 06 अंक 26
दिल्ली, 01 सितंबर-07 सितंबर 2014
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना-800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.

संपादकीय	0120-6451999
	6450888
विज्ञापन व प्रसार	022-42296060
	+91-8451050786
	+91-9266627379
फैक्स न.	0120-2544378

पृष्ठ-16+4 (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड) हर शुक्रवार को प्रकाशित

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

पूरे देश में आज लगभग 3.2 करोड़ मुकदमे लंबित हैं. देश में 1000 फास्ट ट्रैक कोर्ट काम कर रही हैं, जिन्होंने पिछले ग्यारह सालों में लगभग 32 लाख मुकदमों का निस्तारण किया. आंकड़ों के अनुसार, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों एवं अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों के तक़रीबन 4,655 पद रिक्त पड़े हैं, जिसकी वजह से लंबित मामलों की सुनवाई में देरी हो रही है.

सतीश शेट्टी हत्याकांड

अनगिनत फाइलें खुलवाने वाले की फाइल बंद

सतीश शेट्टी का नाम आपको याद है? अगर नहीं याद है, तो इसमें आपकी गलती भी नहीं है. इतने बड़े देश में, जहां रोज सौ ख़बरें पैदा होती हैं और उतनी ही दम तोड़ देती हैं, वहां चार साल पहले सच के एक सिपाही की हत्या की घटना भला कौन याद रखना चाहेगा और क्यों? बहरहाल, चार साल पहले हुई इस हत्या की सीबीआई जांच चल रही थी, लेकिन एक भी गवाह और पर्याप्त सुबूत न मिलने की बात कहकर सीबीआई ने इस मामले की क्लोजर रिपोर्ट अदालत में दाखिल कर दी है यानी नो वन किल्ड सतीश (सतीश को किसी ने नहीं मारा).

शशि शेखर

बीते 11 अगस्त को देश के बहुचर्चित आरटीआई कार्यकर्ता सतीश शेट्टी हत्याकांड की जांच कर रही सीबीआई ने वडगांव-मावल कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी. यानी इस क्लोजर रिपोर्ट के दाखिल होते ही एक तरह से सीबीआई ने उन लोगों को क्लीन चिट दे दी है, जिन पर इस हत्याकांड में शामिल होने का शक किया जा रहा था. सीबीआई ने इस मामले में किसी को भी गिरप्तार नहीं किया. सतीश शेट्टी की हत्या 13 जनवरी, 2010 को हुई थी. इस हत्या के पीछे भू-माफियाओं का हाथ होने की आशंका जताई गई थी.

दरअसल, पुणे के सतीश शेट्टी जब 13 जनवरी, 2010 को सुबह अपने घर से बाहर निकले, तो उन पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया गया. 38 वर्षीय सतीश पुणे से 40 किलोमीटर दूर तालेगांव में रहते थे. सूचना के अधिकार के तहत सतीश कई मामलों का पर्दाफाश कर चुके थे. सतीश पुणे की भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति के संयोजक भी थे. आरटीआई का इस्तेमाल करके सतीश शेट्टी ने महाराष्ट्र में कई ज़मीन घोटालों और मुंबई-पुणे एक्सप्रेस-वे में हुए घोटाले को उजागर किया था. इसी वजह से सतीश भू-माफियाओं के निशाने पर आ गए थे. आरटीआई की सहायता से सतीश ने अवैध बंगले के निर्माण और मिट्टी के तेल एवं राशन की कालाबाज़ारी के विरोध में भी आवाज़ उठाई थी. बॉम्बे हाईकोर्ट ने सतीश शेट्टी हत्याकांड का स्वत: संज्ञान लेकर सीबीआई को इस मामले की जांच करने का आदेश दिया था. इससे पहले पुणे पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी. 8 अगस्त, 2014 को भी हाईकोर्ट ने सीबीआई को उन ज़मीन घोटालों की फाइलें खोलने के लिए कहा था, जिनमें सतीश शेट्टी ने एफआईआर दर्ज कराई थी. खुद सीबीआई ने भी माना था कि उक्त मामलों का सतीश की हत्या से संबंध हो सकता है, इसलिए उनकी जांच ज़रूरी है. सीबीआई चार साल से इस मामले की जांच कर रही थी. तक़रीबन वह मामले की तह तक पहुंच भी चुकी थी. सीबीआई ने 10,000 पृष्ठों की जांच रिपोर्ट भी बना ली थी.

8 अगस्त, 2014 को अदालत ने सीबीआई को उक्त मामले खोलने के आदेश दिए और कहा कि चार सप्ताह के भीतर सीबीआई इस पर अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश करे. घोटालों की रिपोर्ट सौंपने की बजाय सीबीआई ने तीन दिनों बाद ही यानी 11 अगस्त को वडगांव-मावल कोर्ट में सतीश शेट्टी हत्याकांड जांच की क्लोजर रिपोर्ट दे दी. आधार यह था कि किसी भी अभियुक्त के ख़िलाफ़ कोई सुबूत नहीं मिला. सवाल है कि 8 अगस्त से लेकर 11 अगस्त तक यानी 3 दिनों के भीतर ऐसा क्या हो गया, जिससे सीबीआई को पीछे हटना पड़ा. सीबीआई के प्रवक्ता का कहना है कि अभियुक्तों के ख़िलाफ़ अभियोजन चलाने के लिए पर्याप्त सुबूत नहीं थे, इसलिए क्लोजर रिपोर्ट लगा दी गई.

ग़ौरतलब है कि आरटीआई कार्यकर्ता सतीश शेट्टी ने पुणे-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर ज़मीन हड़पने के

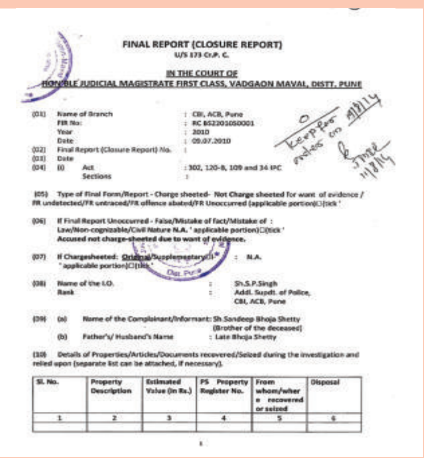
FINAL REPORT (CLOSURE REPORT)
U/S 173 Cr.P.C.
IN THE COURT OF
HON'BLE JUDICIAL MAGISTRATE FIRST CLASS, VADGAON MAVAL, DISTT. PUNE

(01) Name of Branch : CBI, ACB, Pune
FIR No: : RC BS2201005000[illegible]
Year : 2010
Date : 09.07.2010
(02) Final Report (Closure Report) No. :
(03) Date
(04) (i) Act : 302, 120-B, 109 and 34 IPC
Sections :
(05) Type of Final Form/Report - Charge sheeted- Not Charge sheeted for want of evidence / FR undetected/FR untraced/FR offence abated/FR Unoccurred (applicable portion)☐(tick')
(06) If Final Report Unoccurred - False/Mistake of fact/Mistake of Law/Non-cognizable/Civil Nature N.A. ' applicable portion)☐(tick' :
Accused not charge-sheeted due to want of evidence.
(07) If Chargesheeted: Original/Supplementary☐' 'applicable portion)☐(tick' : N.A.
(08) Name of the I.O. : Sh.S.P.Singh
Rank : Addl. Supdt. of Police, CBI, ACB, Pune
(09) (a) Name of the Complainant/Informant: Sh Sandeep Bhoja Shetty (Brother of the deceased)
(b) Father's/ Husband's Name : Late Bhoja Shetty
(10) Details of Properties/Articles/Documents recovered/Seized during the investigation and relied upon (separate list can be attached, if necessary).

Sl. No.	Property Description	Estimated Value (in Rs.)	PS Property Register No.	From whom/where recovered or seized	Disposal
1	2	3	4	5	6

1

मामले में जिन 13 लोगों के ख़िलाफ़ 2009 में तालेगांव पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई थी, उसमें आइडियल रोड बिल्डर्स (आईआरबी) के मुखिया वीरेंद्र मैसकर का भी नाम शामिल था, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके राजनीतिक गलियारों में ऊंचे संबंध हैं. ध्यान देने की बात यह है कि सतीश अक्टूबर 2009 में एफआईआर दर्ज कराते हैं और फरवरी 2010 में उनकी हत्या हो जाती है. अक्टूबर 2012 में सीबीआई ने आईआरबी के कार्यालय पर छापे भी मारे थे. इस मामले में अभियुक्तों के पालीग्राफ टेस्ट भी हुए थे, लेकिन अपनी क्लोजर रिपोर्ट में सीबीआई ने यह कहा है कि पालीग्राफ टेस्ट को ठोस सुबूत नहीं बनाया जा सकता.

बहरहाल, सीबीआई द्वारा इस मामले को बंद करने के संबंध में सरकार की तरफ़ से कुछ नहीं कहा गया है. सांसद राजू शेट्टी ने ज़रूर इस मसले पर आवाज़ उठाई है. राजू शेट्टी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर आरटीआई कार्यकर्ता सतीश शेट्टी की हत्या की जांच फिर से सीबीआई द्वारा शुरू कराने की मांग की है. राजू शेट्टी ने सीबीआई के निर्णय को चकित करने वाला निर्णय बताया है. उन्होंने कहा कि सीबीआई ने इसके पूर्व कई पेचीदा मामलों को उजागर किया है. अगर यह जांच बंद हो गई, तो समाज में गलत संदेश जाएगा. जाहिर है, सतीश शेट्टी ने सड़क निर्माण परियोजना के घोटाले में अहम खुलासा किया था. इस घोटाले में कुछ बड़े लोगों के नाम सामने आ सकते थे, लेकिन अब सीबीआई द्वारा जांच बंद होने से भ्रष्टाचार के कुछ अहम मामले शायद कभी जनता के सामने नहीं आ पाएंगे.

सवाल है कि जिस व्यवस्था के ख़िलाफ़ कोई नागरिक एक सूचना निकालता है और उसे सार्वजनिक करता है, वही व्यवस्था क्यों और कितनी सुरक्षा उस नागरिक को देना चाहेगी? निष्पक्ष जांच की बात तो बहुत दूर की है. यह सच्चाई कौन नहीं जानता कि किसी भी बड़े घोटाले में कौन-कौन से और किस तरह के लोग शामिल होते हैं. भारत में जितने भी बड़े घोटाले सामने आए हैं, उनमें किसी नेता या अफसर की संलिप्तता ज़रूर होती है. ऐसे में अगर कोई आम आदमी किसी घोटाले का पर्दाफाश करता है, तो सोचिए क्या होगा. ■

shashishekhar@chauthiduniya.com

देर से मिला इंसाफ़ नाइंसाफ़ी है

एक वरिष्ठ वकील साहब का पुत्र क़ानून की पढ़ाई ख़त्म करके पिता के साथ वकालत करने लगा. बड़े वकील साहब शहर के एक बड़े सेठ जी का दीवानी मुकदमा कई सालों से लड़ रहे थे. सालों से निर्णय की स्थिति में आने के बाद भी उस पर अंतिम फ़ैसला नहीं हो सका था. तारीख़ पर तारीख़ बदस्तूर जारी थी. सेठ जी का मुनीम हर तारीख़ पर एक तयशुदा रकम बड़े वकील साहब के हवाले कर जाता. पुत्र वकील ने एक दिन उस मुकदमे का अवलोकन किया और अपने पिता से कहा कि वह इस मुकदमे की पैरवी करना चाहता है, तो पिता ने उसे इसकी अनुमति दे दी. पुत्र ने मुकदमे के दौरान जमकर बहस की और कहा कि इसका फ़ैसला तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था. जज साहब ने कहा कि आपकी बात ठीक है, लेकिन क्या आप अपने पिताजी से पूछकर आए हैं? पुत्र ने कहा, हां, उनकी अनुमति के बाद ही मैं यहां आया हूं. सालों पुराने इस मुकदमे पर आख़िरकार अदालत ने सेठ जी के पक्ष में फ़ैसला दे दिया. बेटा अपना पहला मुकदमा जीतकर पिता के पास पहुंचा और बोला, मैंने सेठ जी का मुकदमा जीत लिया. यह सुनकर पिता ने गुस्से में कहा, तुमने यह क्या किया? जिस मुकदमे की वजह से तुम वकील बन सके, तुमने वह मुकदमा ही ख़त्म कर दिया. देश में देरी से न्याय मिलने की एक बड़ी वजह यह भी है.

नवीन चौहान

भारत में देर से न्याय मिलने की कहानियां बहुत पुरानी और बड़ी संख्या में हैं, लेकिन इस बार तो देरी से फ़ैसला सुनाने के मामले में सारी हदें पार हो गईं. सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश को ही हाईकोर्ट से न्याय मिलने में 39 साल लग गए. आलम यह है कि फ़ैसला सुनने के लिए वह इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं. वाकया वर्ष 1975 का है, जब सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस ए एन राय अपनी कार में बेटे अंजोय नाथ राय, कर्मचारी जयनंद और कार चालक इंदर सिंह के साथ कोर्ट से अपने घर की ओर जा रहे थे. जैसे ही वह सुप्रीम कोर्ट के गेट से निकल कर 200 मीटर की दूरी पर पहुंचे, वैसे ही वहां मौजूद तीन युवकों ने उनकी कार पर हैंडग्रेनेड से हमला कर दिया. हालांकि, दोनों ही ग्रेनेड नहीं फटे और कोई भी शख्स हताहत नहीं हुआ. इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी. सीबीआई ने संतोष आनंद, रंजन, सुदेवानंद एवं विक्रम नामक युवकों को गिरफ्तार किया था. विक्रम बाद में सरकारी गवाह बन गया था. इस मामले में निचली अदालत ने अपना फ़ैसला एक साल बाद यानी 1976 में दे दिया था. उस वक्त ए एन राय जीवित थे. निचली अदालत ने अभियुक्तों संतोष आनंद अवधूत, सुदेवानंद अवधूत और रंजन द्विवेदी को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई थी. तीनों अभियुक्तों ने निचली अदालत के निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. 39 साल बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने उस पर अपना फ़ैसला सुनाते हुए दो आरोपियों संतोष आनंद अवधूत एवं सुदेवानंद अवधूत की सजा बरकरार रखी और रंजन द्विवेदी को सुबूतों के अभाव में बरी कर दिया है.

इसी तरह बहुचर्चित सूर्यानेल्ली बलात्कार मामले में केरल हाईकोर्ट ने फ़ैसला देने में 18 साल लगा दिए. घटना के समय पीड़िता नाबालिग थी. उसे आरोपी केरल एवं तमिलनाडु के विभिन्न स्थलों पर ले गए. चालीस दिनों में 3000 किमी की यात्रा के दौरान विभिन्न जगहों पर 40 से ज़्यादा लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर 26 फरवरी, 1996 को उसे मुक्त कर दिया. इस मामले में 36 आरोपी थे. मुकदमे के दौरान पांच आरोपियों की मौत हो गई. इस मामले की नए सिरे से सुनवाई के लिए बनाई गई पीठ ने सात आरोपियों को बरी कर दिया. अदालत ने शेष आरोपियों को पांच से लेकर 13 साल तक की सजा सुनाई और जुर्माना लगाया.

इसी तरह डीटीसी के कंडक्टर रामबीर सिंह 41 सालों से इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं. 41 साल पहले डीटीसी ने चुस्ती की अनोखी मिसाल पेश की थी. आज की तारीख में रामबीर सिंह 70 साल के हो चुके हैं. वाकया 1973 का है. रामबीर सिंह यादव डीटीसी में बस कंडक्टर थे. उनकी बस मायापुरी जा रही थी. उसी दौरान टिकट चेकर स्क्वॉयड आ धमका. टिकट चेकर्स ने पाया कि एक महिला को 10 पैसे का टिकट दिया गया है, जबकि 15 पैसे का टिकट बनना चाहिए था. पांच पैसे के लिए टिकट चेकर्स स्क्वॉयड ने रणवीर सिंह के ख़िलाफ़ डीटीसी के साथ धोखाधड़ी और लापरवाही का मामला बनाया. विभागीय जांच हुई और फ़ैसला रामबीर सिंह के ख़िलाफ़ आया. सरकारी खजाने को पांच पैसे का नुक़सान पहुंचाने के लिए रामबीर सिंह को दोषी ठहराया गया. जांच रिपोर्ट के आधार पर उन्हें 1976 में नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया. रामबीर सिंह ने डीटीसी के इस फ़ैसले को लेबर कोर्ट में चुनौती दी. अदालत ने वर्ष 1982 में रामबीर के पक्ष में फ़ैसला दिया. डीटीसी ने लेबर कोर्ट के फ़ैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी. हाईकोर्ट ने डीटीसी की याचिका अप्रैल 2007 में खारिज कर दी. इसके बाद 2008 में डीटीसी ने हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर कर दी. यह मामला अभी तक विचाराधीन है.

इस साल जुलाई के अंत तक सुप्रीम कोर्ट में 65,762 मुकदमे लंबित हैं. पूरे देश में आज लगभग 3.2 करोड़ मुकदमे लंबित हैं. देश में 1000 फास्ट ट्रैक कोर्ट काम कर रही हैं, जिन्होंने पिछले ग्यारह सालों में लगभग 32 लाख मुकदमों का निस्तारण किया. आंकड़ों के अनुसार, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों एवं अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों के तक़रीबन 4,655 पद रिक्त पड़े हैं, जिसकी वजह से लंबित मामलों की सुनवाई में देरी हो रही है. पिछले दो सालों में सुप्रीम कोर्ट और निचली अदालतों में लंबित मामलों की संख्या में मामूली कमी आई है. कई बार तो सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में जज रह चुके लोगों ने सुनवाई की धीमी गति देखकर कहा कि यदि इसी रफ्तार से अदालतों में काम चलता रहा, तो लंबित मामले निपटाने में तीन-चार सौ साल लग जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी बार-बार दोहराते रहे हैं कि देरी से इंसाफ, नाइंसाफी है.

न्याय मिलने में देरी का कारण केवल जज और सुविधाओं की कमी नहीं है. न्यायाधीशों की नियुक्ति में देरी, जज-वकीलों की साठगांठ और प्रभावशाली लोगों के कारण भी इंसाफ मिलने में देरी होती है. जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने तो अदालतों के जज-अंकल सिंड्रोम से प्रभावित होने की बात आधिकारिक रूप से कही थी. निचली अदालत के वकील भी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट छोड़िए, ग़रीब तो निचली अदालत में भी मुकदमा लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, क्योंकि वह जानता है कि कोर्ट-कचहरी में न जाने कितने दिन लग जाएंगे, इसलिए वह दोहरे नुक़सान से बचना चाहता है. संपत्ति विवाद के मुकदमों का फ़ैसला आने में पीढ़ियां गुजर जाती हैं. यदि कोई व्यक्ति अदालत में मुकदमा लड़ने की हिम्मत कर भी ले, तो सालों तारीख पर तारीख, वकील की फीस के साथ जगह-जगह रिश्वत देने के कारण उसकी हालत खराब हो जाती है. निचली अदालत के बाद लोगों की हिम्मत दम तोड़ देती है. ज़मीन बंटवारे, किरायेदारी और ऐसे ही न जाने कितने मुकदमे लोग सालों से लड़ रहे हैं. वकील अपनी फीस के चक्कर में भी लोगों को चक्कर कटवाते रहते हैं. सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अल्तमश कबीर ने कहा था कि आधारभूत ढांचे की कमी के कारण ही मुकदमों की संख्या बढ़ रही है. जजों की संख्या बढ़ाने के साथ ही अदालतों को सुविधाएं दिलाने की तरफ़ भी उन्होंने सरकार का ध्यान दिलाया था.

जजों एवं सुविधाओं की कमी, ग़रीब आदमी की अदालत से दूर होती पहुंच और इंसाफ में देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की इस तरह की टिप्पणी से आम आदमी में भी निराशा पैदा होती है. बड़े-बड़े वकील अपने मुवक्किल को फ़ायदा पहुंचाने के लिए सुनवाई को लंबे समय तक टलवाते रहते हैं. यह बात अदालत की जानकारी में होने के बावजूद कोई कुछ नहीं कर पाता. सरकार को पुराने मामले वर्गीकृत कर मध्यस्थता के आधार पर ख़त्म कराने के लिए पहल करनी चाहिए. हर मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक आधार पर करके लोगों को राहत देनी चाहिए, जिससे लोगों का विश्वास कम से कम अदालत के प्रति तो बना रहे. वरना सरकारी व्यवस्थाओं का तो भगवान ही मालिक है. ■

navinonline2003@gmail.com

अमर सिंह की पार्टी में वापसी की चर्चा के कारण ही कुछ प्रतिरोधी गतिविधियां भी तेज हो गई हैं. अमर सिंह समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, इन अटकलों को आधार बनाकर पार्टी के कुछ नेता कार्यकर्ताओं में आक्रोश पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं. आजम के बयान को भी इसी परिप्रेक्ष्य में लिया जा रहा है. अभी कुछ ही दिनों पहले पार्टी के प्रदेश महासचिव डॉ. सीपी राय ने कहा, मैं अमर सिंह के पार्टी में शामिल होने के सख्त ख़िलाफ़ हूं.

फिर मिले मुलायम और अमर सिंह

साफ़ हो रहा है वापसी का रास्ता

प्रभात रंजन दीन

राजनीतिक ताप समझें, तो यह स्पष्ट हो रहा है कि अमर सिंह के समाजवादी पार्टी में शरीक होने का रास्ता साफ़ हो रहा है. जनेश्वर मिश्र पार्क के लोकार्पण समारोह में शरीक हुए अमर सिंह का 19 अगस्त को मुलायम से मिलने उनके घर जाना, उस मुलाकात में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का साथ रहना और फिर उनका पार्टी कार्यालय भी जाना अमर सिंह की पार्टी में वापसी का ठोस संदेश दे गया. मुलायम के आवास पर दोनों नेताओं की बीच काफी देर तक बातचीत हुई. मुलायम सिंह से मुलाकात के बाद अमर सिंह ने कहा, मैंने मुलाकात ही तो की है, कोई डाका तो नहीं डाला. इसके लिए इतना हंगामा क्यों बरप रहा है. मेरा मुलायम से पारिवारिक रिश्ता है, इसलिए मिलने गया था. वह जब भी मुझे बुलाएंगे, मैं उनसे मिलने जाऊंगा. मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है. अखिलेश मेरे बेटे जैसे हैं. अमर सिंह ने यह भी कहा, शिवपाल और मुलायम सिंह दोनों मेरे भाई जैसे हैं. आज पहले मैं शिवपाल से मिलने गया और उसके बाद मुलायम सिंह यादव से.

कुछ ही दिनों पहले अमर सिंह ने देहरादून में कहा था कि अगर मुलायम सिंह समाजवादी पार्टी में बुलाएंगे, तो वह वापस आने को तैयार हैं. लेकिन, उनकी वापसी को लेकर बढ़ी गतिविधियों से प्रो. राम गोपाल यादव और आजम खान जैसे वरिष्ठ नेता नाराज़ चल रहे हैं. वे अपनी नाराज़गी खुलेआम व्यक्त भी कर रहे हैं. समाजवादी पार्टी में अमर सिंह आएं न आएं, लेकिन अमर सिंह को लेकर इस राजनीतिक दल में राजनीति अपनी निकृष्टता के स्तर पर उतर आई है. अमर सिंह का समाजवादी पार्टी में प्रवेश सपा के अभिभावक मुलायम सिंह यादव की इच्छा पर निर्भर करता है, यह कहने के बावजूद सपा के नेता अमर सिंह के पार्टी में आने पर यह कर देंगे, वह कर देंगे की धमकी देने से बाज नहीं आ रहे हैं. स्पष्ट है कि सपा के कुछ शीर्ष नेताओं में भीषण अनुशासनहीनता है और उन पर कोई लगाम नहीं है. यह स्थिति पार्टी को नुक़सान पहुंचा रही है. ऐसे समय में, जब प्रदेश में 12 विधानसभा सीटों और एक लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने वाला है और यह उपचुनाव पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ है.

राजनीति की नब्ज समझने वाले लोगों का कहना है कि अमर सिंह को लेकर कुछ बड़े नेताओं की पेशबंदी ही यह संकेत दे रही है कि अमर सिंह की पार्टी में वापसी हो रही है. कुछ नेताओं की तीखी बयानबाजी अमर सिंह का प्रवेश रोकने के लिए हो रही है. यह अलग बात है कि पार्टी अनुशासन की भी ऐसी-तैसी हो रही है. अमर सिंह के दोबारा प्रवेश पर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अभी चुप है, लेकिन कुछ चुनिंदा नेता बात-बहादुरी की हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं. समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता ने कहा कि जनेश्वर मिश्र पार्क के लोकार्पण समारोह में आए अमर सिंह की मुलायम सिंह यादव से मंच पर भले ही बात न हुई हो, लेकिन मंच के नेपथ्य में अमर और मुलायम के बीच विस्तृत बातचीत हुई थी. यह बातचीत लखनऊ हवाई अड्डे की वीवीआईपी लॉबी और हवाई जहाज में हुई थी. सूत्रों का तो यहां तक कहना है कि राज्यसभा चुनाव के पहले अमर सिंह की समाजवादी पार्टी में इंट्री की घोषणा की जाएगी. प्रो. राम गोपाल यादव, आजम खान एवं सीपी राय जैसे नेता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के इस निर्णय को कामयाब न होने देने के लिए ही अनुशासनहीन बयानबाजी से परहेज नहीं कर रहे हैं.

अभी पिछले दिनों प्रो. राम गोपाल यादव ने पार्टी स्वयंभू बनते हुए बाकायदा यह घोषणा कर दी कि अमर सिंह का समाजवादी पार्टी में प्रवेश किसी भी क़ीमत पर नहीं होगा. अमर सिंह को पार्टी में शामिल किया जाएगा या नहीं, यह फ़ैसला जब अकेले मुलायम के हाथ में है, तो राम गोपाल का यह बयान किस परिप्रेक्ष्य में लिया जाए, इसे लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में भ्रम की स्थिति बनी हुई है. पार्टी सूत्रों का कहना है कि राम गोपाल या आजम खान के तल्ख बयान अमर फोबिया को लेकर ही आ रहे हैं. आजम खान तो अमर सिंह की पुनर्वापसी को लेकर इतने परेशान हो गए हैं कि उन्होंने यहां तक कह दिया कि क़ानून व्यवस्था के मामले पर अखिलेश यादव की सरकार पूरी तरह फेल हो गई है. आजम खान जैसे वरिष्ठ नेताओं की तरफ़ से अनुशासनहीनता भरे वक्तव्यों का जारी होना उनकी बेचैनी ही अभिव्यक्त कर रहा है. जनेश्वर मिश्र पार्क के लोकार्पण समारोह में प्रो. राम गोपाल और आजम खान के शरीक न होने से भी पार्टी की खूब किरकिरी हुई थी.

अखिलेश सरकार के पूरी तरह फेल हो जाने जैसे वक्तव्य के बाद राज्य सरकार ने आजम के चहेते नौकरशाहों पर सीधी कार्रवाई शुरू कर दी है. रामपुर में आजम खां के खास माने जाने वाले एआरटीओ कौशलेंद्र प्रताप यादव के निलंबन को इसी कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है. याद करें कि कौशलेंद्र यादव ही वह अधिकारी थे, जो अमर सिंह की अंतरंग सांसद जयाप्रदा से अभद्रता करने और उनकी गाड़ी से लालबत्ती उतरवाने के बाद भी ज़िले में लगातार डटे हुए थे. कौशलेंद्र को आपत्ति यह थी कि उनके आका के क्षेत्र में दूसरे की लालबत्ती लगी गाड़ी कैसे आ घुसी. कौशलेंद्र ने गाड़ी से न सिर्फ़ लालबत्ती उतरवा दी, बल्कि 25,000 रुपये का जुर्माना भी ठोंक दिया था. कौशलेंद्र के ख़िलाफ़ हुई कार्रवाई को अमर सिंह की नाराज़गी दूर करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है.

बहरहाल, अमर सिंह की पार्टी में वापसी की चर्चा के कारण ही कुछ प्रतिरोधी गतिविधियां भी तेज हो गई हैं. अमर सिंह समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, इन अटकलों को आधार बनाकर पार्टी के कुछ नेता कार्यकर्ताओं में आक्रोश पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं. आजम के बयान को भी इसी परिप्रेक्ष्य में लिया जा रहा है. अभी कुछ ही दिनों पहले पार्टी के प्रदेश महासचिव डॉ. सीपी राय ने कहा, मैं अमर सिंह के पार्टी में शामिल होने के सख्त ख़िलाफ़ हूं. यदि उन्हें पार्टी में फिर से शामिल किया जाता है, तो इस बात से मुझे काफी दु:ख होगा. राय ने अमर सिंह की राजनीतिक हैसियत को भी खुलेआम खूब खंगाला और ऐसा करने में पार्टी अनुशासन का कोई ध्यान नहीं रखा. शिवपाल सिंह यादव की पहल पर 19 अगस्त को हुई मुलायम-अमर मुलाकात इतनी चर्चा में रही कि लखनऊ आए भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को भी कहना पड़ा, मुलायम सिंह जी, अमर सिंह को लाने से भी अब समाजवादी पार्टी बचने वाली नहीं है. इस मुलाकात में अपनी भूमिका को लेकर पूछे गए सवाल से शिवपाल ने इंकार नहीं किया और अमर सिंह की पार्टी में वापसी की संभावनाओं को भी खारिज नहीं किया. शिवपाल ने इतना ही कहा, यह फ़ैसला केंद्रीय नेतृत्व को लेना है. उन्होंने यह कहकर सरगर्मी और बढ़ा दी कि इस मुलाकात से अच्छी शुरुआत हुई है. शिवपाल ने साफ़-साफ़ कहा कि अमर अगर पार्टी में वापस आने का प्रस्ताव देते हैं, तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उस पर विचार कर सकता है. ■

feedback@chauthiduniya.com

बिहार

शकुनी के पासों में उलझा महा-गठबंधन

सरोज सिंह

महा-गठबंधन के भविष्य को लेकर बिहार में इन दिनों अटकलों का बाज़ार गर्म है. दोस्ती में कुश्ती होगी या फिर यह नई दोस्ती दुश्मनों के छक्के छुड़ा देगी, इसे लेकर चर्चाओं और नुक्कड़ बहसों का दौर जारी है. लेकिन, दोस्ती की बिसात पर कुछ ऐसे पासे फेंके जाने लगे हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि कहीं महा-गठबंधन की डोर उलझ कर न रह जाए. उपचुनाव के लिए मतदान के ठीक पहले शकुनी चौधरी ने नीतीश कुमार एवं लालू प्रसाद को सीधे निशाने पर लेकर यह संकेत दे दिया कि पार्टी और गठबंधन में सब कुछ उन दोनों की मर्जी से नहीं होगा. शकुनी चौधरी राजनीति के बहुत ही मंझे हुए खिलाड़ी हैं, इसलिए उन्होंने अपना पासा फेंकने के लिए मतदान के ठीक पहले का समय चुना. यह सभी जानते हैं कि शकुनी चौधरी खुद को राज्यसभा न भेजे जाने से बेहद आहत हैं.

बताया जाता है कि नई दोस्ती से पहले खुद नीतीश कुमार शकुनी चौधरी के घर गए और उनसे राज्यसभा भेजने का वादा किया, लेकिन बाद में क्या हुआ, यह भी सब जानते हैं. शकुनी चौधरी खफा थे ही, ऐसे में नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद से गठबंधन का ऐलान करके उन्हें और भी नाराज़ कर दिया. शकुनी चौधरी का मत था कि भले ही लोकसभा चुनाव में पार्टी हार गई, लेकिन उपचुनाव में लालू से गठबंधन करने का कोई मतलब ही नहीं है. शकुनी चौधरी कहते हैं कि बेहतर होता नीतीश कुमार अकेले चुनाव मैदान में जाते और जनता का विश्वास हासिल करने की कोशिश करते. उपचुनाव के बाद गठबंधन पर परिस्थितियों के हिसाब से फ़ैसले लिए जा सकते थे, लेकिन गलत सलाहकारों से घिरे नीतीश कुमार ने ऐसा नहीं किया. शकुनी चौधरी कहते हैं कि लालू और नीतीश अहंकार में डूबे हुए हैं, इसलिए उनका विनाश तय है.

शकुनी चौधरी कहते हैं कि नीतीश कुमार कभी नेता नहीं हो सकते, वह सिर्फ़ साजिशकर्ता हो सकते हैं. लालू हर रोज उनका अपमान करते हैं, इसके बावजूद वह लालू के पैर पकड़ कर बैठे हैं. नीतीश कुमार में अगर जरा भी शर्म बची है, तो उन्हें राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए. शकुनी बताते हैं कि नीतीश उनके पास आकर गिड़गिड़ाए थे, तब उन्होंने उनका साथ दिया था. उनसे पहले लालू एक माह तक दौड़ते रहे. शकुनी का मानना है कि सत्ता के लिए बना यह गठबंधन सफल नहीं होगा. दरअसल, शकुनी चौधरी ने अपनी भड़ास निकाल कर पार्टी के उन विधायकों एवं नेताओं की भावनाओं को स्वर दे दिए, जो महा-गठबंधन के ख़िलाफ़ तो हैं, लेकिन खुलकर अपनी बात रखने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे. शकुनी चौधरी कहते हैं कि वह अकेले इस मत के नहीं हैं, बल्कि पार्टी के ज़्यादातर लोग ऐसा चाहते हैं, लेकिन एक आदमी की जिद के कारण पार्टी रसातल में जा रही है.

ग़ौरतलब है कि जदयू के बागी विधायकों ने पहले ही यह ऐलान कर दिया था कि लालू के साथ गठबंधन एक आत्मघाती क़दम है और इसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. जल्द ही वे लोग पार्टी को टेकओवर कर लेंगे, लेकिन मांझी सरकार को कोई ख़तरा नहीं होगा. दरअसल, शकुनी चौधरी के बगावती तेवरों ने जदयू के बागी विधायकों को नई ताकत दे दी है. ऐसा नहीं है कि महा-गठबंधन का विरोध केवल जदयू में हो रहा है. राजद के भी कई नेताओं को नीतीश से रिश्ता मंजूर नहीं है. राजद के पूर्व सांसद रघुवंश सिंह कहते हैं कि महा-गठबंधन में पार्टी और उसके नेता तो जुड़ गए, पर जनता नहीं जुड़ पाई. राजद, कांग्रेस एवं जदयू के बीच आपसी सामंजस्य की कमी है. राजद के कई नेता कहते हैं कि नीतीश राज में यादव हाशिये पर रहे, अब किस मुंह से नीतीश यादव वोटों की तरफ़ ताक रहे हैं. शकुनी चौधरी की बगावत के बाद विरोधी दलों ने भी महा-गठबंधन पर हमले तेज कर दिए हैं. नेता प्रतिपक्ष नंद किशोर यादव कहते हैं कि वह तो पहले से कहते आ रहे हैं कि यह महा-गठबंधन नहीं, बल्कि महा-ठगबंधन है. यादव ने कहा कि नीतीश में अगर नैतिकता है, तो वह शकुनी के हमले का जवाब दें. शकुनी ने जिस तरह नीतीश पर हमला किया, वह न केवल उनकी पार्टी की कमजोर स्थिति दर्शाता है, बल्कि राजद-जदयू गठबंधन के भविष्य पर भी प्रश्न खड़ा करता है. नीतीश राजनीतिक अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं.

लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस कहते हैं कि वह जो बात कहते आ रहे थे, वही शकुनी ने भी कह दी. महा-गठबंधन लोभियों का जमावड़ा है. पासवान समाज की जो उपेक्षा नीतीश राज में हुई, उसे कैसे भूला जा सकता है. समाज को बांटने वाले लोग अब बिहार और देश बचाने की बात करते हैं. पारस दावा करते हैं कि जदयू एवं राजद के कई विधायक उनके संपर्क में हैं. ठीक यही दावा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडेय कर रहे हैं. वह कहते हैं कि 50 से अधिक जदयू विधायक उनके संपर्क में हैं, जो सही समय आने पर पार्टी से अलग हो जाएंगे. पांडेय कहते हैं कि लालू के साथ मिलकर नीतीश जंगलराज लाना चाहते हैं, लेकिन जनता उनके मंसूबे सफल नहीं होने देगी. नीतीश को भाजपा ने आगे बढ़ाया, पर अहंकार के चलते वह गलत फ़ैसले लेने लगे. लोकसभा चुनाव में जनता उन्हें सबक सिखा चुकी है, विधानसभा चुनाव में उनका सूपड़ा साफ़ हो जाएगा. पांडेय का दावा है कि बिहार में अगली सरकार एनडीए की बनेगी.

सत्ता के गलियारों में अब यह चर्चा जोर पकड़ने लगी है कि लालू प्रसाद का बेवजह हस्तक्षेप कहीं इस महा-गठबंधन को बेमौत न मार दे. चुनाव प्रचार के दौरान लालू ने हमेशा यह एहसास दिलाने की कोशिश की कि वही फ्रंट रनर हैं. पैरों में आकर नीतीश के बैठने संबंधी बयान में लालू का यही अहंकार टपकता है. हालांकि बाद में उन्होंने अपना बयान सुधारा, लेकिन जितना नुक़सान होना था, वह हो गया. जानकार बताते हैं कि नीतीश समर्थक नेताओं ने इस बारे में अपना विरोध उन तक पहुंचा दिया. शरद यादव ने इशारों-इशारों में लालू को हिदायत भी दे दी. मतलब यह कि दोस्ती की बुनियादी शर्तें भी पूरी नहीं की जा रही हैं. चुनाव में हार-जीत अलग बात है, पर एक-दूसरे का सम्मान करने में भी परहेज हो जाए, तो फिर महा-गठबंधन का भविष्य समझा जा सकता है. शकुनी चौधरी ने जो बातें कहीं, उनका जवाब जदयू के पास नहीं है. जदयू के बागी ऐसे ही कुछ और विस्फोटों का इंतजार कर रहे हैं, ताकि पार्टी में एकाधिकार के ख़िलाफ़ जो लड़ाई उन्होंने छेड़ रखी है, उसे मुकाम तक पहुंचाया जा सके. बागी यह मानकर चल रहे हैं कि नीतीश का दौर अब ख़त्म हो चुका है. लालू से हाथ मिलाकर उन्होंने अपनी अंतिम चाल चल दी है. इसके बाद नीतीश के पास कोई तीर नहीं है. इसलिए बहुत जल्द हालात बदलेंगे और जदयू में एक नया सवेरा होगा. सुशील मोदी कहते हैं कि जंगलराज-2 की वापसी के नायक और सह-नायक जोर लगा रहे हैं, लेकिन उनके नापाक मंसूबे कामयाब नहीं होंगे. बिहार अब विकास चाहता है, इसलिए चुनाव में ऐसी ताकतों का पूरी तरह सफाया हो जाएगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
CHAUTHI DUNIYA

चौथी दुनिया की हर खबर अब आपके Android फोन पर भी उपलब्ध,
Play Store से Download करें | CHAUTHI DUNIYA APP |

झारखंड दिशोम पार्टी (झादिपा) का भाजपा में विलय हो गया. साकची गरम नाला स्थित रामगढ़िया सभागार में आयोजित एक समारोह में झादिपा नेता सालखन मुर्मू एवं उनके समर्थकों ने भाजपा की सदस्यता ली. मुर्मू ने कहा कि आदिवासी मतदाताओं के बिकाऊ चरित्र, ईसाई आदिवासियों के असहयोग और संसाधनों के अभाव ने चुनावी दंगल में पीछे धकेल दिया.

झारखंड

जोड़-तोड़ और गठजोड़ का नया दौर

मंगलानंद

आगामी नवंबर में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक जोड़-तोड़ और गठजोड़ का एक नया दौर शुरू हो गया है. राज्य के स्थापना काल से लेकर अब तक हुए विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमों को पीछे छोड़ते हुए इस बार रिकॉर्ड जोड़-तोड़ की राजनीति हुई. कई छोटे राजनीतिक दलों का बड़े राजनीतिक दल में विलय हो गया. राज्य के सभी दलों के नेताओं को ख़तरा सिर्फ़ भाजपा से है. ऐसे में नेताओं की पहली पसंद भाजपा बन चुकी है. झामुमो से लेकर झाविमो तक के नेता भाजपा में सीधे तौर पर प्रवेश कर रहे हैं. 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा के चुनाव में प्रदेश के क्षेत्रीय दलों के अध्यक्ष संभावनाएं तलाश कर रहे हैं. किस दल से गठबंधन उनके हित में होगा, इसके लिए मंथन का दौर जारी है.

बिहार की तर्ज पर झारखंड में भी महा-गठबंधन का राजनीतिक प्रयोग शुरू हो चुका है. विधानसभा चुनाव से पहले एक नया गठबंधन सामने आया है, जिसका नाम झारखंड प्रगतिशील गठबंधन (जेपीए) रखा गया है. जय भारत समानता पार्टी के अध्यक्ष मधु कोड़ा, टीएमसी के प्रदेश अध्यक्ष बंधु तिर्की एवं झारखंड पार्टी होरो के अध्यक्ष एनोस एक्का ने यह नया गठबंधन बनाया है. मधु कोड़ा ने कहा कि जनता राज्य में परिवर्तन चाहती है, हम विकल्प देंगे. अन्य दल जुड़ने का प्रस्ताव देते हैं, तो हम विचार करेंगे. जेपीए राज्य की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगा. सीटों के बंटवारे के संबंध में घोषणा रांची में होने वाले महा-सम्मेलन में की जाएगी. कोड़ा ने कहा कि झारखंड की जनता यूपीए और एनडीए से तंग आ चुकी है. हम भाजपा और कांग्रेस छोड़कर अन्य विचारधारा वाले दलों के साथ शर्तों पर समझौता करने के लिए तैयार हैं. पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनके कार्यकाल में जितने कार्य हुए, उतने किसी अन्य मुख्यमंत्री के कार्यकाल में नहीं हुए. विधायक बंधु तिर्की ने कहा कि मधु कोड़ा उनके सर्वमान्य नेता होंगे और जेपीए का नेतृत्व करेंगे.

बिहार की तर्ज पर झारखंड में भी महा-गठबंधन का राजनीतिक प्रयोग शुरू हो चुका है. विधानसभा चुनाव से पहले एक नया गठबंधन सामने आया है, जिसका नाम झारखंड प्रगतिशील गठबंधन (जेपीए) रखा गया है. जय भारत समानता पार्टी के अध्यक्ष मधु कोड़ा, टीएमसी के प्रदेश अध्यक्ष बंधु तिर्की एवं झारखंड पार्टी होरो के अध्यक्ष एनोस एक्का ने यह नया गठबंधन बनाया है.

झारखंड दिशोम पार्टी (झादिपा) का भाजपा में विलय हो गया. साकची गरम नाला स्थित रामगढ़िया सभागार में आयोजित एक समारोह में झादिपा नेता सालखन मुर्मू एवं उनके समर्थकों ने भाजपा की सदस्यता ली. मुर्मू ने कहा कि आदिवासी मतदाताओं के बिकाऊ चरित्र, ईसाई आदिवासियों के असहयोग और संसाधनों के अभाव ने चुनावी दंगल में पीछे धकेल दिया. आदिवासियों के हित में हमें रणनीति बदलनी पड़ी और भाजपा में विलय का निर्णय लेना पड़ा. समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व विधायक सरयू राय, दिनेशानंद गोस्वामी, अमरप्रीत सिंह काले आदि मौजूद थे.

लिट्टीपाड़ा के झामुमो विधायक साइमन मरांडी, तमाड़ के जदयू विधायक गोपाल कृष्ण पातर उर्फ राजा पीटर, पूर्व विधायक एवं झाविमो नेता दुलाल भुइयां, रांची के पूर्व विधायक गुलशन लाल अजमानी और झाविमो छोड़ चुके रांची के पूर्व डिप्टी मेयर अजय नाथ शाहदेव समेत कई नेता अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए. झारखंड विकास मोर्चा के विधायक समरेश सिंह, जयप्रकाश सिंह, चंद्रिका महथा एवं निर्भय शाहबादी ने दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की और हरी झंडी मिलने के बाद भाजपा में शामिल हो गए. कांग्रेस किसी गठबंधन में शामिल होने की बजाय अकेले चुनाव लड़ना चाहती है. नेताओं एवं कार्यकर्ताओं का मानना है कि लोकसभा चुनाव में गठबंधन का लाभ कांग्रेस को नहीं मिला और पार्टी की करारी हार हुई. गठबंधन में शामिल होने से पार्टी को न केवल नुक़सान उठाना पड़ेगा, बल्कि संगठन भी कमजोर होगा. प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत का कहना है कि गठबंधन के साथ पार्टी दो चुनाव लड़ी, लेकिन नतीजे अपेक्षित नहीं रहे. ऐसे में संगठन खड़ा करने और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए अकेले चुनाव लड़ना हितकर है. उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की इस भावना से आलाकमान को अवगत कराया जाएगा, क्योंकि गठबंधन पर अंतिम निर्णय आलाकमान को लेना है. बैठक में सह-प्रभारी ताराचंद भगोरा, प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत, विधायक दल के नेता राजेंद्र प्रसाद सिंह, जिलाध्यक्ष विशन सिंह बेदी, देबू चटर्जी एवं दीपिका पांडेय समेत राज्य भर के जिलाध्यक्ष मौजूद थे.

कुल मिलाकर यह साफ़ हो चुका है कि सबका मुकाबला भाजपा से होगा. प्रदेश में सबसे अधिक नुक़सान झारखंड विकास मोर्चा को हुआ है. इस पार्टी में भगोड़े नेताओं की संख्या सबसे अधिक रही. सुदेश महतो की पार्टी आजसू अस्तित्व रक्षा की लड़ाई अपने दम पर लड़ रही है, इस दल के नेताओं ने कहीं और जाना मुनासिब नहीं समझा.■

feedback@chauthiduniya.com

उत्तराखंड

सरकार के काम को जनता का आशीर्वाद

राजकुमार शर्मा

बिहार में हुए महा-गठबंधन का भविष्य उज्ज्वल है और उसका सफल प्रयोग देवभूमि से ही शुरू हुआ. यह कहना है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत का. चौथी दुनिया के साथ बातचीत में रावत कहते हैं कि समय की मांग के अनुसार यह बिहार विधानसभा उपचुनाव में सफल साबित होगा. सांप्रदायिकता और भ्रष्टाचार देश के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है. वह कहते हैं कि मोदी की हवा ख़त्म हो चुकी है और काठ की हांडी बार-बार नहीं चढ़ती. जनता अच्छे दिन खोज रही है और भारतीय जनता पार्टी के क़दम येदियुरप्पा की ओर बढ़ रहे हैं.

कांग्रेस के गर्दिश के दिनों में जिस तरह राज्य में हुए उपचुनाव में तीनों सीटें जीतकर हरीश रावत ने अपनी नेतृत्व क्षमता साबित की. आत्मविश्वास से लबरेज दिख रहे मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि उनकी प्राथमिकता रही है कि राज्य की कांग्रेस सरकार जनता को सभी सुविधाएं व्यवस्थित ढंग से मुहैया कराए. विधानसभा उपचुनाव के एक माह बाद संपन्न हुए पंचायत चुनाव में भी हरीश के नेतृत्व में कांग्रेस ने जबर्दस्त सफलता हासिल की. खराब स्वास्थ्य के बावजूद कांग्रेस को उबारने वाले हरीश रावत ने अपनी सफलता का पूरा श्रेय राज्य की जनता को दिया. ग़ौरतलब है कि हरीश रावत कांग्रेस के ग्रासरूट कार्यकर्ता रहे हैं. छात्र राजनीति से अपनी शुरुआत करने वाले हरीश ने सदैव जनता को अपना आदर्श माना. राजनीति की पहली पायदान पर उनका मुकाबला डॉ. मुरली मनोहर जोशी से हुआ. तबसे लेकर अब तक हरीश अजेय सिद्ध हुए.

चौथी दुनिया को एक निर्भीक एवं निष्पक्ष अख़बार बताते हुए हरीश रावत कहते हैं कि अन्य समाचार-पत्र समूहों को भी निष्पक्षता के साथ अपनी भूमिका निभानी चाहिए. राज्य कांग्रेस में बढ़ रही गुटबाजी का सवाल सिरे से खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि दल के जो भी छोटे-बड़े नेता अपने सुझाव सामने रखते हैं, उन पर हम विचार करते हैं. हमारी कोशिश है कि सरकार हर स्तर पर जनता की कसौटी पर खरी उतरे. हम जनता के सेवक हैं और हर पल उसके साथ हैं. उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने सरकार की छवि खराब करने के लिए हर स्तर पर दुष्प्रचार का अभियान चलाया, लेकिन उसकी नकारात्मक सोच उसके लिए अभिशाप बन गई. खराब स्वास्थ्य के बावजूद हमने और हमारी सरकार ने जनसेवा का सकारात्मक मार्ग अपनाया, जो वरदान सिद्ध हुआ यानी जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चार धाम यात्रा सहित पर्यटन को बहाल कर खुशहाली का मार्ग खोलने की हर कोशिश कर रही है. रावत ने नंदा

देवी हिमालयी कुंभ की सफलता का श्रेय जनता को दिया.

हरीश ने केंद्र सरकार को सांप्रदायिक सौहार्द के लिए अपनी कथनी-करनी में अंतर समाप्त करने की सलाह दी और कहा कि शाह और येदियुरप्पा के रास्ते पर चलकर सांप्रदायिकता और भ्रष्टाचार को ख़त्म नहीं किया जा सकता. लालकिले से खुद को प्रधान सेवक कहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नसीहत देते हुए हरीश रावत ने कहा कि उन्हें जुबानी सेवक बनने से बचना चाहिए. हरीश ने बताया कि राज्य के मंत्रियों-अफसरों की विदेश यात्राओं पर रोक लगा दी गई है. सरकार की पूरी कोशिश है कि राज्य में कोई भी शख्स भूखा न सोए. केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह के उस बयान कि हरीश सरकार अच्छा काम कर रही है, पर उन्होंने कहा कि यह एक सच्चाई है और सच को सच बताने वालों की अभी कमी नहीं है.■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
CHAUTHI DUNIYA
चौथी दुनिया की हर खबर अब आपके Android फोन पर भी उपलब्ध,
Play Store से Download करें | CHAUTHI DUNIYA APP

1988 में यूपी सरकार ने सीबीसीआईडी इंक्वारी का आदेश दिया. पूर्व ऑडिटर जैनरल ज्ञान प्रकाश के नेतृत्व में तीन सदस्यीय इंक्वायरी कमेटी बनी और फिर उसने 1994 में अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश कर दी. ये रिपोर्ट 1995 में उस समय तक सामने नहीं लाई गई जबतक कि प्रभावित व्यक्ति इलाहबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बैंच नहीं पहुंचे. सीबीसीआईडी रिपोर्ट में पीएसी और पुलिस विभाग के 37 कर्मचारी के प्रोसिक्यूसन की सिफारिशें की गईं और फिर प्रथम जून 1995 को राज्य सरकार ने उनमें से 19 को प्रोसिक्यूट करने का निर्देश दिया था.

फोटो-*प्रभात पाण्डेय*

हाशिमपुरा नरसंहार

अदालत में आखिरी सुनवाई जारी है...

गत 13 अगस्त 2014 को बदनामे जमाना हाशिमपुरा नरसंहार से संबंधित 27 वर्षीय पुराने मुकदमे की अंतिम दौर की सुनवाई दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में शुरू हुई. उसके बाद 16 अगस्त को भी सुनवाई हुई. 13 अगस्त को स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर सतीश टमटा ने अंतिम बहस शुरू की और अदालत के सामने मेरठ शहर के हाशिमपुरा मुहल्ले से 22 मई 1987 को कथित रूप से पीएसी के जवानों के द्वारा अगवा करके मुरादनगर (गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश) लाए गए. 42 व्यक्तियों में से एक एक को गोली मार कर हत्या करने का बृतांत बताया और इन्हीं लोगों में से जिंदा बचे हुए दो व्यक्ति द्वारा दर्ज की गई एफआरआई की कॉपी प्रस्तुत किया. इसी के साथ साथ इस मुकदमे के तमाम गवाहों के बयानों को भी पढ़ कर सुनाया. स्मरण रहे कि पीएसी के 19 आरोपियों में से तीन का देहांत हो चुका है. इस मुकदमे के फैसले का इंतजार पूरे राष्ट्र को बेचैनी से इंतजार है. लेकिन सवाल है कि इस मुकदमे को आखिर अंजाम तक पहुंचने में 27 वर्ष क्यों लग गए? इस मामले में मुस्लिम एवं मानवाधिकार संगठनों की भूमिका क्या रही? इन प्रश्नों के पेशे-नजर चौथी दुनिया जिसने 27 वर्ष पूर्व इस मामले को सामने लाने में अहम रोल अदा किया, सिलसिलेवार सीरिज शुरू कर रहा है. आइए इस बार सबसे पहले देखते हैं हाशिमपुरा मामला आखिर है क्या और अदालती प्रक्रिया में इतनी देर क्यों लगी? आगामी सप्ताह मुस्लिम एवं मानवाधिकार संगठनों एवं विशिष्ट व्यक्तियों की भूमिका से संबंधित खुलासे पेश किए जाएंगे.

ए.यू. आसिफ

हाशिमपुरा मेरठ शहर का एक पुराना और प्रसिद्ध मुस्लिम मुहल्ला है. इसके ठीक पीछे एक हिंदू मुहल्ला आबाद है, जिसके सामने सड़क पार गुलमर्ग सिनेमा हॉल है. 19 मई 1987 को मेरठ शहर के दूसरे क्षेत्रों में सांप्रदायिक घटना एवं तनाव के कारण पूरे शहर कर्फ्यू लगा था. हाशिमपुरा एवं उससे सटे हुए इलाके में सबकुछ सामान्य था. लेकिन 22 मई 1987 को अचानक फौज और पैरामिलेट्री फोर्सेस ने हाशिमपुरा की नाकाबंदी कर दी. इसके बाद मोहल्ले के तमाम घरों में तलाशी की मुहिम शुरू कर दी. फिर मोहल्ले के तमाम मर्दों को बाहर सड़क पर लाकर घुटने के बल बैठा दिया गया. इस दौरान 360 व्यक्तियों को गिरफ्तार करके पीएसी के ट्रकों में लादकर मेरठ के सिविल लाइंस थाना और पुलिस लाइंस भेज दिया गया. इन गिरफ्तार 360 लोगों में से 42 लोगों (जिनमें नौजवानों की संख्या अधिक थी) को पड़ोस के ग़ाजियाबाद जिले के मुरादनगर में पुल के समीप स्थित गंग बैरेज कैनाल ले जाया गया. जहां ढ़ेड़ दर्जन पीएसी जवानों ने लगभग रात्रि के नौ बजे अंधेरे में इन 42 लोगों को एक-एक करके गोली मारना शुरू की और उन्हें नहर में फैंकना शुरू कर दिया. इसी बीच अबुपूर गांव जा रही सड़क पर चलती गाड़ियों की हेडलाइट्स की रोशनी में दिखाई पड़ने के डर से पीएसी के जवान कुछ बचे लोगों को लेकर हिंडन कैनाल पहुंचे. कुछ लोगों को ट्रक के अंदर गोली मारी और कुछ को नहर के किनारे गोली मारी. उसके बाद बहते हुए पानी में उन्हें फेंक दिया. गोली मारे जाने वाले 42 लोगों में से कुछ बुरी तरह घायल हो गए लेकिन किसी तरह जिंदा बच गए. दरअसल किसी तरह बचे ये लोग ही लोग इस नरसंहार की घटना के चश्मदीद गवाह हैं. इनमें हाशिमपुरा के स्कूली छात्र जुल्फीकार नासीर शामिल थे.

नरसंहार की यह घटना 22-23 मई 1987 की रात को घटित हुई. 24 मई की शाम को जब यह पत्रकार मुरादनगर पुल से अबुपूर गांव की ओर जा रही गंग नहर के किनारे सड़क पर पंहुचा, उस वक्त भी वहां सड़क और झाड़ियों पर खून के धब्बे मौजूद थे. सड़क पर पुलिस द्वारा बनाया पीले रंग का क्रॉस का निशान लगा हुआ था. मगर दूसरे दिन जब लोक दल के दो नेता डॉ. सुब्रहमणयम स्वामी एवं मोहमद युनूस सलीम के साथ यह पत्रकार यहां पहुंचा तो वह पीला निशान मौजूद नहीं था. उसे मिटा दिया गया था. ये मालूम नहीं हो सका कि उस निशान को किसने मिटाया. वर्ष 1987 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्राइम ब्रांच सेंट्रल इन्वेस्टीगेशन डिपार्टमेंट (सीवी-सीआईडी) इनक्वाइरी के दौरान लिंक रोड थाने के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह का बयान है कि सूचना मिलने पर वो हिंडन कैनल की ओर गए यहां उन्होंने पीएसी के एक ट्रक को दूसरे घटनास्थल से लौटता हुआ पाया. इसके बाद जब उन्होंने उसका पीछा किया तो वह ट्रक पीएसी की 41वीं वाहिनी के कैंप में घुस गया. इसके बाद गाजियाबाद के तत्कालीन एसपी विभूति नारायण राय और डीएम नसीम जैदी भी 41वीं वाहिनी पहुंचे और सीनियर पीएसी अधिकारियों के साथ उपरोक्त ट्रक की पहचान करने की कोशिश की,लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला.

जैसा कि जगजाहिर है कि मीडिया में खुलासा (तब चौथी दुनिया ने इस खबर को दुनिया के सामने लाया था) आने एवं मानवाधिकार, मुस्लिम एवं अन्य संगठनों और व्यक्तियों के द्वारा इस नरसंहार के विरुद्ध आवाज उठाने के बाद भी केंद्र में राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार संसद के अंदर एवं बाहर और उत्तर प्रदेश राज्य में वीर बहादुर सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार दोनों इस नरसंहार के होने के बारे में सिरे से इन्कार करते रहे. इस पत्रकार को अब भी याद है जब कुछ सड़ी हुई लाशों के पास खड़े होकर 1987 को डॉ. स्वामी से पूछा गया कि ये सब क्या है तो उन्होंने जवाब दिया कि ये स्टेट स्पानसर्ड जिनोसाइड है. उस समय जब पूर्व विधि राज्य मंत्री युनूस सलीम से पूछा गया कि क्या यह स्टेट स्पानसर्ड जिनोसाइड नहीं है? तब उन्होंने कहा कि अगर ये जिनोसाइड नहीं है तो फिर क्या है. (साप्ताहिक रेडिएंस, 21-27 जून 1987) 1988 में यूपी सरकार ने सीबीसीआईडी इंक्वारी का आदेश दिया. पूर्व ऑडिटर जैनरल ज्ञान प्रकाश के नेतृत्व में तीन सदस्यीय इंक्वायरी कमेटी बनी और फिर उसने 1994 में अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश कर दी. ये रिपोर्ट 1995 में उस समय तक सामने नहीं लाई गई जबतक कि प्रभावित व्यक्ति इलाहबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बैंच नहीं पहुंचे. सीबीसीआईडी रिपोर्ट में पीएसी और पुलिस विभाग के 37 कर्मचारी के प्रोसिक्यूसन की सिफारिशें की गईं और फिर प्रथम जून 1995 को राज्य सरकार ने उनमें से 19 को प्रोसिक्यूट करने का निर्देश दिया था. उसके बाद 20 मई 1997 को मुख्यमंत्री मायावती ने भी शेष 17 पदाधिकारियों के प्रोसिक्यूशन की इजाजत दी. इंक्वारी के बाद 1996 में गाजियाबाद के सीजेएम के यहां सीपीसी के सेक्सन 197 के अंतर्गत चार्जशीट पेश की गई जिन्होंने फौरन ही अदालत में आरोपियों को हाजिर होने के लिए वारंट जारी कर दिए. 1994 से लेकर 2000 तक कुल मिलाकर 23 बार जमानती वारंट जारी किए गए मगर इनमें से कोई अदालत में हाजिर नहीं हुआ. फिर अप्रैल 1998 से लेकर अप्रैल 2000 तक 17 बार जमानती वारंट इशू किए गए. 2000 में इन 19 आरोपियों में से 16 ने गाजियाबाद की अदालत में काफी दबाव पड़ने पर सरेंडर किया और फिर उन्हें मात्र जमानत ही नहीं मिली बल्कि उन्होंने अपनी अपनी पुलिस की नौकरी दोबारा ज्वॉइन भी कर ली.

फिर 2001 में गाजियाबाद में हो रही ट्रायल की कार्यवाही में बहुत देरी होने के कारण हत्या किए गए लोगों के संबंधियों और बचे कुचे लोगों ने गाजियाबाद से दिल्ली मुकदमा को ट्रांस्फर करने की सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन दी. तब जाकर सितंबर 2002 में उच्चतम न्यायालय ने मुकदमा के स्थानांतरण की अनुमति दी. मगर तीस हजारी अदालत में मुकदमा शुरू नहीं हो सका क्योंकि राज्य सरकार ने नवंबर 2004 तक उस मुकदा के लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त नहीं किया. वैसे इस प्रोसिक्यूटर को भी किसी अयोग्यता के कारण बदलना पड़ा. मई 2006 में तमाम 19 पीएसी आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट फाइल की गई उनपर जो आरोप लगाए गए वो हत्या एवं गवाही के साथ टैंपरिंग करने के मामले थे जो कि आईपीसी के सेक्सन 302/120बी /307/ 201/ 149/ 364/ 148/147 के अंतर्गत थे. फिर 15 जुलाई 2006 को ट्रायल शुरू होते समय ये तीथी भी बढ़ाई गई. उस समय दिल्ली सेशन अदालत के एडिशनल सेशल जज एनपी कौशिक ने यूपी के चीफ सेक्रेटरी और विधि सचिव को नोटिस देते हुए पुछा आखिर ये मुकदमा अर्जेंट बुनियाद पर मुनासिब अंदाज से क्यों नहीं निपटाया गया. फिर जब ट्रायल शुरू हुआ तो प्रभावितों में जिंदा बचे हुए जुल्फीकार नासीर ने तीस हजारी अदालत में आकर चश्मदीद गवाह के तौर सबकुछ बताया. तत्पश्चात फरवरी 2007 में एक दूसरे जीवित बचे मोहमद उस्मान ने कहा कि जब हम लोगों में से तीन नौजवानों को उस रात्रि सड़क से निकाल कर गोली मारी गई तो ट्रक में हम लोगों ने हंगामा किया तब हम लोगों को भी चुप करने के लिए गोली छोड़ी गई. मई 2010 में सीबीसीआईडी द्वारा 161 गवाहों में से 36 की जांच की गई. 19 मई 2010 को चार गवाहों ने एडिशनल सेशन जज मनु राय सेठी के सामने अपने बयान दर्ज कराए. ये सिराजुदीन, अब्दुल गफ्फार, अब्दुल हमीद और उस समय के ओएसडी जीएल शर्मा थे. फिर 16 अक्टूबर 2012 को जनता पार्टी अध्यक्ष डॉ स्वामी ने दिल्ली की इस अदालत का दरवाजा खटखटाया और इस मुकदमा में उन दिनों गृह राज्य मंत्री पी चिदंबरम के विरुद्ध उनकी कथित भूमिका की इंक्वायरी की मांग की जिसे रद्द कर दिया गया. डॉ स्वामी का आरोप था कि इन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री के साथ घटना से एक रात्री पूर्व मेरठ की सर्किट हाउस में पूरी साजिश रची थी.

ये है पूरी दर्दनाक दास्तान एवं संबंधित राज्य सरकार द्वारा मुकदमा को टालने की कोशिश. बहरहाल सुनवाई खत्म होने पर सच सामने आ जाएगा और देर से ही सही प्रभावितों और उनके संबंधियों के साथ साथ बचे कुचे लोगों को अंततः न्याय मिल पाएगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

ये दुखद घटना 22-23 मई 1987 की रात्रि में हुई. ये पत्रकार मुरादनगर पुल पर बाएं ओर अबुपूर गांव जा रही गंग कैनल के किनारे सड़क पर 24 मई की शाम जब पहुंचा तो वहां सड़क और झारियों पर लहू के धब्बे उस समय में भी मौजूद थे और सड़क पर पुलिस द्वारा पीले रंग का क्रोस का निशान लगा हुआ था. मगर दूसरे दिन जब लोक दल के दो नेता डॉ. सुब्रमण्यण स्वामी एवं मोहमद युनूस सलीम के साथ ये पत्रकार यहां पहुंचा तो इस निशान को मिटा दिया गया था. ये मालूम नहीं हो सका कि ये किसने मिटाया. 1987 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्राइम ब्रांच सेंट्रल इनवेस्टीगेशन डिपार्टमेंट (सीवीसीआईडी) इनक्वाइरी के दौरान लिंक रोड थाना के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह का बयान है कि सूचना मिलने पर वो हिंडन कैनल की ओर गए यहां उन्होंने पीएसी के एक ट्रक को इस दूसरे घटनास्थल से लौटते हुए पाया और जब उसका पिछा किया तब वो पीएसी की 41वीं वाहिनी कैंप में घुस गया. उसके बाद गाजियाबाद के उस समय के एसपी विभूति नारायण राय एवं डीएम नसीम जैदी भी 41वीं वाहिनी पहुंचे और सीनियर पीएसी अधिकरियों के द्वारा उपरोक्त ट्रक की पहचान करने की कोशिश की मगर इसका कोई नतीजा नहीं निकला.

ब्रेड खाने के बाद रमाकांत का पेट फूल गया और दोबारा तेज दर्द होने लगा. इस पर डॉक्टरों ने उन्हें जनरल वॉर्ड से इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट कर दिया और रात में ऑपरेशन करने की बात कही, लेकिन ऑपरेशन नहीं किया गया. जैसे-तैसे रात कटी. सुबह जब डॉक्टर राउंड पर आए, तो उनसे ऑपरेशन के लिए पूछा गया. जवाब में उन्होंने कहा कि देखते हैं कि आज या कल या कब करेंगे. पिता की बिगड़ती हालत और डॉक्टरों की अनिर्णय की स्थिति देखकर रमाकांत के पुत्र ने उन्हें गोरखपुर के एक निजी अस्पताल ले जाने का निर्णय किया.

रमाकांत

ग़रीबों के लिए नहीं है गोरखपुर मेडिकल कॉलेज

नवगठित मोदी सरकार ने देश के सभी सरकारी अस्पतालों में आवश्यक दवाएं मुफ्त देने की बात कही थी, लेकिन बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज में व्याप्त भ्रष्टाचार के चलते मरीजों को दवाएं बाहर से खरीदनी पड़ रही हैं. डॉक्टरों ने इंफेक्शन कम करने के लिए 500 रुपये का एंटीबायोटिक इंजेक्शन रमाकांत को लिखा, जो दिन में तीन बार लगना था.

नवीन चौहान

पूर्वांचल की स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ समझा जाने वाला गोरखपुर स्थित बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज इन दिनों अव्यवस्था और मनमानी का शिकार है. ग़रीब मरीजों को यहां तरह-तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. डॉक्टरों द्वारा टालमटोल वाला रवैया अख्तियार करना आम बात हो गई है. उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करने का दंभ भरती रहती हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर हालत में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता. जब नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल के वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ने का निर्णय लिया, तो इलाकाई लोगों को लगा था कि उनके (नरेंद्र मोदी) प्रधानमंत्री बनते ही पूर्वांचल की मूलभूत समस्याएं दूर हो जाएंगी और अच्छे दिन आ जाएंगे, लेकिन अभी तक लोगों को सिर्फ़ निराशा हाथ लगी है.

बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान लापरवाही बरतने का एक ताजा मामला प्रकाश में आया है. हुआ यह कि देवरिया निवासी रमाकांत लंबे समय से पेट दर्द से पीड़ित थे. वह बीते 10 अगस्त को अपना इलाज कराने देवरिया से गोरखपुर आए. मेडिकल कॉलेज में जांच के बाद डॉक्टरों ने उनकी आंतों में इंफेक्शन बताया और ऑपरेशन की सलाह देते हुए उन्हें अस्पताल में भर्ती कर लिया. इसके बाद भी रमाकांत के पेट में दर्द लगातार होता रहा. डॉक्टरों ने कई बार मरीज के परिजनों को ऑपरेशन की तैयारी करने के लिए कहा और खुद एक-एक दिन करके ऑपरेशन टालते रहे. उधर दर्द में दिन-ब-दिन इज़ाफा हो रहा था. हालत बिगड़ती देख डॉक्टरों ने उन्हें केवल लिक्विड डाइट लेने और एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगवाने की सलाह दी. इसके बाद हालत में थोड़ा सुधार हुआ. तक़रीबन 5-6 दिनों के बाद डॉक्टरों ने उन्हें ब्रेड (सॉलिड डाइट) लेने की सलाह दी.

ब्रेड खाने के बाद रमाकांत का पेट फूल गया और दोबारा तेज दर्द होने लगा. इस पर डॉक्टरों ने उन्हें जनरल वॉर्ड से इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट कर दिया और रात में ऑपरेशन करने की बात कही, लेकिन ऑपरेशन नहीं किया गया. जैसे-तैसे रात कटी. सुबह जब डॉक्टर राउंड पर आए, तो उनसे ऑपरेशन के लिए पूछा गया. जवाब में उन्होंने कहा कि देखते हैं कि आज या कल या कब करेंगे. पिता की बिगड़ती हालत और डॉक्टरों की अनिर्णय की स्थिति देखकर रमाकांत के पुत्र ने उन्हें गोरखपुर के एक निजी अस्पताल ले जाने का निर्णय किया. जब परिजनों ने मरीज को निजी अस्पताल में शिफ्ट करने की बात कही, तो डॉक्टरों ने उन्हें ऑन पेपर डिस्चार्ज नहीं किया. यह मनमानी और धांधागर्दी नहीं, तो और क्या है?

नवगठित मोदी सरकार ने देश के सभी सरकारी अस्पतालों में आवश्यक दवाएं मुफ्त देने की बात कही थी, लेकिन बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज में व्याप्त भ्रष्टाचार के चलते मरीजों को दवाएं बाहर से खरीदनी पड़ रही हैं. डॉक्टरों ने इंफेक्शन कम करने के लिए 500 रुपये का एंटीबायोटिक इंजेक्शन रमाकांत को लिखा, जो दिन में तीन बार लगना था. इंजेक्शन अस्पताल में उपलब्ध था, इसके बावजूद इंजेक्शन उन्हें उपलब्ध नहीं कराया गया और बाहर से खरीद कर लाने को कहा गया. एक बार बाहर से इंजेक्शन लाने के बाद दूसरे दिन ड्यूटी पर तैनात सिस्टर ने 500 रुपये देने पर अस्पताल से ही इंजेक्शन उपलब्ध कराने की बात कही. पैसे मिलते ही आउट ऑफ स्टॉक इंजेक्शन अस्पताल में उपलब्ध हो गया! इतनी जल्दी किस एजेंसी ने अस्पताल को इंजेक्शन की आपूर्ति कर दी? 10 अगस्त से 21 अगस्त यानी 12 दिनों तक अस्पताल में रहने के बावजूद कोई फ़ायदा नहीं हुआ. दवा और जांच में तक़रीबन 15 हज़ार रुपये खर्च हो गए, सो अलग. भ्रष्टाचार का आलम यह कि एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड जैसी जांचें भी बाहर से करानी पड़ीं. हर साल दिमागी बुखार का सामना करने वाले पूर्वांचल के इस मेडिकल कॉलेज में क्या एक्स-रे और अल्ट्रासाउंड जैसी बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं? यदि उपलब्ध हैं, तो उनका उपयोग किसके लिए होता है? इस मेडिकल कॉलेज को सरकारें जो पैसा उपलब्ध कराती हैं, वह आख़िर कहां जाता है? देश का ग़रीब आदमी डॉक्टरों को भगवान मानता है. उसका शासन-प्रशासन से विश्वास पहले ही उठ गया था, लेकिन अब उसका विश्वास इन भगवानों से भी उठता जा रहा है. सरकारी अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज लोगों को भरोसा खोते जा रहे हैं. मजबूरी में उन्हें अपने मरीज की जान बचाने के लिए निजी अस्पतालों की ओर रुख करना पड़ रहा है. सीधा-सा मतलब यह है कि देश में कोई भी सरकार आ जाए, लेकिन सरकारी अस्पतालों के तौर-तरीके नहीं बदलने वाले. जनता मरती है, तो मरती रहे. रमाकांत के मसले पर जब चौथी दुनिया ने बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज के डीन के पी कुशवाहा से बात की, तो उन्होंने इसकी जानकारी न होने की बात कही. जानकारी लेने के बाद मरीज को दोबारा मेडिकल कॉलेज लाने के लिए कहा, लेकिन मरीज के परिजनों का भरोसा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों से इतना डिग चुका था कि वे दोबारा वहां जाने की हिम्मत नहीं जुटा सके. केंद्र सरकार देश में एम्स जैसे संस्थान स्थापित करने की दिशा में काम कर रही है. यह परियोजना पूरी तरह कार्यान्वित होने में अभी वक्त लगेगा, तब तक लोगों को इसी तरह जूझना पड़ेगा. सरकार को सबसे पहले देश के मेडिकल कॉलेजों को सुधारना होगा और उनकी गुणवत्ता बढ़ानी होगी, ताकि लोगों को अपने घर के आसपास ही बेहतर इलाज मिल सके. ■

navinonline2003@gmail.com

पूर्वोत्तर की महिलाएं

पुरुषों से दो क़दम आगे

भारत नारी को शक्ति का प्रतीक मानता है, लेकिन महिलाओं के साथ आए दिन होने वाले भेदभाव ने इस प्रतीक को शक्तिहीन बना दिया है. वातानुकूलित कमरों में बैठ कर तमाम किस्म के विमर्श होते हैं कि कैसे महिलाओं को सशक्त बनाया जाए. लेकिन, भारत में एक ऐसी जगह भी है, जहां की महिलाएं इस पूरी कहानी की अलग और सुंदर तस्वीर पेश करती हैं. आइए, जानते हैं, पूर्वोत्तर की महिलाओं की वे कहानियां, जो बताती हैं कि असल में महिला सशक्तिकरण के मायने क्या हैं....

एस. बिजेन सिंह

देश के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं को सम्मान दिलाने की जद्दोजहद जारी है, वहीं दूसरी तरफ़ पूर्वोत्तर की महिलाएं शिक्षा, खेल एवं समाजसेवा आदि हर क्षेत्र में अपने-अपने राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हुए देश का नाम रोशन कर रही हैं. घरेलू महिलाएं भी घर के कामकाज के अलावा कुछ ऐसे कार्यों से जुड़ी हुई हैं, जो इन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद करते हैं. इससे न केवल इनकी अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार आ रहा है, बल्कि इसका असर राज्य की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है.

मणिपुर स्थित ईमा कैथेल केवल महिलाओं का बाज़ार है. यह बाज़ार महिला सशक्तिकरण का एक प्रतीक है. ईमा कैथेल राजधानी इंफाल के बीचोबीच स्थित है. राज्य की महिलाओं को कार्यस्थल, घर एवं समुदाय की ओर से कई तरह की सहूलियतें हासिल हैं, जो देश के बाकी हिस्सों में बहुत कम मिलती हैं. इस बाज़ार की दुकानदार महिलाओं की अपनी एक अलग जीवनशैली है. यहां हरी सब्जियां, खाद्य पदार्थ, लोहे के औजार, मछलियां, कपड़े, बांस निर्मित वस्तुएं एवं मिट्टी के बर्तन आदि का व्यवसाय होता है. ईमा कैथेल के माध्यम से मणिपुर की महिलाओं ने व्यापार-वाणिज्य के क्षेत्र में अपने क़दम आगे बढ़ाए हैं. इन दुकानदार महिलाओं को समय-समय पर राजनीतिक और सैन्य हलचलों का भी सामना करना पड़ता है. जीवन को स्वदेशी बनाए रखने में इन महिलाओं की बड़ी भूमिका है. अपने परिवार एवं समुदाय के लिए ये आर्थिक स्तंभ की तरह हैं. ये 4,000 शक्तिशाली महिलाएं अपने बेहतर भविष्य के लिए हमेशा एकजुट रहती हैं.

पूर्वोत्तर मूल रूप से महिला प्रधान समाज है. यहां महिलाओं की स्थिति बहुत मजबूत है. पुरुषों की अपेक्षा परिवार की ज़्यादातर ज़िम्मेदारियां महिलाएं संभालती हैं. ये घर से बाहर निकल कर मज़दूरी करती हैं, अपनी खेती-बाड़ी का काम संभालती हैं, पुरुषों से कई गुना ज़्यादा काम करके अपना परिवार चलाती हैं. यहां की महिलाएं कोई भी निर्णय अपने स्तर पर लेने में सक्षम एवं स्वतंत्र हैं. नगालैंड की महिलाएं दुर्गम पहाड़ों पर खेती का काम करती हैं. इन मेहनतकश महिलाओं पर घर-समाज की ओर से किसी तरह की पाबंदी नहीं होती. ये महिलाएं उतने ही बिंदास अंदाज में रहती हैं, जितने पुरुष. मिजोरम, जो अधिकतर पहाड़ पर बसा हुआ है, की महिलाएं अपने बच्चे को पीठ पर बैठाकर लकड़ी काटने जाती हैं, कटी हुई लकड़ी सिर पर लाद कर देर शाम अपने घर लौटती हैं, लेकिन परिवार में किसी को उनसे शिकायत नहीं रहती. त्रिपुरा में महिलाएं खेती-बाड़ी का ज़िम्मा खुद संभालती हैं, दुर्गम पहाड़ों पर चढ़ कर झरने से पानी लाती हैं. यह सिर्फ़ एक दिन की बात नहीं है, बल्कि यह जीवन का हिस्सा है. मणिपुर में महिलाएं झील से मछली पकड़ने के काम में घर के पुरुषों की मदद करती हैं. साक्षरता के मामले में भी पूर्वोत्तर की महिलाएं किसी से कम नहीं हैं. अगर पुरुषों का प्रतिशत 80 है, तो महिलाएं भी 70 फ़ीसद दर के साथ उनके क़दम से क़दम मिला रही हैं.

इतिहास गवाह है कि पूर्वोत्तर की महिलाओं ने विषम से विषम परिस्थितियों में मोर्चा संभाला है. 1904 और 1939 में हुए संघर्ष नुपी लाल में मणिपुर की महिलाओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया था. ब्रिटिश सरकार के अन्याय के ख़िलाफ़ महिलाओं ने कपड़ा बुनने में इस्तेमाल होने वाले लकड़ी के टुकड़े को अपना हथियार बनाया और पुरुषों से एक क़दम आगे बढ़कर मोर्चा संभाल लिया. आज भी हर साल 12 दिसंबर को उन महिलाओं को याद किया जाता है. नगा स्वतंत्रता सेनानी रानी गायदिनलू को भी लोग याद करते हैं. काफी लंबे समय तक वह जेल में रहीं. उन्होंने गांधी जी द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर 14 सालों तक आज़ादी की लड़ाई लड़ी.

पूर्वोत्तर की महिलाओं को स्वयं के महिला होने का कोई दु:ख नहीं होता, क्योंकि उन्हें घर और समाज का पर्याप्त संरक्षण हासिल है. माता-पिता बेटी-बेटे के बीच फर्क नहीं करते, कोई पक्षपात नहीं बरतते. जबकि उत्तर भारत में बेटी का जन्म होते ही बहुधा घर में मायूसी छा जाती है. वजह भी है. समाज में दहेज प्रथा आज भी खुशियों को ग्रहण लगा रही है. वहीं पूर्वोत्तर में अलग रिवाज है. वर पक्ष वधु के घर वालों को खुद दहेज देते हैं, जिससे वधु अपने पारंपरिक परिधान खरीदती है. बॉक्सिंग में पांच बार विश्व चैंपियन रहीं मैरी कॉम के जीवन पर आधारित एक फिल्म भी आ रही है. मैरी कॉम पूर्वोत्तर की महिलाओं का एक सशक्त रूप है. ग़रीब परिवार में पैदा होने के बावजूद खेल के क्षेत्र में उन्होंने देश का नाम रोशन किया. दो बच्चों की मां बनने के बाद वह विश्व चैंपियन बनीं. यह उनके लिए एक चुनौती थी. ■

sbijensngh@gmail.com

चौथी दुनिया
CHAUTHI DUNIYA
चौथी दुनिया की हर खबर अब आपके Android फोन पर भी उपलब्ध, Play Store से Download करें | CHAUTHI DUNIYA APP |

www.kamalmorarka.com

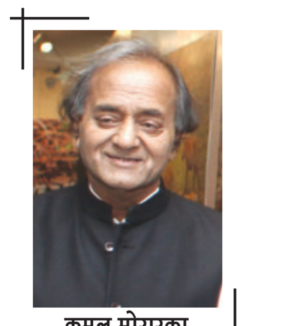

कमल मोरारका

भारतीय मीडिया का संकट काल

पत्रकारिता की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि पिछले दस सालों से कुछ समाचार पत्रों को छोड़कर अधिकांश समाचार पत्रों और टीवी चैनलों के मालिक व्यावसायिक घराने हो गए हैं. इसका परिणाम यह हुआ कि आज जो समाचार हमें मिलते हैं, वे पूंजीपतियों के लिए होते हैं, न कि आम आदमी या फिर समाज के निचले तबक़े के लोगों के लिए. उदाहरण के तौर पर वित्त मंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह के समय लाए गए आर्थिक सुधार को ले सकते हैं.

दुनिया के अन्य देशों की तरह भारत में भी पत्रकारिता साल दर साल परिवर्तित हुई है. अगर हम 1947 में देश को मिली आज़ादी के बाद पिछले 65 सालों की बात करें तो पत्रकारिता के क्षेत्र में बड़े परिवर्तन हुए हैं. 1995 के मध्य में सेटेलाइट टीवी हमारे देश में आया. उसके बाद से 24 घंटे चलाए जाने वाले समाचार चैनलों ने अपना एक ब्रांड बनाया है, जिसमें एक ही समाचार बार-बार दिखाया जाता है. यही नहीं, हंसी तो इस बात पर आती है कि अलग-अलग समाचार चैनल अलग-अलग समाचार दोहराते रहते हैं. टीवी चैनलों के आ जाने से समाचार पत्रों पर उनका प्रभाव पड़ा है. समाचार पत्र बहुत ज़्यादा समाचार नहीं दे पाते हैं, क्योंकि एक दिन पहले ही हम टेलीविजन पर समाचार देख लेते हैं, लेकिन समाचार पत्रों की महत्ता इस बात के लिए है कि हम उनमें न केवल रोज़मर्रा के समाचार पाते हैं, बल्कि उसके साथ किसी मुद्दे पर विभिन्न लोगों के विचार भी हमें पढ़ने को मिलते हैं. समाचार पत्रों में जो रोज़ के समाचार दिए जाते हैं, उन्हें ग़लत तरीक़े से पेश नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे समाचार लोग टीवी पर पहले ही देख लेते हैं.

पत्रकारिता की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि पिछले दस सालों से कुछ समाचार पत्रों को छोड़कर अधिकांश समाचार पत्रों और टीवी चैनलों के मालिक व्यावसायिक घराने हो गए हैं. इसका परिणाम यह हुआ कि आज जो समाचार हमें मिलते हैं, वे पूंजीपतियों के लिए होते हैं, न कि आम आदमी या फिर समाज के निचले तबक़े के लोगों के लिए. उदाहरण के तौर पर वित्त मंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह के समय लाए गए आर्थिक सुधार को ले सकते हैं. मुझे विश्वास है कि किसी भी अन्य नीति की तरह इसके भी दो पक्ष हैं. यही वजह है कि कुछ लोग किसी नीति का समर्थन करेंगे और कुछ लोग विरोध. लेकिन सोचने वाली बात यह है कि 1991 के बाद सभी समाचार पत्र और टीवी चैनल इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि आर्थिक सुधार ही भारत की सभी समस्याओं का अंतिम समाधान है. यही कारण है कि 21 वर्षों के बाद लोग यह कहते नज़र आ रहे हैं कि बहुत विकास हुआ है, लेकिन तथ्य कुछ और हैं. यह विकास 1991 के पहले शुरू हुआ.

अगर आप प्रत्येक पांच साल का औसत निकालेंगे तो पाएंगे कि परिणाम मिश्रित रहा है. कभी विकास की गति तेज़ रही तो कभी काफ़ी धीमी. पिछले तीन-चार सालों की बात करें तो विकास दर नीचे गिर रही है. इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि विकास दर का संबंध केवल आर्थिक नीति से है. इसके कई अन्य कारण भी हैं. उदाहरण के तौर पर इस समय अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं, इसलिए विकास दर धीमी रही है. इसके लिए किसी विशेष आर्थिक नीति को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता. मतलब यह है कि मीडिया को वस्तुनिष्ठ होना चाहिए. आजकल मीडिया की निर्भरता कॉरपोरेट क्षेत्र पर अत्यधिक बढ़ गई है. किसी भी स्थिति में मीडिया विज्ञापनों के लिए कॉरपोरेट क्षेत्र पर निर्भर रहता है, लेकिन पहले और आजकल की स्थिति में परिवर्तन आ गया है. पहले समाचार पत्रों के प्रसार और लोगों तक उनकी पहुंच के आधार पर विज्ञापन दिए जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है. आजकल बड़े-बड़े औद्योगिक घराने शीर्ष के समाचार पत्रों को विज्ञापन नहीं देते, क्योंकि वे उनके खिलाफ़ लिखते हैं. मेरी जानकारी के अनुसार, किसी अन्य देश में ऐसा नहीं होता है.

भारत में 1970 के दशक में इंदिरा गांधी डिफ्यूजन ऑफ प्रेस ऑनरशिप एक्ट नाम से एक विधेयक लाई थीं. यह विधेयक संसद में पेश तो हुआ, लेकिन पारित नहीं हुआ और कानून नहीं बन पाया. इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य यह था कि जो व्यक्ति समाचार पत्र का मालिक है, वह किसी दूसरे उद्योग का मालिक नहीं हो सकता और जो किसी दूसरे उद्योग का मालिक है, वह समाचार पत्र नहीं निकाल सकता है. औद्योगिक घरानों ने इसका विरोध किया और कहा कि यह प्रेस की स्वतंत्रता पर आक्रमण है, जबकि वास्तविकता यह नहीं थी. आज प्रेस के ऊपर हमला किसी तानाशाह द्वारा नहीं, बल्कि धन कुबेरों द्वारा किया जा रहा है. प्रेस को समाप्त करने के दो तरीक़े होते हैं. पहला यह है कि समाचार पत्र को प्रकाशित ही न होने दिया जाए. यह तरीक़ा तानाशाही वाले देशों में अपनाया जाता है. दूसरा तरीक़ा यह है

भारत में 1970 के दशक में इंदिरा गांधी डिफ्यूजन ऑफ प्रेस ऑनरशिप एक्ट नाम से एक विधेयक लाई थीं. यह विधेयक संसद में पेश तो हुआ, लेकिन पारित नहीं हुआ और कानून नहीं बन पाया. इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य यह था कि जो व्यक्ति समाचार पत्र का मालिक है, वह किसी दूसरे उद्योग का मालिक नहीं हो सकता और जो किसी दूसरे उद्योग का मालिक है, वह समाचार पत्र नहीं निकाल सकता है.

कि प्रेस को पैसे से खरीद लो, ताकि वह सही विचार ही प्रस्तुत न कर सके. भारत में यही दूसरा तरीक़ा अपनाया जाता है. आजकल अगर कोई ग़रीबों, अल्पसंख्यकों, बेरोज़गारों एवं अनुसूचित जाति के लिए आवाज़ उठाता है, तो उसे मीडिया समाचार नहीं बनाता है.

मुझे याद है कि जब मैं स्कूल और कॉलेज में था तो समाचार पत्र के संपादक और मालिक के बीच टकराहट होती रहती थी. हिंदुस्तान टाइम्स के मालिक बिड़ला थे और संपादक एस मुलगांवकर थे, टाइम्स ऑफ इंडिया के मालिक डालमिया एवं जैन थे और संपादक फ्रैंक मोरेस थे या फिर इंडियन एक्सप्रेस के मालिक राम नाथ गोयनका थे, जो अलग तरह के थे. उस समय बात कुछ और थी, लेकिन आज अधिकांश संपादक अपनी सुविधा का ख्याल पहले रखते हैं. अब यह बहुत कठिन सवाल है कि इस विकासशील समाज में हम इसे कैसे रोक सकते हैं. मैं सोचता हूं कि एक ऐसा क़ानून होना चाहिए, जिसके द्वारा इसे रोका जा सके. डिफ्यूजन ऑफ प्रेस ऑनरशिप एक्ट इसे रोकने का एक रास्ता हो सकता है.

इसके अलावा भी रास्ता हो सकता है. पत्रकार यह तर्क देते हैं कि निरक्षर लोग संसद में जा रहे हैं. संसद लोगों का प्रतिनिधित्व करती है. मान लें, आप कहते हैं कि सांसद बनने के लिए स्नातक की डिग्री ज़रूरी हो. इसका मतलब यह है कि आप ज्यादातर लोगों को इससे अलग कर रहे हैं, क्योंकि भारत के अधिकांश लोग ग्रेजुएट नहीं हैं. मज़ाक़ की बात तो यह है कि पत्रकार सांसद के लिए योग्यता निर्धारित करने की मांग करते हैं, लेकिन अपने लिए नहीं. मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जो हिंदी या अंग्रेजी तो जानते हैं, लेकिन और कुछ नहीं के बराबर जानते हैं. आजकल के युवा पत्रकार यह ज़हमत नहीं उठाते कि पुस्तकालय में जाएं और इस बात की जानकारी लें कि जवाहर लाल नेहरू के समय में क्या हुआ था या फिर जब इंदिरा गांधी या लाल बहादुर शास्त्री सदन में थे तो क्या हुआ था. इसलिए भारत के पत्रकारों के स्तर में सुधार के लिए कुछ करने की आवश्यकता है. कैसे किया जाए, यह एक कठिन सवाल है.

सबसे पहले समस्या का अनुभव करना ज़रूरी है, उसके बाद ही उसका समाधान हो सकता है. आज भारतीय मीडिया के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह संकट के दौर से गुज़र रहा है. अधिकांश समाचार पत्र कॉरपोरेट हाउसों के लिए काम कर रहे हैं. छोटे समाचार पत्रों को दबा दिया जाता है, क्योंकि वे विज्ञापन नहीं ले पाते हैं. इसलिए सरकार को इन छोटे समाचार पत्रों के लिए ज़रूर कुछ करना चाहिए, ताकि ये अपने पैरों पर खड़े हो सकें. या फिर डिफ्यूजन ऑफ प्रेस ऑनरशिप एक्ट जैसा क़ानून लाना चाहिए. क्या करना चाहिए, यह मैं नहीं जानता. मैं इसे बहस का एक मुद्दा बनाना चाहूंगा.■

feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ पूरे देश को लड़ना होगा

दस सालों के बाद भारत के प्रधानमंत्री को लोगों के बीच भाषण करते देखना सुखद लगता है और खासकर तब, जब प्रधानमंत्री भारत की सबसे बड़ी समस्या बिजली की समस्या पर चिंता व्यक्त करें और साथ ही यह आशा दिलाएं कि अगले कुछ सालों में देश में बिजली उपलब्ध हो जाएगी और शहरों ही नहीं, गांवों को भी 24 घंटे बिजली मिलेगी. बिजली विकास की सबसे बड़ी आधारशिला है. बिजली अगर सबसे बड़ी आधारशिला है, तो उसका उत्पादन होगा कैसे और वह सर्वसुलभ होगी कैसे? प्रधानमंत्री भी इस बात से अनजान नहीं हैं कि देश में कोयले का भंडार खर्च करने की जगह उसे बचाना ज़रूरी है और बिजली के लिए पानी उपलब्ध है नहीं.

अभी तक यही दो ज्ञात स्रोत बिजली के रहे हैं और जिस बात की तरफ़ उन्होंने इशारा किया, वह है सौर ऊर्जा यानी सूरज की रौशनी से बिजली का उत्पादन. यह तकनीक महंगी है, लेकिन इसके अलावा देश के पास कोई चारा नहीं है. जब प्रधानमंत्री ने यह कहा कि हर घर को अपने लिए बिजली का उत्पादन करना चाहिए, तो उनके इस वाक्य की सराहना भी होनी चाहिए और इस पर अमल भी होना चाहिए. हर घर में सौर ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए सौर पैनल लगाने पड़ेंगे, लेकिन उनकी क़ीमतों में जिस प्रकार से बढ़ोतरी होने जा रही है, वह यह बताता है कि प्रधानमंत्री की कही हुई इस योजना को पलीता लगाने की कोशिश होने वाली है.

वे सारे लोग, जो सरकार के किसी भी वक्तव्य में मुनाफा देखते हैं, अचानक सक्रिय हो गए हैं और सौर पैनलों का निर्माण करने वाले लोगों के बीच आपस में एक गठबंधन हो गया है. अगर प्रधानमंत्री ने तत्काल यह फ़ैसला नहीं लिया कि घरों के लिए इस्तेमाल होने वाले सौर पैनलों की क़ीमत एक सीमा से आगे नहीं बढ़ेगी, तो फिर प्रधानमंत्री का यह वाक्य कि हर घर अपने लिए सौर ऊर्जा का उत्पादन करे, मुनाफाखोरों के लिए एक नया रास्ता खोलने वाला क़दम साबित हो सकता है. अभी तक प्रधानमंत्री की ओर से ऐसी कोई घोषणा सामने नहीं आई है. आशा करनी चाहिए कि प्रधानमंत्री तत्काल इस तरह की घोषणा करेंगे, ताकि सौर ऊर्जा पैनलों का निर्माण करने वाली कंपनियां इस देश को मुनाफाखोरी के जाल में नए सिरे से धकेलने में कामयाब न होने पाएं.

प्रधानमंत्री को यह भी फ़ैसला लेना होगा कि जो कंपनी चाहे, वह इस देश में एक मेगावाट से लेकर 500 मेगावाट तक का सौर ऊर्जा निर्माण संयंत्र कहीं भी लगा सकती है. लगाने का स्थान ग्रिड के क़रीब हो और उसकी अनुमति उसे 5 से 7 दिन में मिल जाए. इसके लिए आवश्यक है कि एक पूर्णकालिक मंत्रालय का गठन इस ज़िम्मेदारी के साथ हो कि अगले साल भर में इस देश में कम से कम एक लाख से दो लाख मेगावाट सौर ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य रखकर उसे पूरा भी किया जाए. मैं देश के लोगों के सामने यह साफ़ कर दूं कि सौर ऊर्जा के निर्माण में 8 महीने से ज़्यादा समय नहीं लगता और यही बात नरेंद्र मोदी को सौर ऊर्जा के काम में लगने वाले मंत्री और अधिकारियों को समझानी होगी तथा उनके सामने सिर्फ़ आठ महीने का लक्ष्य रखना होगा कि वे आठ महीने में किस तरह सौर ऊर्जा का उत्पादन करते हैं. और, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ़ सौर ऊर्जा को ही अगले बजट से पहले का अपना लक्ष्य मान लें, तो वह इस देश के लिए विकास का नया मार्ग खोलने में सक्षम हो पाएंगे और उनके ऊपर लोग भरोसा करेंगे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक वाक्य भ्रष्टाचार की मुखालफत के रूप में कहते हैं कि यह समाप्त होना चाहिए, लेकिन यह नहीं कहते कि जो भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ खड़ा होगा, वह देश के लिए खड़ा होगा और उसका साथ सरकार हर क़ीमत पर देगी. भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ लड़ने वालों का साथ सरकार कैसे देगी, यह भी प्रधानमंत्री को साफ़ करना होगा. साथ ही प्रधानमंत्री को देश के गांवों में रहने वाले लोगों का आह्वान करना होगा कि वे भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ खड़े हों. दरअसल, पिछले दस सालों में ही नहीं, बल्कि पिछले कई सालों में जितनी भी योजनाएं बनीं, वे सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गईं और जो सबसे कुरूप पहलू सामने आया है, वह यह कि देश के गांवों की पंचायतें इस भ्रष्टाचार का हिस्सा बन गई हैं.

मैं दक्षिण भारत की बात नहीं करता, लेकिन उत्तर भारत में ज़्यादातर ग्राम पंचायतें भ्रष्टाचारी तंत्र का आख़िरी हिस्सा बनी हुई हैं. इस भ्रष्टाचार को रोकने में सिर्फ़ और सिर्फ़ गांव के लोग ही अपनी इच्छा शक्ति भी दिखा सकते हैं और इसे रोक भी सकते हैं. अब यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या देश की सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि वह भ्रष्टाचार का विरोध करने वालों का साथ देते हैं या भ्रष्टाचार का विरोध करने के नाम पर भ्रष्टाचारियों का साथ देते हैं. लोगों को यह नहीं लगना चाहिए कि सरकार कहती तो भ्रष्टाचार का विरोध है, लेकिन साथ भ्रष्टाचार करने वालों का देती है.

क्यों नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के गांवों में रहने वाले नौजवानों का, किसानों का आह्वान करते हैं कि वे गांव में चलने वाली सारी योजनाओं के ऊपर नज़र रखें और कहीं पर भ्रष्टाचार होता हुआ देखें, तो उसका तत्काल विरोध भी करें और सरकार को उसकी जानकारी भी दें. हो सकता है कि कई जगहों पर लोग दुश्मनी निकालने के लिए गलत शिकायतें भी करें. वहां पर सरकार को उन शिकायतों की जांच करने वालों को भरोसा दिलाना होगा कि अगर वह सही जांच करेंगे, तो उन्हें उसका उचित पुरस्कार मिलेगा. एक संपूर्ण योजना गांवों में चल रही योजनाओं के भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए सरकार को जल्दी से जल्दी लानी होगी, अन्यथा उसकी बात एक होगी और उसकी करनी दूसरी होगी.

विद्युत क्षेत्र में 30 से 40 प्रतिशत की चोरी होती है. यह चोरी बड़े पूंजीपति भी करते हैं, यह चोरी शहरों में भी होती है, यह चोरी गांवों में भी होती है और यह सब बिजली तंत्र का काम देख रहे सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से होता है. इस चोरी को रोकने के लिए जन-जागरण भी ज़रूरी है और जन-अभिक्रम भी ज़रूरी है. हालांकि, विद्युत राज्यों का विषय है, लेकिन केंद्र सरकार को राज्य सरकारों को मोटिवेट करके इस बिजली चोरी को रोकने की दिशा में सख्त क़दम उठाना चाहिए. दरअसल कुछ विषय ऐसे हैं, जिनमें कहीं राजनीति होनी ही नहीं चाहिए. जैसे कि बुनियादी ढांचे का निर्माण, जिसका पहला क़दम विद्युत उत्पादन, विद्युत वितरण और विद्युत चोरी है. ये किसी राजनीतिक बहस के दायरे में नहीं आते, ये शुद्ध और शुद्ध भ्रष्टाचार हैं. इस भ्रष्टाचार का विरोध हर पार्टी को करना चाहिए.

प्रधानमंत्री समझदार हैं, लेकिन जब आप देश के सारे लोगों को अपने अभियान में शामिल करना चाहते हैं, तो आपको देश के साधारण से साधारण आदमी की बात में भी निहितार्थ तलाशने चाहिए. लोग अपनी समस्याओं के फौरन निदान की बात नहीं कर रहे. वे पिछले पैंसठ सालों से अपनी समस्याओं के निदान का रास्ता देख रहे हैं, जो उन्हें कहीं नज़र नहीं आ रहा. हर बार विकास के नाम पर उन्हें भ्रष्टाचार मिलता है और सामान्य गति से हुए काम उनके सामने उपलब्धियों के रूप में रखे जाते हैं. इसीलिए जब कोई प्रधानमंत्री कहता है कि हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, तो इसका मतलब वह भी लोगों को एक नए सिरे से भटकाने का रास्ता तलाश रहा है. यह हर्ष की बात है कि अभी तक यह वाक्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से नहीं निकला है. लेकिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वाक्य तो कहा है कि 60 सालों तक राज करने वाले 60 दिनों का भी हनीमून टाइम नहीं दे रहे हैं और आलोचना कर रहे हैं.

यह वाक्य कि 60 दिनों में कुछ नहीं हो सकता, उस वाक्य की पूर्व भूमिका बन सकता है, अगर प्रधानमंत्री ने सावधानी नहीं बरती कि हमारे हाथ में कोई जादू की छड़ी नहीं है, जिससे हम रातोरात देश का कायाकल्प कर दें. इस देश की जनता तो पीढ़ियों से यही वाक्य सुनती आई है और देश का 70 प्रतिशत से ज़्यादा हिस्सा लगभग नर्क में जीता आया है. इसलिए जब कोई नई सरकार आती है, तो लोगों के मन की इच्छाएं, आकांक्षाएं नए सपने देखने लगती हैं और उन सपनों को पूरा होने के लिए पांच साल की बात कही जाती है. और, फिर पांच साल के बाद यह कहा जाता है कि वे सपने क्यों नहीं पूरे हो पाए. यह वाक्य इस देश में उन ताकतों को मजबूत करता है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के ख़िलाफ़ एक नई व्यवस्था खड़ा करना चाहती हैं.

इसलिए पहली आशा प्रधानमंत्री से यही है कि वह भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ खड़े होने के लिए गांव के लोगों का आह्वान करें और यह भरोसा दिलाएं कि जो भ्रष्टाचार का विरोध करेगा, उसका साथ सरकार देगी और किस रूप में देगी, यह स्पष्ट करें. सौर ऊर्जा के निर्माण में लगने वाली कंपनियों की मुनाफाखोरी, गांवों में फैले पंचायतों के भ्रष्टाचार और विशेषकर बिजली चोरी जैसे मामलों के ख़िलाफ़ खड़े होने का आह्वान करना आज की पहली आवश्यकता है और आशा करनी चाहिए कि प्रधानमंत्री इन समस्याओं को समझ कर इनके ख़िलाफ़ खड़े होने के लिए लोगों का आह्वान करेंगे और जो खड़ा होगा, उसका साथ भी देंगे.■

editor@chauthiduniya.com

एक पीढ़ी, जो न बहकी और न बिकी

उत्तर प्रदेश की डाकू या दस्यु समस्या भी रविवार का मुख्य विषय बन गई थी. हमेशा दस्यु जीवन इस देश के लोगों में उत्सुकता जगाता रहता था या कहें कि आज भी जगाता रहता है. दस्यु प्रभावित क्षेत्रों का समाज, वहां के तनाव, वहां की समस्याएं, वहां के रिश्ते, वहां का दमन तथा वहां का इतिहास, भूगोल रविवार का प्रिय विषय रहा. हमने डाकुओं के बारे में कभी अपराध कथा का दृष्टिकोण नहीं अपनाया, शायद इसीलिए हमारी लिखी रिपोर्ट सारी दुनिया में छपी. ऐसी ही एक रिपोर्ट फूलन देवी-विक्रम मल्लाह के बारे में थी. इस कवर स्टोरी को करने के लिए मुझे बीस दिन से ज़्यादा बीहड़ों में रहना पड़ा. डाकुओं से संपर्क जुड़ता था, फिर टूट जाता था. जाने कितने लोगों ने मुझे चेताया था कि फूलन बहुत घटिया डाकू है. अगर मिले, तो वह बंधक बनाकर रख सकती है. संपर्क ने भी बहुत हतोत्साहित किया था, लेकिन जब मैं तेइसवें दिन फूलन से जंगल में मिला, तो मुझे मिली एक दुबली-पतली काली-सी लड़की, पैंट-शर्ट पहने, जो कम से कम दस्यु सुंदरी तो नहीं ही लगती थी.

फूलन के पास ख़बर थी कि मैं उसके गांव जा चुका हूं, उसके मां-बाप व छोटी बहन और भाई से मिल चुका हूं. उससे आत्मीयता जल्दी ही बढ़ गई तथा उसने वह सब बताया, जो रविवार में छपा और जिसे सारी दुनिया ने रविवार से अनुवाद किया. कई पत्रकारों ने तो अपनी कल्पना की घोड़ी दौड़ाई तथा उसी कवर स्टोरी में मिर्च मिलाई और अपने नाम से अंग्रेजी व हिंदी की पत्रिकाओं में छापी. मेरा इस तरह की पत्रकारिता का यह पहला अनुभव था, जिसने मुझे बहुत दुखी किया था. तब एसपी ने समझाया था कि हमारी दुनिया ही ऐसी है, जिसमें अक्सर मेहनत कोई और करता है और खाता कोई और है. मैं अपने पूरे पत्रकारिता काल में अब तक उस तकलीफ को भूल नहीं पाया हूं. इसीलिए मैंने किसी भी नए व्यक्ति की रिपोर्ट का श्रेय किसी दूसरे को लूटने नहीं दिया.

उन दिनों रविवार के संपादक को किसी भी घटना की जानकारी मिलती थी, तो पहली कोशिश उनकी यह होती थी कि कैसे वह सबसे पहले अपने पत्रकारों को घटनास्थल पर भेजें. उन दिनों पत्रकारों में होड़ मचती थी कि कौन पर्दे के पीछे की कहानी सबसे पहले लेकर सामने आए. दैनिक अख़बारों में रिपोर्ट छपने के बाद भी हमारी लिखी रिपोर्ट अलग ही जानकारी पाठकों को देती थी. जितने प्रमुख राजनीतिक विषय होते थे, उतने ही सामाजिक विषय भी होते थे. फील्ड रिपोर्ट यानी घटनास्थल से रिपोर्ट. जो घटनास्थल पर जाकर रिपोर्ट नहीं लिखता था, वह हिकारत की नज़र से देखा जाता था. घटनास्थल पर जाने में उदयन शर्मा व मुझमें होड़ लगी रहती थी. वह वरिष्ठ थे, अक्सर जीत जाते थे. उनकी रिपोर्ट अकेले उनके नाम से छपती थी. लेकिन कभी-कभी दोनों को एक ही रिपोर्ट का अलग-अलग हिस्सा लिखने का मौक़ा मिल जाता था. उनके साथ छपी मेरी कुछ ही रिपोर्ट हैं, लेकिन वे मेरी सुखद यादें हैं. उदयन विषय उड़ाने में उस्ताद थे. एक बार मैं झगड़ गया, तब उन्होंने मुझे सीख दी कि हमारी दुनिया में हर कोई दूसरे का मांस नोचकर खाता है. जब एसपी को मैंने उदयन की बात बताई, तो उनका कहना था कि इससे यह सीख लो कि अपना मांस दूसरे को मत खाने दो. विषय को, विषय वस्तु को तथा क्या लिखना चाहते हो, छुपाकर रखो. अति उत्साह में सब कुछ उजागर मत कर दो. एसपी इसी तरह संपादकीय गुर सिखाया करते थे.

फूलन के पास ख़बर थी कि मैं उसके गांव जा चुका हूं, उसके मां-बाप व छोटी बहन और भाई से मिल चुका हूं. उससे आत्मीयता जल्दी ही बढ़ गई तथा उसने वह सब बताया, जो रविवार में छपा और जिसे सारी दुनिया ने रविवार से अनुवाद किया. कई पत्रकारों ने तो अपनी कल्पना की घोड़ी दौड़ाई तथा उसी कवर स्टोरी में मिर्च मिलाई और अपने नाम से अंग्रेजी व हिंदी की पत्रिकाओं में छापी. मेरा इस तरह की पत्रकारिता का यह पहला अनुभव था, जिसने मुझे बहुत दुखी किया था. तब एसपी ने समझाया था कि हमारी दुनिया ही ऐसी है, जिसमें अक्सर मेहनत कोई और करता है और खाता कोई और है.

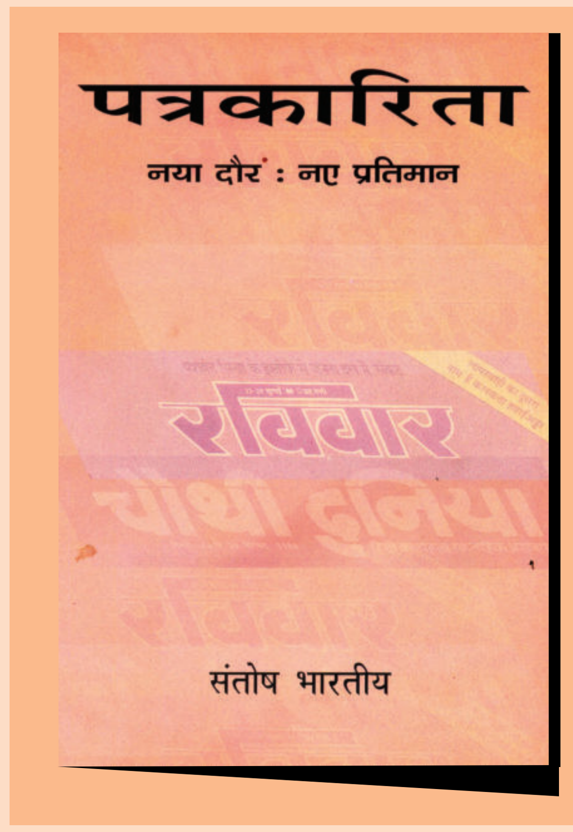

आज पत्रकारिता के मायने बदल गए हैं, बदल रहे हैं अथवा बदल दिए गए हैं, नतीजतन, उन पत्रकारों के सामने भटकाव जैसी स्थिति आ गई है, जो पत्रकारिता को मनसा-वाचा-कर्मणा अपना धर्म-कर्तव्य और कमज़ोर-बेसहारा लोगों की आवाज़ उठाने का माध्यम मानकर इस क्षेत्र में आए और हमेशा मानते रहे. और, वे नवांकुर तो और भी ज़्यादा असमंजस में हैं, जो पत्रकारिता की दुनिया में सोचकर कुछ आए थे और देख कुछ और रहे हैं. ऐसे में, 2005 में प्रकाशित संतोष भारतीय की पुस्तक-पत्रकारिता: नया दौर, नए प्रतिमान हमारा मार्गदर्शन करती और बताती है कि हमारे समक्ष क्या चुनौतियां हैं और हमें उनका सामना किस तरह करना चाहिए. चार दशक से भी ज़्यादा समय हिंदी पत्रकारिता को समर्पित करने वाले संतोष भारतीय देश के उन पत्रकारों में शुमार किए जाते हैं, जो देश और समाज से जुड़े प्रत्येक मुद्दे पर निर्भीक, सटीक, निष्पक्ष टिप्पणी करते हैं.

यह वह दौर था, जिसने कुछ को सामान्य पत्रकारों की श्रेणी से निकाल कर विशिष्ट श्रेणी में पहुंचा दिया था. जो विशिष्ट श्रेणी में पहुंचे, वे हमेशा फील्ड में रहते थे तथा फील्ड रिपोर्ट की तलाश में दिन-रात एक किए रहते थे. बस, ट्रेन, कार, टैक्सी या लिफ्ट मांगकर किसी भी तरह घटनास्थल तक पहुंचना सबसे बड़ा उद्देश्य रहता था. अच्छे संपादक चौबीसों घंटे उनसे फोन संपर्क में रहते थे. उन दिनों मोबाइल व फैक्स नहीं था, फिर भी संपादक अपने रिपोर्टर की पहुंच से दूर नहीं होते थे. उन दिनों कल्याण मुखर्जी खुशवंत सिंह के संपादन में निकलने वाली पत्रिका न्यू देहली के विशेष संवाददाता थे. एसपी का संदेश आया कि कल्याण की मदद करो. कल्याण को मैं मोटर साइकिल पर बैठाकर फूलन के गांव गढ़ा का पुरवा ले गया. कच्ची पगडंडी पर कई बार हम दोनों गिरे. मोटर साइकिल मैंने कानपुर के एक दोस्त से मांगी थी, क्योंकि उन दिनों फूलन के गांव तक जीप से भी आसानी से नहीं पहुंचा जा सकता था. बाद में किसी जीप से गढ़ा का पुरवा एमजे व एसपी भी गए. फूलन का गांव चंबल में बीहड़ों के किनारे था.

अधिकांश ज़िलों के पत्रकार बहुत ही अपनेपन से बाहर से आए पत्रकारों की हर तरह की मदद करते थे. रविवार का नाम लेकर कोई भी चला जाए, उसे उत्तर भारत के किसी भी ज़िले में कोई भी परेशानी नहीं होती थी. कानपुर उन दिनों एक बहुत बड़े केंद्र के रूप में उभरा था. उन दिनों वहां आज अख़बार के संपादक विनोद शुक्ल थे. उन्होंने व आज के ही तत्कालीन संवाददाता दिलीप शुक्ल ने बाहर से गए पत्रकारों की काफी मदद की थी. ये दोनों नाम केवल उदाहरण के लिए ही लिख रहा हूं, क्योंकि यह सूची काफी लंबी है. लेकिन उस दौर की सच्चाई यह थी कि पत्रकार बेख़ौफ होकर लिखते थे, इसके लिए उनके पास कम से कम रविवार उपलब्ध था. मैं साफ़ करना चाहता हूं कि मैं यहां रविवार की तारीफ़ नहीं लिख रहा हूं, बल्कि उस समय की सच्चाई लिख रहा हूं कि किस तरह रविवार ने एक पूरी पीढ़ी तैयार कर दी, जो व्यवस्था विरोध के आधार पर अपना क़दम तय करती थी तथा जिसे खरीदने या बहकाने की कोशिश लगभग बेकार हो जाती थी.■

feedback@chauthiduniya.com

मेघनाद देसाई

ख़तरे में पाकिस्तान का लोकतंत्र

तालिबान के साथ कई साल तक अनिश्चितता के संबंधों में रहने के बाद पाकिस्तान ने आख़िरकार यह फ़ैसला किया है कि तालिबान उसका दोस्त नहीं है, बल्कि वह सत्ता का दावेदार बनना चाहता है. तालिबान दोस्ती नहीं चाहता, बल्कि सत्ता में भागीदारी चाहता है, जैसा कि उसने अफ़गानिस्तान में किया था. तालिबान पूरी तरह एक इस्लामिक मूवमेंट है. वह इस बात में दिलचस्पी रखता है कि जिन देशों में इस्लामिक बहुलता है, वहां सत्ता हासिल की जाए.

जब आज़ादी का समय आया, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान को भारत से एक दिन पहले आज़ाद किया जाना चाहिए. वजह यह कि वह दोनों ही समारोहों में मौजूद रहना चाहते थे. दोनों देशों को उनके इस अभिमान की क़ीमत चुकानी पड़ी. दोनों देश शुरुआत में यह बात नहीं समझ पाए कि आख़िर धर्म आधारित विभाजन करने का मतलब क्या है? मुहम्मद अली जिन्ना यह सोचते थे कि विभाजन के बाद भी वह अपनी छुट्टियां मालाबर स्थित अपने घर पर मना सकेंगे. जवाहर लाल नेहरू यह सोचते थे कि पाकिस्तान ज़्यादा दिनों तक बना नहीं रह सकेगा और आख़िरकार भारत में आकर वापस मिल जाएगा. आज़ादी के 67 सालों बाद विश्व के मुस्लिम बहुमत वाले देशों में सबसे बड़ा लोकतंत्र पाकिस्तान इस समय मुश्किलों के दौर से गुजर रहा है. हो सकता है कि यह क्षणिक हो, जो महत्वाकांक्षी एवं अधैर्यवान इमरान खान जैसे नेता द्वारा लाया गया हो. लेकिन, जबसे उनकी पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ द्वारा इस्लामाबाद के लिए रैली की जा रही है, यह मामला गंभीर होता जा रहा है. इस मसले को अवामी तहरीक के नेता डॉ. ताहिर उल कादरी और भी गंभीर बना रहे हैं.

प्रत्यक्ष रूप से आरोप यही है कि 2013 के चुनाव में धांधली की गई थी, लेकिन असली सवाल यह है कि अगर यही आरोप लगाना था, तो इतने लंबे समय तक इंतजार क्यों किया गया? अगर उसी समय क़दम उठाया गया होता, तो शायद मामला इतना गंभीर नहीं होता, जितना आज हो गया है. पाकिस्तान की वास्तविक परेशानी उसके उत्तर-पश्चिम हिस्से में तालिबान है. बीते सालों के दौरान पाकिस्तान की सरकार का अमेरिका के प्रति रवैया बदल गया है. एक बार तालिबान के ऊपर ड्रोन हमलों के बारे में कहा गया कि यह स्वागत योग्य नहीं है. पाकिस्तानी सत्ता ने इसे अपनी संप्रभुता में हस्तक्षेप माना. तालिबान के साथ समझौते के प्रयास भी किए गए. इमरान खान इस क़दम में सक्रिय थे. अब इस समय पाकिस्तान सरकार चाहती है कि अमेरिका पाक सेना के तालिबान के ख़िलाफ़ चल रहे ऑपरेशन में ड्रोन हमलों के जरिए मदद करे.

तालिबान के साथ कई साल तक अनिश्चितता के संबंधों में रहने के बाद पाकिस्तान ने आख़िरकार यह फ़ैसला किया है कि तालिबान उसका दोस्त नहीं है, बल्कि वह सत्ता का दावेदार बनना चाहता है. तालिबान दोस्ती नहीं चाहता, बल्कि सत्ता में भागीदारी चाहता है, जैसा कि उसने अफगानिस्तान में किया था. तालिबान पूरी तरह एक इस्लामिक मूवमेंट है. वह इस बात में दिलचस्पी रखता है कि जिन देशों में इस्लामिक बहुलता है, वहां सत्ता हासिल की जाए. वह साधारण राजनीति समाप्त कर अपनी आतंकी गतिविधियों से दुनिया को डराकर रखना चाहता है. इस वजह से सिर्फ़ पाकिस्तान परेशानी में नहीं है, बल्कि लगभग पूरे इस्लामिक जगत में ऐसी परेशानी चल रही है कि इन इस्लामिक चरमपंथियों की वजह से मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है.

इस्लाम में विभेद की प्रक्रिया को वहाबी मूवमेंट से तेजी मिली, जिसे हवा दी सऊदी अरब ने. अब यह परेशानी कैंसर बनती जा रही है. बीते चालीस सालों के दौरान उसने देश के बाद देश बर्बाद किए हैं. इसके लिए आपको एक बार आईएसआईएस के आतंकियों की तरफ़ देखना होगा, जो यजिदियों और शियाओं के सिर कलम कर रहे हैं. सीरिया में तीन सालों से सिविल वार चल रहा है, इराक में सत्ता समाप्त हो चुकी है, मिस्र में सेना की वापसी हो गई है, लीबिया में अराजकता है. नाइजीरिया एवं केन्या में बोको हराम मजबूत हो रहा है. निष्कर्ष स्वरूप यह कहा जा सकता है कि मुसलमानों को अपने धर्म वालों से जितना ख़तरा है, उतना किसी और से नहीं है.

अगर तालिबान को मजबूत होने का मौक़ा मिलेगा, तो पाकिस्तान बहुत भीषण धार्मिक ख़तरे की ओर है, वहीं शिया भी किनारे लगा दिए जाएंगे. पश्चिमी देश भी अब हस्तक्षेप करने से बाज आ रहे हैं. उन्होंने सीरिया के मामले में भी हस्तक्षेप नहीं किया, जब आईएसआईएस ने ख़लीफ़ा घोषित करने की बात की. अब जबकि याजिदियों का नरसंहार किया जा रहा है, तो ये देश हस्तक्षेप कर रहे हैं. इसे पाखंडपूर्ण भी कहा जा सकता है, क्योंकि इन्हीं पश्चिमी देशों ने सीरिया में आम नागरिकों के लगातार मारे जाने के बावजूद इस तरह का हस्तक्षेप नहीं किया था. लेकिन 9/11 की घटना के बाद पश्चिमी देशों के मुसलमानों के प्रति व्यवहार में परिवर्तन आया है. यह गलत हो सकता है, लेकिन अविवादित नहीं. पूरी संभावना है कि इन सबके बावजूद पाकिस्तान सुरक्षित बचा रहेगा. कमजोर राजनीतिक नेतृत्व के बावजूद उसके पास एक मजबूत सिविल सोसायटी है. देश में लोकतंत्र कमजोर पड़ चुका था. अब जबकि एक बार यह फिर मजबूत हो रहा है, तो इसे मदद की ज़रूरत है. असल सवाल यह है कि आख़िर अपने लोगों के मारे जाने के बावजूद मुस्लिम दुनिया उन्हें बचाने क्यों नहीं आ रही है? आख़िर क्यों बड़े स्तर पर सिविल सोसायटी के लोग इसके ख़िलाफ़ प्रदर्शन नहीं करते? क्या लोग सिर्फ़ अमेरिका की गलतियों पर ही ऐसे आंदोलन करते हैं?■

feedback@chauthiduniya.com

अग्नयाशय का कैंसर

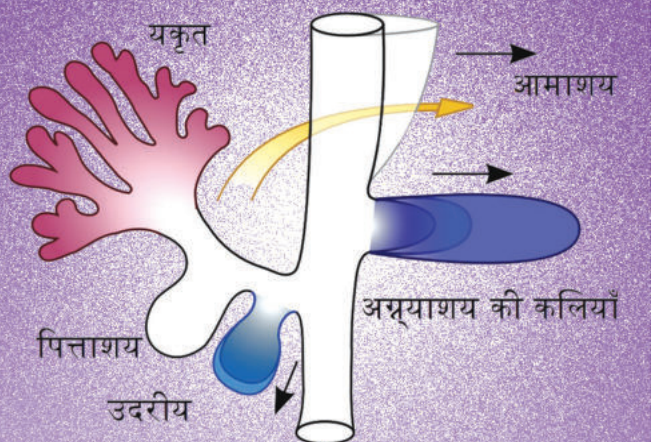

नवीन चौहान

अग्नयाशय(पैन्क्रियस) पेट के पीछे और छोटी आंत (छोटी आँत का प्रारंभ) के पहले भाग के पास एक बड़ी ग्रंथि होती है. अग्नयाशय शक्तिशाली पाचन एन्जाइमों का रिसाव करता है. ये एन्ज़ाइम वसाओं, प्रोटीनों और कार्बोहाइड्रेट्स को पचाने में मदद करते हैं. अग्नयाशय हार्मोन-इंसुलिन और ग्लूकागॉन को रक्त में छोड़ते हैं. ये हार्मोन रक्त में ग्लूकोज़ स्तर को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

अग्नयाशय का कैंसर संयुक्त राज्य अमेरिका में कैंसर से होने वाली मौतों के पांचवा सबसे बड़ा कारण है और भारत में लगातार बढ़ रहा है. अग्नयाशय के कैंसर का इलाज शुरूआत में मुश्किल है, क्योंकि इसके कोई खास लक्षण नहीं हैं. समयपूर्व जो लक्षण दिखते है उन्हें पहचानना मुश्किल है, क्योंकि ये सीधी अग्नयाशय के कैंसर का संकेत नही देते. क्योंकि अग्नयाशय शरीर में गहराई पर स्थित है और दूसरे अंगों के पीछे छुपा हुआ है, चिकित्सक नियमित जांच के दौरान देख या अनुभव कर नहीं सकते हैं. अग्नयाशय के कैंसर का पता अक्सर किसी विकसित चरण पर लगता है. इस स्थिति में यह बहुत तेजी से बढ़ता और फैलता है. अंतिम स्थिति में इसका इलाज करना कठिन है, जिसका परिणाम निम्न उपचार दरों में होता है. एक्सोक्राइन अग्नयाशय के कैंसर के ट्यूमर का सर्वाधिक प्रचलित प्रकार है. जो कोशिकाएं पाचन एन्जाइमों का रिसाव करती हैं वो अग्नयाशय के एक्सोक्राइन वाले भाग को बनाती हैं. अग्नयाशय के बाहरी रिसाव वाले के ज़्यादातर ट्यूमर प्रकृति में असाध्य होते हैं. अग्नयाशय के बाहरी रिसाव के ट्यूमर को एडीनोकार्सिनोमा कहते हैं. ये अग्नयाशय के लगभग 95% मामलों में पाए जाते हैं. अग्नयाशय के एडीनोकार्सिनोमा सामान्य रूप से अग्नयाशय की नलिकाओं से उत्पन्न होते हैं, लेकिन ये उन कोशिकाओं से भी विकसित हो सकते हैं जो अग्नयाशय के एन्ज़ाइम बनाती हैं.

एंडोक्राइन ट्यूमर जो कोशिकाएं हार्मोनों का रिसाव करती हैं वो अग्नयाशय के आंतरिक भाग (एंडोक्राइन) का निर्माण करती है. एंडोक्राइन ट्यूमर बहुत कम होते हैं. एंडोक्राइन ट्यूमर को खास तौर पर आइलेट कोशिका ट्यूमरों के रूप में जाना जाता है. आइलेट कोशिका के ट्यूमर भी कई प्रकार के होते हैं जिनको हार्मोन का रिसाव करने वाली कोशिकाओं के प्रकार के अनुसार विभाजित किया गया है. जिनसे वो उत्पन्न होते हैं. इंसुलिनोमा-उन कोशिकाओं से उत्पन्न होते हैं जो इंसुलिन बनाती हैं. ग्लूकागॉनोमा-उन कोशिकाओं से जो ग्लूकागॉन का रिसाव करती हैं. गैस्ट्रिनोमा - उन कोशिकाओं से जो गैस्ट्रिन (हार्मोन मुक्तिकृत द्वारा पेट) बनाती हैं. सोमेटोस्टेटिनोमा-उन कोशिकाओं से जो सोमेटोस्टेटिन बनाती हैं. वीआईपीओमा -उन कोशिकाओं से आते हैं जो वैसो सक्रिय आंत्रिय पैप्टाइड (वी आई पी) बनाती हैं. ये ट्यूमर यदि हार्मोनों का रिसाव करते हैं तो उन्हें काम करने वाले के रूप में और यदि रिसाव नहीं करते हैं तो उन्हें काम न करने वाले के रूप में जाना जाता है. अधिकांश काम करने वाले आइलेट कोशिका ट्यूमर बिनाइन यानी सुसाध्य होते हैं, जबकि काम न करने वाले ट्यूमरों के मलिगनेंट (असाध्य) होने की ज्यादा संभावना होती है. इन ट्यूमरों का उपचार ट्यूमर के विशिष्ट प्रकार और उसके विकसित होने के चरण पर निर्भर करता है.

कैंसर एक बहुकारकीय रोग है. जोखिम वाले कारकों का होना या नहीं होना इसके होने की अकेली वजह नहीं है. कुछ आदतों से बच कर और स्वस्थ जीवनशैली को अपनाकर कैंसर होने की संभावनाओं को कम किया जा सकता है.

अग्नयाशय कैंसर के कारण

अग्नयाशय का कैंसर होने की संभावना 40 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में ज्यादा होती है. धूम्रपान करने वाले लोगों में न करने वालों की तुलना में अग्नयाशय का कैंसर होने की संभावना अधिक होती है. सिगरेट पीना इसका सबसे प्रबल और जोखिम वाले कारकों में से एक है. सिगरेट के धुंए में कार्सिनोजन एक बड़ी मात्रा में होता है. यह अग्नयाशय में कैंसर का सबसे प्रमुख कारण है. असंतुलित खानपान से भी इसका खतरा रहता है.मांस, कोलेस्ट्रॉल, तला हुआ भोजन और नाइट्रोज़एमाइनों की अधिक मात्रा वाले आहार अग्नयाशय के कैंसर का जोखिम बढ़ा सकते हैं. फल और सब्ज़ियों का अधिक मात्रा में सेवन करने से इसका खतरा कम होता है. कुछ समय पहले के शोध से ये बात भी सामने आई है कि मोटापा और व्यायाम न करना भी इस कैंसर के कारणों में से एक हो सकता है. अग्नयाशय का कैंसर पुरुषों में महिलाओं से डेढगुना ज्यादा होने की संभावना होती है. लेकिन महिलाओं के बीच तंबाकू के बढ़ते इस्तेमाल की वजह से आंकड़ों में बदलाव हो रहे हैं और महिलाओं में भी इसका जोखिम बढ़ रहा है. यह बीमारी वंशानुगत भी होती है. अग्नयाशय के कैंसर वाले 10 प्रतिशत रोगियों में यह रोग वंशानुगत कारणों से होता है. पर्यावर्णीय कारक अग्नयाशय के कैंसर की संभावना को काफी बढ़ाते हैं. कैंसर के कारणों एसबेस्टस, रासायनिक दवाएं, डाय और पैट्रोरसायनों का कैंसर के साथ संबंध रहा है अग्नयाशय की दीर्घ-कालिक जलन को अग्नयाशय के कैंसर से जोड़ कर देखा जाता है. आनुवांशिक पैंक्रियाइटिस का अग्नयाशय का कैंसर विकसित होने की संभावना अधिक होती है. मधुमेह को भी अग्नयाशय के कैंसर से जोड़ कर देखा जाता है. मधुमेह अग्नयाशय के कैंसर का एक लक्षण होता है, और यह अग्नयाशय का कैंसर के जोखिम को बढ़ा भी सकता है. किसी बीमारी की वजह से जिन रोगियों के पेट का एक भाग निकाल दिया जाता है (अर्थात आंशिक गैस्ट्रैक्टॉमी) ऐसे लोगों में अग्नयाशय के कैंसर होने की संभावना अधिक होती है, इसमें पेट में दर्द होता है यह दर्द ट्यूमर के बढ़ने के कारण होता है. जो इसे आसपास के अंगों के विरुद्ध ज्यादा जगह लेने की कोशिश करता है और धक्का लगाता है इस कारण दर्द होता है. भोजन करने के बाद लेटे होने पर यह दर्द हो सकता है. इसमें भूख नहीं लगती है या भोजन करने की इच्छा नहीं होती है. या कहें भोजन से घृणा हो जाती है. इस वजह से वजन में कमी आती है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कैंसर कोशिका स्वस्थ कोशिकाओं से पौष्टिक तत्वों लेने के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं. अग्नयाशय के ट्यूमर सामान्य रुप से पाचन क्रिया में हस्तक्षेप करते हैं, जो वज़न और घटा देता है. इस दौरान पीलिया हो जाता है, पित्त नलिका का अंतिम भाग अग्नयाशय के सिर के पीछे पर अग्नयाशय की नलिका के साथ जुड़ता है और छोटी आंत के प्रारंभ (ड्यूओडेनम) में खाली होता है. जैसे अग्नयाशय के सिर में कोई ट्यूमर बढ़ता है पित्त नलिका अवरुद्ध हो जाती है. जब नलिका अवरोधित हो जाती है पित्त यकृत में लौट जाता है और रक्तप्रवाह में प्रवेश करता है जिससे आंखे और त्वचा पीली हो जाती है. क्योंकि पित्त पाचन नलिका में नहीं पहुंचता है, मल हल्के या मिट्टी के रंग का हो जाता है पीलिया मूत्र में पित्त इकट्ठा होने से इसका रंग सामान्य से गहरा हो जाता है. बुखार, कंपकंपी, दस्त, डायबटीज, दस्त लगते हैं, दस्त अग्नयाशय के एन्जाइमों के अभाव के कारण से होते हैं, जो पाचन को प्रभावित करता है.

लक्ष्यीकृत उपचार क्या है?

लक्ष्यीकृत उपचार कैंसर के लिए एक प्रकार का उपचार है जिसमें ऐसी दवाओं का इस्तेमाल होता है जो खास तौर पर कैंसर (कर्क रोग) कोशिकाओं को बढ़ने से रोकता है. लक्ष्यीकृत उपचार से सामान्य स्वस्थ कोशिकाएं प्रभावित नहीं होती हैं और इसलिए इसके हानिकारक प्रभाव रसायन-चिकित्सा (कीमोथेरपी) के हानिकारक प्रभावों से कम हैं. लक्ष्यीकृत उपचार पार्श्वप्रभावों जैसे मितली, उल्टी और बालों के झड़ने जैसी परेशानियां नहीं होती हैं. लेकिन इससे त्वचा में दाने-चित्ते (ददोरे), रक्तस्राव और थक्काकरण जैसे दूसरे असर हो सकते हैं.

निदान

अग्नयाशय के कैंसर का निदान जांचों से किया जा सकता है जिनमें चिकित्सा परीक्षण, विभिन्न इमेजिंग तकनीक, रक्त परीक्षण और बायोप्सी प्रक्रियाएं शामिल हैं. मेडिकल हिस्ट्री वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति, बताए गए लक्षणों, पिछली चिकित्सा समस्याओं, उपचार, परिवार की मेडिकल हिस्ट्री, जीवनशैली और धूम्रपान करना, तंबाकू चबाना, शराब पीना, आहार आदि आदतों की समीक्षा की जाती है. अल्ट्रासोनोग्राफ़ी, सीटी स्कैन,एमआरआई, पॉज़ीट्रॉन एमीशन टोमोग्राफ़ी (पीईटी) और पीईटी-सीटी (इमेजिंग), ईआरसीपी, बायोप्सी, रक्त परीक्षण की मदद से मरीज की स्थिति का आकलन किया जाता है. अग्नयाशय के कैंसर अधिकांशतः अग्नयाशय की नलिकाओं में पाए जाते हैं. अग्नयाशय की नलिका का एडीनोकार्सिनोमा सबसे अधिक प्रचलित प्रकार का अग्नयाशय का कैंसर है और सामान्य रूप से अग्नयाशय के सिर में पाया जाता है. ट्यूमर की कोई विशिष्ट आकृति नहीं होती है और यह आसपास के स्वस्थ ऊतकों में बढ़ता है, जिनमें पड़ोस में अग्नयाशय के ऊतक, रक्त वाहिकाएं और लिम्फ़ नोड्स शामिल हो सकते हैं. म्यूसिन असामान्य रूप से उच्च स्तर ट्यूमरों द्वारा उत्पादित किया जाता है.

उपचार

अग्नयाशय के कैंसर (कर्क रोग) का समयपूर्व चरणों में निदान करना कठिन है, और इस प्रकार से जिस समय तक कोई रोगी किसी चिकित्सक के पास जाता है और अग्नयाशय का कैंसर (कर्क रोग) के साथ निदानित किया जाता है तब तक रोग सामान्य रूप से फैल चुका होता है और निरोगकारी उपचार केवल कुछ रोगियों के लिए एक विकल्प है. केवल 10 से 15 प्रतिशत रोगियों को शल्यक्रिया का प्रस्ताव दिया जा सकता है. शल्यक्रिया एकमात्र तरीका है जो कैंसरीय ट्यूमर को शरीर से बाहर हटा सकता है. लेकिन विकसित चरणों वाले रोगियों में आपरेशन करना संभव नहीं होता है. क्योंकि कैंसर लिम्फ़ नोडों और अन्य दूरस्थ अंगों तक फैल जाता है. शल्यक्रिया कैंसर के उन रोगियों में संभव है जहां मुख्य रक्त वाहिकाएं, लिम्फ़ नोड और अन्य दूरस्थ अंग प्रभावित नहीं हैं. यदि एकदम बगल वाले ऊतक और लिम्फ़ नोड प्रभावित होते हैं, तो भी शल्यक्रिया अभी भी एक विकल्प हो सकता है क्योंकि प्रक्रिया के दौरान बगलवाले ऊतक को हटाया जा सकता है. विकसित चरणों में शल्यक्रिया रोगी को आराम देने और कैंसर की अन्य जटिलताओं को को कम करने के लिए की जाती है. शल्यक्रिया का प्रकार कैंसर के चरण और स्थान पर निर्भर करता है. तीन प्रकार का ऑपरेशन अग्नयाशय के कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है. पहला अग्नयाशय और छोटी आंत के प्रारंभिक भाग को काटना, दूसरा पॅन्क्रिएटेक्टॉमी (डिस्टल अग्नयाशय को काटना), पॅन्क्रिएटेक्टॉमी यानि पहली शल्यक्रिया में, ड्यूओडेनम (छोटी आंत के प्रारंभिक भाग), अग्नयाशय के सिर, पित्ताशय और पित्त नलिकाओं को हटा दिया जाता है. अवशिष्ट अग्नयाशय, पित्त नलिका और पेट को उसके बाद आंत से जोड़ दिया जाता है. यह शल्यक्रिया जटिल और तकनीकी रूप से संतोषजनक नहीं है इसलिए शल्यक्रिया की सफलता शल्यचिकित्सक की कुशलता और अनुभव और शल्यक्रिया के बाद की देखभाल पर निर्भर करती है. इसलिए पॅन्क्रिएटोड्यू ओडेनेक्टॉमी का इलाज उन चिकित्सालयों में करवाना ज़्यादा अच्छा है जहां ऐसी शल्यक्रिया बड़ी संख्या में की जाती हो.

पॅन्क्रिएटेक्टॉमी में डिस्टल अग्नयाशय को काट दिया जाता है कई मामलों में तिल्ली (स्प्लीन) को भी हटा दिया जाता है. यह शल्यक्रिया अग्नयाशय की पूंछ और शरीर में स्थित ट्यूमरों के लिए एक विकल्प है. पॅन्क्रिएटेक्टॉमी में तिल्ली (स्प्लीन) के साथ पूरे अग्नयाशय को हटा दिया जाता है. इस प्रकार की शल्यक्रिया अग्नयाशय के सिर और शरीर के ट्यूमरों के लिए की जाती थी, लेकिन पूरे अग्नयाशय को हटाने की प्रक्रिया में, आइलेट कोशिकाओं को नुकसान पहुंचता हैं. जो अग्नयाशय की एंडोक्राइनीय क्रिया पर भी असर डालता है. ऐसे लोगों मूं शर्करा स्तरों पर खराब नियंत्रण होता है और उनको जीवन भर इंसुलिन लेने की जरूरत हो सकती है.

आहार और पौष्टिक तत्व पर सुझाव

कम मात्रा में और बार-बार खाना खाएं
हल्का भोजन खाएं जिसको खाने और पचाने में आसान हो
अपनी पसंद का खाना खाएं
खाने में विटामिन और खनिज शामिल करें
उच्च वसा वाले भोजन से बचें
शराब पीना और धूम्रपान करना छोड़ दें
किसी आहार विशेषज्ञ से परामर्श लें
अपने चिकित्सक के सुझाव मानें और कोई दिक्कत हो तो उन्हें बताएं

अग्नयाशय के कैंसर से बचने के लिए आहार और स्वस्थ जीवनशैली बहुत जरूरी है. जिन रोगियों के अग्नयाशय के कैंसर का इलाज किया गया है, उनके लिए कीमोथेरपी और रेडियोथेरपी के साथ थकान दूर करने के लिए व्यायाम लाभदायक है. जरूरत के मुताबिक सही व्यायाम करने से रोगी के लिए सामान्य सेहत पाना आसान हो जाता है. अग्नयाशय का कैंसर संक्रामक नहीं है और यह निकट संपर्क होने पर भी परिवार के सदस्यों को नहीं फैलता है. जब आप रसायन-चिकित्सा (कीमोथेरपी) या रेडियोथेरपी ले रहे होते हैं तब आपकी इम्युनिटी कम होती है. इसलिए सर्दी, खांसी, बुखार या किसी अन्य संक्रमण वाले लोगों के साथ संपर्क से बचना चाहिए. जिन बच्चों को कुछ समय पहले टीका लगाया गया है उनसे भी संक्रमण हो सकता है. अग्नयाशय के कैंसर वाले दस प्रतिशत रोगियों के संबंधियों मे भी रोग पाया गया है. ■

navinonline2003@gmail.com

चौथी दुनिया
CHAUTHI DUNIYA
चौथी दुनिया की हर खबर अब आपके Android फोन पर भी उपलब्ध,
Play Store से Download करें | CHAUTHI DUNIYA APP

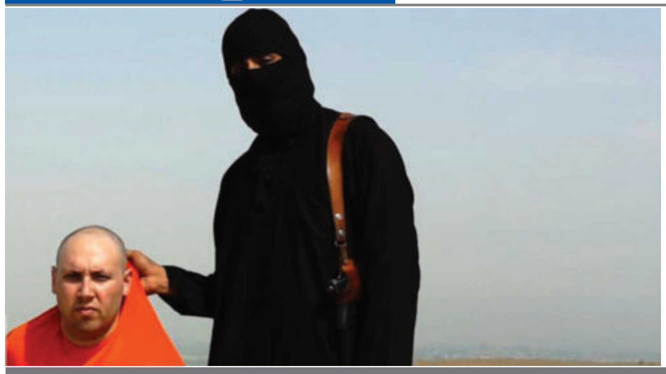

> इसी प्रकार अलबग़दादी का दायां हाथ कहलाने वाला ''हिजी अलबकर' जिसके मशवरे पर ही गतिविधियों का ख़ाका तैयार किया जाता था और दाइश संगठन में अलबग़दादी के बाद सबसे महत्वपूर्ण चेहरा इसी का था, इसने पिछले हते दाइश के लिए लड़ने से इंकार कर दिया है. इसका कहना है कि जिहाद के नाम पर निर्दोषों को मारा जा रहा है. 'हिजी अलबकर' किसी अज्ञात स्थान पर छुपा है. अलबग़दादी से विरोध की कानाफूसियां अधिकृत क्षेत्र के आम नागरिकों की ओर से भी सुनाई दे रही हैं.

संकट में नवाज़ सरकार

अरुण तिवारी

कभी क्रिकेट के मैदान पर जलवा दिखाकर पाकिस्तान को विश्व चैंपियन बनाने वाले इमरान ख़ान और मौलाना ताहिर उल क़ादरी इन दिनों नवाज़ शरीफ़ सरकार के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं. जब से नवाज़ शरीफ़ की पार्टी चुनाव में जीत कर आई, उसके बाद से ही इमरान ख़ान लगातार इस बात का आरोप लगा रहे थे कि चुनाव में बड़े स्तर पर पर धांधली की गई. इस बीच ताहिर क़ादरी ने भी कई बार सरकार का विरोध किया, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ, जिसकी उम्मीद नवाज़ शरीफ़ भी नहीं कर रहे थे. इससे पाकिस्तान में एक बार फिर राजनीतिक अस्थिरता के हालात बनते दिख रहे हैं. शरीफ़ सरकार बेबस नज़र आ रही है. मदद के लिए सेना को जरूर बुलाया गया है, लेकिन इसी सेना द्वारा वर्ष 1999 में किए गए तख्तापलट का ख़ौफ़ अब भी नवाज़ शरीफ़ के जेहन में है.

हालांकि, नवाज़ शरीफ़ ने इस बात का साफ़ ऐलान कर दिया था कि प्रदर्शनकारियों पर न गोली चलाई जाए और न ही लाठी चार्ज किया जाए, लेकिन क्या सिर्फ़ इन निर्णयों से ही वे आम जनता का दिल जीत पाने में कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि आंदोलनकारियों में किसी एक उम्र के लोग नहीं हैं. इनमें बच्चों से लेकर उम्रदराज लोग तक शामिल थे. इससे पहले भी नवाज़ शरीफ़ एक बार सेना द्वारा तख्ता पलट देख चुके हैं. इतना ही नहीं, उन्होंने कई वर्षों तक निर्वासन भी झेला है. इसलिए वह पूरी तरह वाकिफ हैं कि सत्ता से जबरदस्ती हटाए जाने का मतलब क्या होता है. अंतर सिर्फ़ इतना है कि इस बार उनके सामने कोई मिलिट्री जनरल नहीं, बल्कि एक राजनेता ही हैं. कमाल की बात यह है कि उनसे निपटने के लिए नवाज उसी सेना की मदद भी चाहते हैं, जिसने कभी उन्हें सत्ता से बेदख़ल किया था.

तहरीक़-ए-इंसाफ़ पार्टी के नेता इमरान ख़ान का आरोप है कि वर्ष 2013 में हुए आम चुनावों में नवाज़ शरीफ़ ने धांधली की थी और इसी के दम पर वे प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे हैं. वह चुनाव प्रक्रिया में सुधार की मांग भी कर रहे हैं. मौलाना कादरी सात साल कनाडा में रहने के बाद वर्ष 2012 में पाकिस्तान लौटे थे. इससे पहले उन्होंने ज़रदारी पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए, उन्हें पद से हटाने की मांग की थी. अब वह नवाज़ शरीफ़ के इस्तीफ़े की मांग कर रहे हैं. ग़ौरतलब है कि पाकिस्तान में संपन्न हुआ पिछला चुनाव काफ़ी विवादों में रहा. चुनाव परिणाम आने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त के पास देश की 139 संसदीय सीटों का लेखाजोखा है ही नहीं. वहीं, मशहूर पाकिस्तानी न्यूज चैनल जियो टीवी ने 18 फीसद वोटों की गिनती के साथ ही शरीफ़ की पार्टी को विजयी घोषित कर दिया था. इसके अलावा, एक ख़ास बात यह भी है कि पाकिस्तानी सियासत में सेना की भूमिका काफी मायने रखती है. इस पूरे मामले में सेना के रुझान पर राय भिन्न हैं. अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत रह चुके हुसैन हक्कानी ने वाशिंगटन पोस्ट में लिखे अपने आर्टिकल में आशंका जताई है कि इस विरोध प्रदर्शन को सेना का समर्थन भी हो सकता है. कारण यह है कि शरीफ भारत की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं और यह बात सेना को नापसंद है. सेना इसी बहाने शरीफ़ को दबाना चाहती है. शरीफ सरकार से भले ही यह संकट टल जाए, लेकिन मुल्क में जम्हूरियत यानी लोकतंत्र कमज़ोर हो जाएगा. सेना का अभी सरकार में सीधा दख़ल नहीं है. शरीफ़ खुद को बचाने के

लिए मदद लेते हैं, तो यह भविष्य के लिए ठीक नहीं होगा. वैसे भी सत्ता में आने के बाद से अब तक दो मौक़ों पर शरीफ़ को सत्ता की मदद लेना पड़ी है. पहले रावलपिंडी में जहां शिया-सुन्नी हिंसा भड़क गई थी. दूसरी बार कराची एयरपोर्ट पर आतंकी हमले के वक्त.

पाकिस्तान के उद्योगपति भी मान रहे हैं कि शरीफ़ की सरकार गिरी तो ठीक नहीं होगा. बड़ी संख्या में उद्योगपति इमरान के क्रांति मार्च की आलोचना कर रहे हैं. कराची चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इडस्ट्री के पूर्व अध्यक्ष जुबैर मोतीवाला ने बिजनेस रिपोर्टर अख़बार से बातचीत में कहा कि स्थिर सरकार का सीधा नाता देश की आर्थिक सेहत से है. आज मुल्क मुश्किल दौर से गुजर रहा है. सभी को ठहराव चाहिए.

नवाज़ हुए कमज़ोर

मौजूदा संकट ने नवाज़ शरीफ़ को कमज़ोर कर दिया है. विशेष यह हो रहा है कि नवाज़ को अब सेना की आवश्यकता महसूस हो रही है, जिसे वह सरकारी नीतियों से दूर रखना चाहते थे. पाकिस्तान में ज़्यादातर लोगों का यह मानना है कि इसके पीछे सेना का हाथ है. पिछले साल नवाज़ के शपथ लेते ही बहुत सारे लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया था कि यह सियासत में फ़ौज़ी दख़ल के अंत का समय है.

हालांकि, इमरान ख़ान और ताहिर-उल-कादरी के आंदोलन के बाद ये सोच बदलने लगी है. पाकिस्तान में फ़िलहाल जारी राजनीतिक उथल-पुथल ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं, जिसे कुछ हलकों में एक विकट स्थिति के तौर पर देखा जा रहा है. जानकारों का मानना है कि इससे मुल्क की सियासत में सेना के हस्तक्षेप के रास्ते खुल गए हैं. खैर यह देखने वाली बात होगी कि भविष्य में इस आंदोलन का क्या होगा? जानकारों की मानें, तो नवाज़ शरीफ़ को इस आंदोलन से काफ़ी नुक़सान हुआ है. भारत से रिश्ते, तालिबान के ख़िलाफ़ जंग और नाटो के जाने के बाद अफगानिस्तान से रिश्ते जैसे मुद्दों को पहले जहां शरीफ अपने हिसाब से तय करने की कोशिश कर रहे थे, वहीं अब उन्हें सेना की इच्छा के मुताबिक चलना पड़ सकता है. ■

आईएसआईएस के ख़िलाफ़ आर-पार की लड़ाई क्यों नहीं?

वसीम अहमद

आईएसआईएस (दाइश) ने जून 2014 में इराक के उत्तरी हिस्से में संप्रभुता की घोषणा की थी और अबुबकर अल बग़दादी नाम के एक व्यक्ति को नई सल्तनत का अमीर इल मोमीनीन नियुक्त किया था. इराक सरकार ने दाइश पर सैन्य कार्यवाही के लिए लड़ाकू विमान एफ-16 एस की ख़रीदारी को लेकर हुए क़रार के हवाला देते हुए मदद मांगी, लेकिन अमेरिका ने यह कह कर विमान देने से इंकार कर दिया कि अभी इराक के पास इन विमानों को ऑपरेट करने के लिए योग्य पायलट मौजूद नहीं हैं. नतीजतन दाइश तेज़ी के साथ बढ़ता हुआ मूसल तक पहुंच गया और 7 अगस्त को मूसल डैम पर क़ब्ज़ा करने के अलावा मख़मूर और अरबील के लगभग 20-30 किलोमीटर तक के हिस्सों पर क़ब्ज़ा कर लिया. उसके बाद अमेरिका ने दाइश के विरूद्ध सैन्य कार्यवाही करने में कुर्दी सेना ''पशमर्गा'' की मदद की और मूसल में दाइश के 9 ठिकानों और 8 गाड़ियों पर हमला किया. इन हमलों में 9 ठिकाने तबाह होने के साथ-साथ अनेक बैरक और 6 सशस्त्र और बस्तरबंद गाड़ियों के अलावा, दो कार मोबाइल विमान रोधक भी तबाह हुए. इसके अलावा, कुछ ऐसे स्थानों को तबाह किया गया, जहां पर विस्फोटक पदार्थ रखे हुए थे. यह सभी हमले बमबारी और ड्रोन के द्वारा किये गए.

दैनिक ''अलशर्क़ अल औसत'' में प्रकाशित ओबामा प्रबंधन की रिपोर्ट को देखा जाए तो अंदाज़ा होता है कि अमेरिकी हमले का उद्देश्य सीमित है और वह केवल दाइश के विस्तार को रोकना चाहता है, लेकिन अमेरिकी इंटेलीजेंस अधिकारियों की राय एक दूसरी रिपोर्ट में इसके बिल्कुल विपरीत है. इनका कहना है कि इससे यह समझ लेना कि दाइश का अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा और वह आसानी से लौटकर अपने बैरकों में चला जाएगा, ग़लत होगा. अधिकरियों की भविष्यवाणी बहुत हद तक सच होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि मूसल में हार के एक हफ्ते के अन्दर अलबग़दादी की ओर से एक वीडियो जारी किया गया है, जिसमें अमेरिका को यह धमकी दी गई है कि वह दाइश पर और हमले न करे वर्ना इराक में मौजूद अमेरिकियों पर हमले किये जा सकते हैं, बल्कि कई क़दम आगे बढ़ाते हुए दाइश की ओर से एक और वीडियो जारी किया गया है, जिसमें एक अमेरिका पत्रकार जेम्स फौली का सर काटते हुए दिखाया गया है. इस पत्रकार को 2012 में सीरिया में अग़वा किया गया था.

विशेषज्ञों का मानना है कि दाइश बहुत दिनों तक अपनी गतिविधियों को चला नहीं पाएगा, क्योंकि इसके विरूद्ध कई विरोधी ताक़तें एक साथ सर उठा रही हैं. इधर सीरिया ने इस पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं. दूसरी ओर उत्तरी इराक के नेनवी में सुन्नियों का एक बहुत बड़ा ग्रुप दाइश के मुक़ाबले में आ खड़ा हुआ है. यह ग्रुप कुर्दी सेना के साथ मिलकर मूसल के पूरे हिस्से आज़ाद कराने का संकल्प

रखता है. एक अन्य संगठन के प्रवक्ता माजिऩ सामराई जो इराक़ी सेना में कर्नल रह चुके हैं, ने बताया कि दाइश को इराक से ख़त्म करने के लिए सभी संगठनों ने एक ज्वाइंट वेंचर बनाया है. इसमें फसाइल नक़्शबंदिया, सूरा अशरीन, जैश-ए-राशिदीन, जैश-ए-मुजाहिदीन, जैश-ए-इस्लामी के अलावा अन्य कई ग्रुप दाइश के विरूद्ध संगठित हो गए हैं.

यह स्थिति दाइश पर बाहरी दबाव डालने के लिए काफ़ी है, लेकिन अगबग़दादी के बारे में जैसा कि अमेरिकी इंटेलीजेंस ने कहा है कि वह बेहतरीन युद्ध अनुभव रखता है. लिहाज़ा, वह बाहरी दबाव के कारण अपने इरादे से पीछे नहीं हट सकता है. इधर हाल ही में इसके सामने जो नई परिस्थिति पैदा हुई है, इससे निपटना उसके लिए मुश्किल भरा होगा और हो सकता है कि यही स्थिति इसके अंत का कारण बन जाए, क्योंकि इसके एक क़रीबी साथ अबु अलकु़मान ने स्वयं को इराक व सीरिया में मुसलमानों का ख़लीफ़ा घोषित कर दिया है. अबु अलकु़मान का असली नाम अली मूसा श्वाख़ है और वह जिल़ा ''तबक़ा'' के रेक़ा गांव का रहने वाला है जो सीरिया में है. वह पेशे से वकील है और 2003 में जिहादी संगठन से जुड़ा था. दाइश की ओर से 'रेक़ा' और इसके चारों ओर की निगरानी का काम अबु अलकु़मान को दिया गया था. विशेष रूप से सज़ा-ए-मौत और फ़ांसी की सज़ा की निगरानी इसी के जिम़्मे थी. इसने पिछले हते दाइश से विद्रोह करके ख़ुद को मुसलमानों का अमीर होने का ऐलान कर दिया है और साथ ही यह बयान भी जारी किया है कि ''अबु बकर अलबग़दादी के ख़ानदान और नस्ल का सही पता किसी को नहीं है जबकि इसके बारे में पूरी क़ौम को पता है कि वह अलअसील क़बीले से संबंध रखता है और 'रेक़ा' का रहने वाला है. इसीलिए जनता इसे अपना अमीर बनाना चाहती है. लिहाज़ा अलबग़दादी को ख़ारिज किया जाता है और इसकी जगह मैं ''ममलकत इस्लामिया'' का ख़लीफ़ा हूं'. इस ऐलान ने अलबग़दादी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दीं हैं. वह बाहरी विद्रोहियों से तो अपने वफ़ादारों के द्वारा मुक़ाबला कर सकता है लेकिन यहां पर तो वफ़ादारों ने ही अपनी वफ़ादारियां बदल दी हैं. स्वयं दाइश के प्रवक्ता अबु मोहम्मद अलअदनानी का कहना है कि 4 हज़ार लोगों के हस्ताक्षर से एक दस्तावेज़ इसे मिला है, जिसमें अबु अलकुमान को अमीर स्वीकार किया गया है.

इसी प्रकार अलबग़दादी का दायां हाथ कहलाने वाला ''हिजी अलबकर' जिसके मशवरे पर ही गतिविधियों का ख़ाका तैयार किया जाता था और दाइश संगठन में अलबग़दादी के बाद सबसे महत्वपूर्ण चेहरा इसी का था, इसने पिछले हते दाइश के लिए लड़ने से इंकार कर दिया है. इसका कहना है कि जिहाद के नाम पर निर्दोषों को मारा जा रहा है. 'हिजी अलबकर' किसी अज्ञात स्थान पर छुपा है. अलबग़दादी से विरोध की कानाफूसियां अधिकृत क्षेत्र के आम नागरिकों की ओर से भी सुनाई दे रही हैं. इस विरोध का मूल कारण यह बताया जा रहा है कि लोग हिंसक वातावरण होने के कारण परेशान हो चुके हैं. आवश्यक वस्तुएं इतनी महंगी हो चुकी हैं कि उन्हें ख़रीदना बस से बाहर हो चुका है. खाद्य पदार्थों की कमी तो है ही, किराये इतने बढ़े हुए हैं कि 100-100 किलोमीटर तक लोग पैदल चलकर जाते हैं. एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जहां 60 इराकी दीनार लगते थे, अब इसी के लिए ढाई सौ दीनार तक देने पड़ते हैं, जबकि आय बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है.

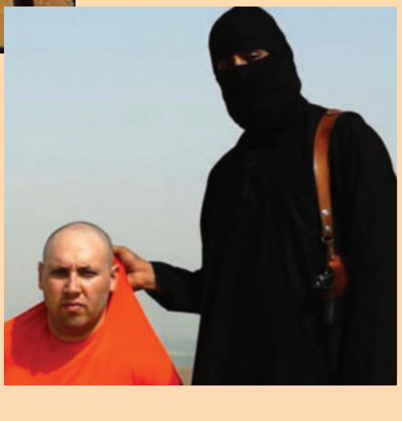

यह परिस्थितियां अलबग़दादी के लिए चिंता का विषय हैं. लिहाज़ा अमेरिकी हमलों के कारण से दाइश का अस्तित्व ख़त्म हो न हो तब भी आंतरिक रूप से जो मतभेदों का तूफान खड़ा हुआ है, इससे अलबग़दादी की कमर टूट रही है और इसी आंतरिक मतभेद के कारण विशेषज्ञों का मानना है कि दाइश के इस्लामी राष्ट्र का सिमटना शुरू हो चुका है. ■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
CHAUTHI DUNIYA

चौथी दुनिया की हर ख़बर अब आपके Android फ़ोन पर भी उपलब्ध,
Play Store से Download करें | CHAUTHI DUNIYA APP

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

कठफोड़वा कछुए से बोला- मित्र तुम्हारे दांत मजबूत हैं. तुम इस फंदे को काटो. मैं शिकारी का रास्ता रोकता हूं. जैसे ही कछुआ फंदा काटने में लग गया. उधर कठफोड़वा शिकारी की झोपड़ी की तरफ उड़ चला. उसने योजना बनाई कि जैसे ही शिकारी झोपड़ी से बाहर निकलेगा, वह उसे चोंच मारकर लहूलुहान कर देगा. उधर शिकारी ने भी जैसे ही हिरण की चीख सुनी तो समझ गया कि वह फंदे में फंस चुका है. वह तुरंत झोपड़ी से बाहर निकला और पेड़ की ओर लपका. लेकिन कठफोड़वे ने उसके सिर पर चोंच मारनी शुरू कर दी.

सब पर कृपा करते हैं साईं बाबा

चौथी दुनिया ब्यूरो

सदगुरू सदा अपने शिष्यों को वेदों तथा शास्त्रों के बारे में शिक्षा प्रदान करते हैं. वे अपने शिष्यों को स्वेच्छा से अपनी क्रियाओं पर नियंत्रण कर सहज ही मुद्राएं लगाकर मंत्रो के जाप का आदेश देते हैं. सदगुरू सदा ही अपने भक्तों को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की शिक्षा देते हैं और कहते हमें अपनी वाणी से किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए. वे अपने शिष्यों को आत्मसाक्षात्कार कराते हैं. सदगुरू हमें हर कठिन-से-कठिन समस्या से बाहर निकलने का रास्ता दिखाते हैं. सदगुरू स्वप्न में भी अपने शिष्य से कोई लाभ या सेवा की लालसा नहीं करते, वह दूसरों की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं. सदगुरू अपने को कभी महान नहीं समझते हैं, उन्हें कभी इसका एहसास नहीं होता है कि वे महान हैं और अपने शिष्य को उनसे तुच्छ नहीं समझते हैं अपितु उसे अपने ही सदृश्य (ब्रह्मस्वरूप) समझा करते हैं.

सदगुरु की मुख्य विशेषता है कि उनके हृदय में सदैव परम शांति विद्यमान रहती है. वे कभी अस्थिर या अशांत नहीं होते और न उन्हें अपने ज्ञान का थोड़ा भी गर्व होता है. उनके लिये राजा से लेकर रंक तक सब एक ही समान है. साईं बाबा के भक्तों के शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप ही उन्हें श्री साईं चरणों की प्राप्ति होती है.

साईं बाबा बचपन से ही निर्जन स्थानों में विचरण करते एवं सदा आत्मलीन रहते थे. वे सदैव भक्तों की निःस्वार्थ भक्ति देखकर ही उनकी इच्छानुसार आचरण किया करते थे. उनका कहना था कि मैं सदा भक्त के पराधीन रहता हूं. साईं बाबा जब जीवित थे, उस समय भक्तों ने जो अनुभव किए, आज भी बाबा के भक्त उसी प्रकार का अनुभव करते हैं. भक्त अपने हृदय को भक्ति विश्वास का दीपक बनाकर उसमें प्रेम प्रज्वलित करें, तो ज्ञानज्योति (आत्म साक्षात्कार) स्वयं प्रकाशित हो उठेगी. प्रेम के अभाव में शुष्क ज्ञान व्यर्थ है. ऐसा ज्ञान किसी के लिए भी लाभप्रद नहीं हो सकता. इसलिए हमारा प्रेम असीम और अटूट होना चाहिये. प्रेम की कीर्ति का गुणगान कौन कर सकता है, जिसकी तुलना में समस्त वस्तुएं तुच्छ जान पड़ती हैं. प्रेम रहित पठन-पाठन सब निष्फल है. प्रेमांकुर के उदय होते ही भक्ति, वैराग्य, शांति और कल्याण रूपी संपत्ति सहज ही प्राप्त हो जाती है. जब तक किसी वस्तु के लिए प्रेम उत्पन्न नहीं होता, तब तक उसे प्राप्त करने की भावना ही उत्पन्न नहीं होती. इसलिये जहां व्याकुलता और प्रेम है, वहां भगवान स्वयं प्रगट हो जाते हैं. भाव में ही प्रेम अंतर्निहित है और वहीं मोक्ष का कारण है. यदि कोई व्यक्ति कलुषित भाव से भी किसी सच्चे संत के चरण पकड़ लें, तो यह निश्चित है कि वह अवश्य तर जाएगा. ऐसी ही कथा नीचे दर्शाई गई है.

बाबा के भक्त स्पटणेकर वकालत का अध्ययन कर रहे थे. एक दिन उनकी अपने सहपाठी श्री शेवड़े से भेंट हुई. अन्य विधार्थी भी वहां एकत्रित हुए और सब ने अपनी-अपनी अध्ययन संबंधी योग्यता का परस्पर परीक्षण किया. प्रश्नोत्तरों से विदित हो गया कि सब से कम अध्ययन श्री शेवड़े का है और वे परीक्षा में बैठने के अयोग्य हैं. जब सब मित्रों ने मिलकर उनका उपहास किया, तब शेवड़े ने कहा कि यघपि मेरा अध्ययन अपूर्ण है, तो भी मैं परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाऊंगा. मेरे साईबाबा ही सबको सफलता देने वाले है. सपटणेकर को यह सुनकर आश्चर्य हुआ और उन्होंने शेवड़े से पूछा कि ये साईं बाबा कौन हैं, जिनका तुम इतना गुणगान कर रहे हो. उन्होंने उत्तर दिया कि वे एक फकीर हैं, जो शिरडी की एक मस्जिद में निवास करते हैं. वे महान सत्पुरुष हैं. ऐसे अन्य संत भी हो सकते हैं, लेकिन वे उनसे अद्वितीय हैं. जब तक पूर्व जन्म के शुभ संस्कार संचित न हो, तब तक उनसे भेंट होना दुर्लभ है. मेरी तो उन पर पूर्ण श्रद्धा है. उनके श्रीमुख से निकले वचन कभी असत्य नहीं होते. उन्होंने ही मुझे विश्वास दिलाया है कि मैं अगले वर्ष परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाऊंगा. मेरा भी अटल विश्वास है कि मैं उनकी कृपा से परीक्षा में अवश्य ही सफलता पाऊंगा. सपटणेकर को अपने मित्र के ऐसे विश्वास पर हंसी आ गई और साथ ही साथ साईबाबा का भी उन्होंने उपहास किया. भविष्य में जब शेवड़े दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो गए, तब सपटणेकर को यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ. साईं इसी प्रकार अपने भक्तों पर सदा ही कृपा बनाए रखते हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

साईं के ग्यारह वचन

1-जो शिरडी आएगा, आपद दूर भगाएगा.
2-चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुःख की पीढ़ी पर.
3-त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा.
4-मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस.
5-मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो.
6-मेरी शरण आ खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए.
7-जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का.
8-भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा.
9-आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वही नहीं है दूर.
10-मुझमें लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया.
11-धन्य-धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य.

साईं भक्तों!

आप भी चौथी दुनिया को साईं से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साईं से आप कब और कैसे जुड़े. साईं की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साईं को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साईं भक्त. साईं बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है. साईं बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर), उत्तर प्रदेश, पिन-201301
ई-मेल feedback@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

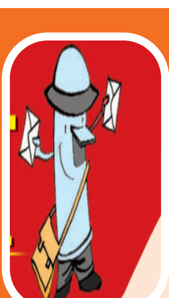

लालू, नीतीश की दोस्ती

कवर स्टोरी-बिहार विधानसभा उपचुनाव महा-गठबंधन का भविष्य(18-24 अगस्त 2014) पढ़ा. मनीष कुमार ने सही कहा है कि इस गठबंधन से सबसे ज्यादा फायदा लालू यादव को मिलने वाला है. नीतीश ने लालू के जगंलराज के विरोध में ही बिहार की सत्ता पर कब्जा जमाया था. नीतीश ने जिसके खिलाफ चुनाव लड़ा था, अब भाजपा के खिलाफ कांग्रेस, राजद, जदयू तीनों पार्टियों का गठबंधन हुआ है. जो एक दूसरे को गाली देते आ रहे थे, वो बिहार विधानसभा उपचुनाव एक साथ लड़ रहे हैं. लोकसभा चुनाव में साम्प्रादयिकता का समीकरण बिगड़ जाने के बाद भी यह जनता को नहीं समझ पा रहे हैं. उपचुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है.

-आलोक सिंह, पटना, बिहार.

डब्ल्यूटीओ और प्रधानमंत्री

खाद्य, भंडारण, डब्ल्यूटीओ और भारत क्या मोदी झुक जाएंगे अमेरिका के सामने(18-24 अगस्त 2014) शीर्षक से लिखे अपने लेख में शशि शेखर ने डब्ल्यूटीओ को लेकर विस्तार से लिखा है. यह बिल्कुल सही है कि विकसित देश इस समझौते को व्यापार के नजरिए से देख रहे हैं. प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि गरीबों किसानों के खिलाफ कोई भी समझौता डब्ल्यूटीओ में नहीं करेंगे. एक काम तो सरकार ने किया है कि आरएसएस के विरोध के बाद जीएम फसलों के फील्ड ट्रायल पर रोक लगा दिया है. पहले भी सरकारे यही कहती रही हैं, लेकिन वे जाकर समझौता कर लेती रही हैं. अब देश की निगाहें नरेंद्र मोदी पर टिकी हैं कि वो अपने वादे पर खरा उतरते हैं या नहीं.

-दीपक चतुर्वेदी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश.

भ्रष्टाचार का बोलबाला

आलेख-रामराज या भ्रष्टराज (18-24 अगस्त 2014) पढ़ा काफी तथ्यपरक है. नवीन चौहन ने मध्य प्रदेश में प्रत्येक दिन भ्रष्टाचार में लिप्त सरकारी कर्मचारियों के नाम आने को लेकर जो सवाल किए हैं, वह बिल्कुल सही है. मध्यप्रदेश में आए दिन लोकयुक्त के छापे के दौरान वहां के सरकारी कर्मचारियों के यहां करोड़ों की संपत्ति मिलती है. अगर ये हाल छोटे कर्मचारियों का है, तो वहां बड़े अधिकारियों के पास कितनी संपत्ति होगी इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है. जिन मंत्रियों और नौकरशाहों के खिलाफ जांच की अनुमति के लिए लंबे समय रोक लगा रखी है अगर सरकार जांच की अनुमति दे, तो उसमे से भी पता चल जाएगा कितने इमानदार हैं और कितने भ्रष्ट.

-रवि कुमार, ग्वालियर, मध्यप्रदेश.

बिना सरकार दिल्ली

आलेख-दिसंबर में तय होगा दिल्ली का राजनीतिक भविष्य(18-24 अगस्त 2014) पढ़ा काफी अच्छा लगा. अभिषेक रंजन सिंह का आलेख काफी विचारोत्तेजक है. दिल्ली में पिछले साल दिसंबर में ही चुनाव हुए थे, उसके बाद आम आदमी पार्टी कांग्रेस समर्थन में सरकार बनाई थी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बने थे. उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने जन-लोकपाल के नाम पर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि वह प्रधानमंत्री का सपना आंखों में संजोए बैठे थे. तब से लेकर आज तक भाजपा से लेकर आप दोनों जोड़-तोड़ की कोशिश कर सरकार बनानी चाही, लेकिन दिल्ली सरकार नहीं बन पाई. केंद्र सरकार से सुप्रीमकोर्ट के सवाल पूछने के बाद लगता है कि दिसंबर में चुनाव हो सकते हैं. चुनाव परिणाम बाद ही पता चलेगा कि किसकी सरकार बनती है.

-पुर्णिमा सिंह, भजनपुरा, दिल्ली.

सपा की अग्निपरीक्षा

आलेख-विधानसभा-लोकसभा उपचुनाव सपा के लिए इज्जत का सवाल(18-24 अगस्त 2014) पढ़ा काफी रुचिकर है. प्रभात रंजन दीन ने सही कहा है कि उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव सपा के लिए नाक का सवाल बन गए हैं. उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा और लोकसभा उपचुनाव के परिणाम सपा के लिए खतरे की घंटी साबति हो सकते हैं. उत्तर प्रदेश में दिनों-दिन अपराध का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है और सपा सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है. उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा चरम पर है सहारनपुर दंगों में मुख्यआरोपी की फोटो जब से अखिलेश यादव के साथ देखी गई तब से लोगों का विश्वास इस सरकार से ज्यादा उठ गया है. अब उपचुनाव परिणाम ही बताएगा कि अखिलेश यूपी कितनी मजबूत रह गई है.

-विशाल कनौजिया, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश.

निडर समाचार पत्र

मैं चौथी दुनिया समाचार पत्र तीन वर्षों से लगातार पढ़ता आ रहा हूं. चौथी दुनिया के हर अंक में प्रकाशित खबरें तथ्यों पर आधारित एवं विचारोत्तेजक होती हैं. चौथी दुनिया समाचार पत्र हर सप्ताह की नई-नई खबरें और जानकारी देता है. चौथी दुनिया समाचार पत्र में संतोष भारतीय और कमल मोरारका का आलेख अखबार में चार चांद लगा देता है. संतोष भारतीय का आलेख और संपादकीय पढ़कर काफी खुशी होती है, जो भी बिना किसी राजनीतिक दबाव के निर्भीक होकर हर मुद्दे पर लिखते हैं. चौथी दुनिया समाचार पत्र का हर लेख अच्छा होता है. मुझे आशा है कि चौथी दुनिया आगे भी इसी निर्भीकता के साथ खबरें प्रकाशित करता रहेगा.

-अरविंद राम, दरभंगा, बिहार.

पाठक पूरा नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने स्वतंत्र विचार व प्रतिक्रियाएं इस पते पर भेजें :

चौथी दुनिया, एफ.2, सेक्टर-11, नोएडा (उत्तर प्रदेश) पिन-201301

कहानी

सच्चे मित्र

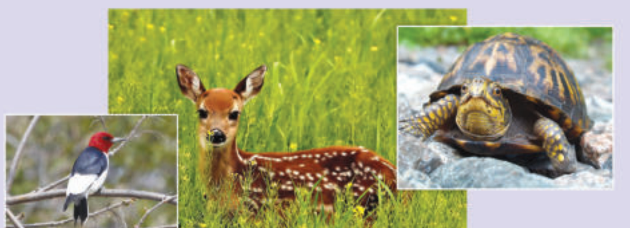

झील किनारे एक जंगल में हिरण, कछुआ और कठफोड़वा एक साथ रहते थे. एक दिन एक शिकारी ने उनके पैरों के निशान देखकर उनके रास्ते में पड़ने वाले पेड़ पर एक फंदा लटका दिया और अपनी झोपड़ी में चला गया. थोड़ी ही देर में हिरण मस्ती में झूमता हुआ उधर से निकला और फंदे में फंस गया. वह जोर से चिल्लाया-बचाओ. उसकी पुकार सुनकर कठफोड़वा के साथ कछुआ वहां आ गया. कठफोड़वा कछुए से बोला- मित्र तुम्हारे दांत मजबूत हैं. तुम इस फंदे को काटो. मैं शिकारी का रास्ता रोकता हूं. जैसे ही कछुआ फंदा काटने में लग गया. उधर कठफोड़वा शिकारी की झोपड़ी की तरफ उड़ चला. उसने योजना बनाई कि जैसे ही शिकारी झोपड़ी से बाहर निकलेगा, वह उसे चोंच मारकर लहूलुहान कर देगा. उधर शिकारी ने भी जैसे ही हिरण की चीख सुनी तो समझ गया कि वह फंदे में फंस चुका है. वह तुरंत झोपड़ी से बाहर निकला और पेड़ की ओर लपका. लेकिन कठफोड़वे ने उसके सिर पर चोंच मारनी शुरू कर दी. शिकारी अपनी जान बचाकर फिर झोपड़ी में भागा और पिछवाड़े से निकलकर पेड़ की ओर बढ़ा. लेकिन कठफोड़वा शिकारी से पहले ही पेड़ के पास पहुंच गया था. उसने देखा की कछुआ अपना काम कर चुका है, उसने हिरण और कछुए से कहा-मित्रों जल्दी से भागो. शिकारी आने ही वाला होगा. यह सुनकर हिरण वहां से भाग निकला. लेकिन कछुआ शिकारी के हाथ लग गया. शिकारी ने कछुए को थैले में डाल लिया और बोला इसकी वजह से हिरण मेरे हाथ से निकल गया. आज इसको ही मारकर खाऊंगा. हिरण ने सोचा उसका मित्र पकड़ा गया है. उसने मेरी जान बचाई थी, अब मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उसकी मदद करूं. यह सोचकर वह शिकारी के रास्ते में आ गया. शिकारी ने हिरण को देखा तो थैले को वहीं फेंककर हिरण के पीछे भागा. हिरण अपनी पुरानी खोह की ओर भाग छूटा. शिकारी उसके पीछे-पीछे था. भागते-भागते हिरण अपनी खोह में घुस गया. उसने सोचा एक बार शिकारी इस खोह में घुस गया तो उसका बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा. थोड़ी ही देर में शिकारी खोह में पहुंचा. उसने सोचा अब हिरण भागकर कहां जाएगा. वह भी खोह के अंदर घुस गया. खोह के अंदर भूल-भुलैया जैसे रास्ते थे. शिकारी उन रास्तों में भटक गया. हिरण दूसरे रास्ते से निकलकर थैले के पास जा पहुंचा और कछुए को आजाद कर दिया. उसके बाद वे तीनों मित्र वहां से सही-सलामत निकल गए. ■

शिक्षा-हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

नैफनेल ने फिर थोड़ा सोचा और अपने पिता की ओट में छिप गया. मोटे आदमी ने उत्साह से अपने दोस्त की ओर देखा और बोला, और सुनाओ दोस्त, तुम्हारा क्या हालचाल है? कोई नौकरी करते हो? किस पद तक पहुंचे?

बाज़ार पर लेखकों का जादू

अनंत विजय

अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ के विमोचन के मौक़े पर पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह ने ऐलान किया कि उनकी किताब की क़रीब पचास हज़ार प्रतियां बिक चुकी हैं. किताब के विमोचन के पहले पचास हज़ार प्रतियां बिक जाना मामूली घटना नहीं है. नटवर सिंह ने इसके लिए इशारों-इशारों में सोनिया गांधी के सिर सेहरा बांधा. दरअसल, नटवर सिंह की किताब रिलीज होने के तक़रीबन दस दिनों पहले यह ख़बर आई थी कि सोनिया गांधी एवं प्रियंका गांधी उनसे मिलने उनके घर गई थीं. इस मुलाकात के दौरान प्रियंका ने छपने वाली किताब के बारे में दरियाफ्त की थी. यह ख़बर लीक इस तरह की गई कि सोनिया एवं प्रियंका किताब के कुछ अंश रोकने का आग्रह करने के लिए नटवर सिंह के पास गई थीं. यह ख़बर जंगल में आग की तरह फैली और पूरे देश में नटवर सिंह की आने वाली किताब को लेकर एक उत्सुकता का वातावरण बना. इसके बाद नटवर सिंह की किताब के कुछ चुनिंदा अंश लीक किए गए, जिनमें यह बताया गया कि सोनिया गांधी ने 2004 में प्रधानमंत्री का पद राहुल गांधी के दबाव में छोड़ा था. किताब रिलीज होने के पहले ही इस बात को लेकर देश भर में चर्चा शुरू हो गई. लोकसभा चुनाव में करारी हार के सदमे से उबर रही कांग्रेस के लिए यह खुलासा एक बड़े झटके की तरह था.

सोनिया ने जब 2004 में प्रधानमंत्री पद ठुकराया था, तब उन्होंने अपने भाषण में इसे अंतरात्मा की आवाज़ करार दिया था. इस ख़बर के सामने आते ही कांग्रेसियों में नंबर बढ़ाने की होड़ लग गई और वह सोनिया के समर्थन में बयानबाजी करने लगे. नटवर की किताब को लेकर बने उत्सुकता के माहौल को कांग्रेसियों की बयानबाजी ने और बढ़ा दिया. एक खुलासा और हुआ कि सोनिया की मर्जी के बगैर सरकार में पत्ता भी नहीं हिलता था. प्रकारांतर से यह बात फैली कि सोनिया सरकारी फाइलें देखती थीं. इस खुलासे को मजबूती मिली प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पूर्व मीडिया सलाहकार की किताब में हुए खुलासे से. संजय बारू की किताब में भी इसी तरह की बात थी कि यूपीए सरकार के अहम फ़ैसले सोनिया की मंजूरी के बाद होते थे. यह बात दीगर है कि सोनिया गांधी अपने इंटरव्यू में कह चुकी थीं कि उनके बच्चे उनके प्रधानमंत्री बनने के ख़िलाफ़ थे. इस बात का खंडन भी आ चुका था कि मनमोहन सिंह सरकार के फ़ैसलों में सोनिया का दखल होता था. लेकिन, किताब की बिक्री बढ़ाने के लिए इतना मसाला काफी था. नतीजा यह हुआ कि किताब के औपचारिक रूप से जारी होने के पहले ही उसकी पचास हज़ार प्रतियां बिक गईं. यह बिक्री बढ़ाने में ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स ने भी मदद की. प्री-लांच के तहत पाठकों को छूट के साथ औपचारिक रिलीज के पहले किताब देने की रणनीति काम आई. ऑनलाइन बिक्री के आंकड़े सार्वजनिक नहीं हुए हैं, लेकिन जानकारों का मानना है कि पचास फ़ीसद से ज़्यादा बिक्री इन साइट्स के माध्यम से हुई.

अब एक दूसरी साहित्यिक घटना पर नज़र डालें. अंग्रेजी में उपन्यास लिखने वाले चेतन भगत के नए उपन्यास का ऐलान एक राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक के पहले पन्ने पर छपे पूरे पेज के विज्ञापन से हुआ. विज्ञापन की भाषा थी, द लेटेस्ट ब्लॉक बस्टर फ्राम चेतन भगत इज हाफ गर्ल फ्रेंड, अ लव स्टोरी. पूरे पेज के विज्ञापन और उसकी भाषा देखने के बाद पहली नज़र में किसी फिल्म का प्रचार लगा था, लेकिन यह विज्ञापन था चेतन भगत के नए उपन्यास का. भारत के साहित्य जगत में इस तरह का यह पहला और अनूठा प्रयोग है. चेतन भगत मूलत: अंग्रेजी में लिखते हैं. गंभीर साहित्य लिखने वाले लेखक एवं आलोचक चेतन भगत के उपन्यासों को हल्का और चालू किस्म का मानते हैं. हिंदी के साहित्यकार चेतन भगत की तुलना मेरठ से लुगदी पर छपने वाले उपन्यासकारों से करते हैं, लेकिन पाठकों के बीच चेतन भगत की लोकप्रियता जबरदस्त है. चेतन भगत अपनी और अपनी किताबों की मार्केटिंग करने का नुस्खा जानते हैं, बाज़ार का फ़ायदा उठाना

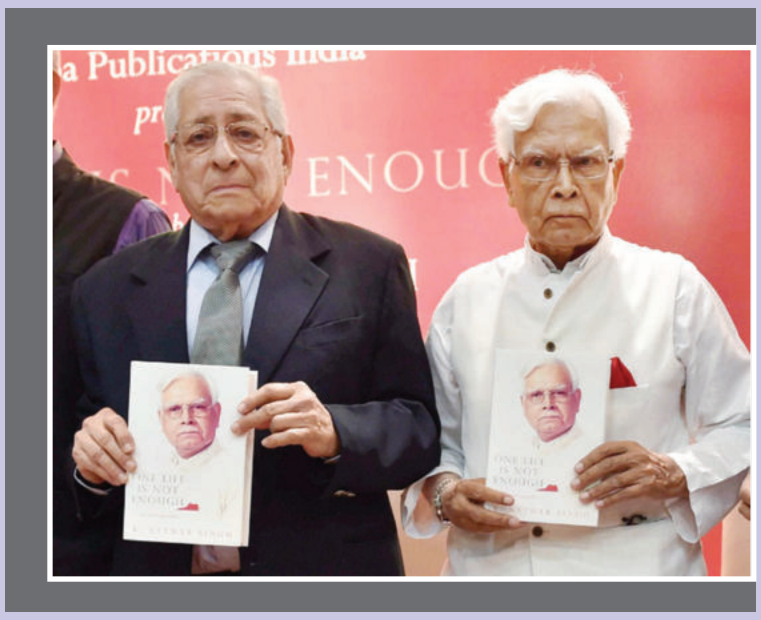

जानते हैं. उनके उपन्यासों पर आमिर खान अभिनीत थ्री इडियट्स के अलावा टू स्टेटस समेत कई सुपर हिट फिल्में भी बन चुकी हैं. बाज़ार का फ़ायदा उठाने और पाठकों को झटका देने की रणनीति के तहत उपन्यास छपने के पहले ही क़रीब पचास लाख रुपये उसके विज्ञापन पर खर्च कर दिए गए. इसकी कल्पना भारतीय साहित्य जगत में नहीं की गई थी.

दरअसल, यह आक्रामक मार्केटिंग रणनीति का हिस्सा है कि पाठकों को पहले चौंकाओ और फिर उन्हें किताब खरीदने के लिए बाध्य कर दो. छपने के पहले उपन्यास की साढ़े सात लाख प्रतियों का ऑर्डर देना और उसे प्रचारित करना इसी आक्रामक रणनीति का हिस्सा है. किताब की अग्रिम बुकिंग शुरू हो चुकी है. पहले दो महीने किताब सिर्फ़ ऑनलाइन वेबसाइट पर ही मिलेगी. एक खास वेबसाइट के साथ टाइअप किया गया है, जो किताब के प्रचार में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रही है. उपन्यास के विज्ञापन में चेतन की किताब के अलावा वेबसाइट का पता और प्रकाशक का नाम भी छपा है. भारतीय किताब बाज़ार के लिए यह एक घटना है. भारत में किताबों का इतना बड़ा बाज़ार है, इसकी कल्पना नहीं की गई थी, लेकिन ऑनलाइन कारोबार के फैलाव ने इसे यथार्थ बना दिया. भारत की जनसंख्या और साक्षरता दर में बढ़ोतरी के बाद पाठकों की संख्या में अभूतपूर्व इजाफा हुआ है, जिसे भुनाने में ऑनलाइन कंपनियां आगे हैं. भारत में जैसे-जैसे इंटरनेट का घनत्व बढ़ता जाएगा और तकनीक का विकास होगा, वैसे-वैसे बाज़ार का फैलाव होगा. अब जरा इन दोनों घटनाओं के बरक्स हिंदी प्रकाशन जगत पर नज़र डालते हैं, तो एक ऐसा सन्नाटा दिखाई देता है, जिसके निकट भविष्य में टूटने की गुंजाइश नज़र नहीं आती. हिंदी के ज़्यादातर प्रकाशक तकनीक का अपने हक़ में इस्तेमाल करने से हिचकिचा रहे हैं. हिंदी पट्टी में साहित्य के पाठक हैं, यह बात हर छोटे-बड़े शहरों में लगने वाले पुस्तक मेले से बार-बार साबित होती है. दिल्ली और अन्य हिंदीभाषी शहरों में किताबों की दुकानें बंद हो गई हैं. पाठकों के लिए किताब खरीदना एक श्रमसाध्य कार्य है. इस कमी को ऑनलाइन बुक स्टोर ने ख़त्म नहीं, तो कम करने की कोशिश ज़रूर की है. हिंदी के हमारे प्रकाशक अब तक इन ऑनलाइन बुक शॉप तक पहुंच नहीं पाए हैं. हिंदी में बड़ी संख्या में किताबें छपती हैं, लेकिन वे बहुत कम संख्या में ऑनलाइन बुक स्टोर तक पहुंच पाती हैं. इसके लिए हिंदी के प्रकाशकों को पहल करनी होगी और उन्हें इन साइट्स के साथ रणनीतिक तौर पर समझौते करने होंगे. एक बार हिंदी के पाठकों को यह पता लग गया कि फलां किताब ऑनलाइन है, तो फिर उसकी बिक्री भी होगी. दूसरी बड़ी बात यह है कि हिंदी के लेखकों को भी तकनीक को गले लगाना चाहिए, उससे दूर नहीं भागना चाहिए.

पिछले विश्व पुस्तक मेले में एक संगोष्ठी में हिंदी के लेखकों के तकनीक से दूर रहने पर मैंने सवाल खड़े किए थे, तो वहां मौजूद एक लेखक को यह बात नागवार गुजरी थी. अब हिंदी के लेखकों में फेसबुक को लेकर एक उत्साह जगा है, लेकिन हमारे वरिष्ठ लेखक अब भी फेसबुक, ट्वीटर, गूगल प्लस आदि से दूर हैं. कई उत्साही युवा लेखक अवश्य तकनीक का बेहतर इस्तेमाल कर पाठकों तक पहुंच रहे हैं. अब ज़रूरत इस बात की है कि पाठकों तक रचनाएं कैसे पहुंचाई जाएं. नटवर सिंह और चेतन भगत की किताबों की सफलता से यह बात साबित हो गई है कि भारत में पाठक हैं. अंग्रेजी पढ़ने वालों की तुलना में हिंदी के पाठक कहीं ज़्यादा हैं. अगर नटवर सिंह की किताब की पचास हज़ार प्रतियां बिक सकती हैं, तो रवींद्र कालिया, उदय प्रकाश, मैत्रेयी पुष्पा, चित्रा मुद्गल एवं मृदुला गर्ग जैसे हमारे वरिष्ठ लेखकों की किताबें कम संख्या में बिकेंगी, इसका कोई आधार नहीं है. कम बिक्री का सिर्फ़ और सिर्फ़ एक आधार समझ में आता है, वह है कृतियों की अनुपलब्धता. हिंदी साहित्य को लेकर मीडिया में भी एक उपेक्षा भाव लगातार विकसित होता जा रहा है. पहले हिंदी की नई कृतियों और कृतिकारों के बारे में अख़बारों में छपा करता था, लेकिन बाज़ारवाद की आड़ में अख़बारों में साहित्य का स्थान कम हुआ. टेलीविजन चैनलों पर तो साहित्य के लिए जगह ही नहीं बची. उधर अंग्रेजी में स्थिति इसके उलट है. चेतन भगत और नटवर सिंह की किताबें छपने के पहले ही मीडिया ने उन्हें हिट करा दिया. हिंदी साहित्य को जनता तक पहुंचाने के लिए एक सामूहिक प्रयास की ज़रूरत है, जिसके लिए प्रकाशकों को पहल करनी होगी और लेखकों एवं मीडिया को उसमें सहयोग करना होगा. अगर ऐसा होता है, तो हिंदी में किताबों के संस्करण तीन सौ से बढ़कर हज़ारों में पहुंच सकते हैं. ■

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)
anant.ibn@gmail.com

किताब मिली

पुस्तक	लेखक
महानायक नरेंद्र मोदी	कुमार पंकज
प्रकाशक	**मूल्य**
डायमंड बुक्स, नई दिल्ली	125 रुपये

नरेंद्र दामोदर दास मोदी इससे पहले भी पत्रकार कुमार पंकज की लेखनी का विषय बन चुके हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में. और, तब दूरद्रष्टा नरेंद्र मोदी के नाम से एक पुस्तक बाज़ार में आई थी. अब जबकि गुजरात से निकल कर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं, तो कुमार पंकज ने एक बार फिर उन पर अपनी कलम चलाई है. 17 अध्यायों वाली इस पुस्तक में नरेंद्र मोदी के अब तक के सफर का वर्णन किया गया है. नरेंद्र मोदी को क़रीब से जानने की चाह रखने वालों के लिए यह पुस्तक उपयोगी साबित हो सकती है.

लेखक और प्रकाशक इस कॉलम के लिए अपनी किताबें हमें भेज सकते हैं.
चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301
ई-मेल: feedback@chauthiduniya.com

रूसी कहानी

मोटा और पतला

एंटन चेखव

रूस के महान साहित्यकारों में शुमार किए जाते हैं. लघु कथा लेखन के क्षेत्र में उनका योगदान सिर्फ़ रूस तक ही सीमित नहीं रहा. कथा लेखन की विधा में वह दुनिया भर में मशहूर हैं. विश्व की कई अलग-अलग भाषाओं में उनकी लघुकथाओं का अनुवाद किया गया है. चेखव साहित्यकार होने के साथ-साथ एक डॉक्टर भी थे. उन्होंने साहित्य लेखन के साथ अपना डॉक्टरी का पेशा भी पूरे जीवन जारी रखा. उन्होंने द आर्टिस्ट वाइफ, द ट्रायल, लेडी विद द लिटिल डॉग और ऐट द बारबर्स जैसी विश्व प्रसिद्ध लघुकथाएं लिखी हैं.

दो दोस्त थे, एक मोटा और एक पतला. दोनों एक दिन वेनिकोलाएवस्की स्टेशन पर मिले. मोटे ने कुछ ही देर पहले स्टेशन पर खाना खाया था. उसके होठों पर अभी भी चिकनाई नज़र आ रही थी, उसके बदन से खाने की खुशबू आ रही थी. पतला अभी ट्रेन से उतरा था. वह संदूक, बंडल और डिब्बों से लदा हुआ था. उसके बदन से कॉफी ग्राउंड और मीट की गंध आ रही थी. एक पतली-सी महिला और एक लंबा-सा लड़का उसके पीछे-पीछे थे. लंबी ठोड़ी वाली यह महिला उसकी पत्नी थी. स्कूल जाने की उम्र का लड़का उसका बेटा था.

पतले को देखते ही मोटा चिल्लाया, पोरफिरी, मेरे दोस्त ...यह तुम ही हो ना? कितनी गर्मियां बीत गईं और कितनी सर्दियां बीतीं तुम्हें देखे बिना.

खुदाया शुक्र! पतला चिल्लाया, मीशा, मेरे बचपन के दोस्त...तुम कहां से टपक पड़े?

दोनों दोस्तों ने एक-दूजे को तीन बार किस किया और भरी हुई आंखों से एक-दूसरे को देखते रहे. दोनों के चेहरों से मिलने की खुशी टपक रही थी.

मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी. यह तो जबर्दस्त सरप्राइज है. देखो मुझे, आज भी मैं वैसा ही हैंडसम हूं, उतना ही प्यारा, जितना हुआ करता था. तुम कैसे हो? कुछ कमाया-धमाया? शादी की? मैंने तो शादी कर ली...देखो...यह मेरी पत्नी लूसी है. इसका पहला नाम वांतसेनबैश था...और यह है मेरा बेटा नैफनेल. थर्ड में पढ़ता है. और, यह है मेरे बचपन का दोस्त नफान्या. हम स्कूल में साथ थे, पतले ने बोलना शुरू किया, तो बोलता ही चला गया.

नैफनेल ने थोड़ा सोचा और फिर अपनी कैप उतार ली. पतला आदमी बोलता ही जा रहा था, स्कूल में तो हम बच्चे ही थे. तुम्हें याद है, स्कूल में लड़के तुम्हें कैसे चिढ़ाते थे? तुम्हारा नाम हीरोस्ट्राट्स रख दिया था, क्योंकि तुमने सिगरेट से स्कूल बुक में एक छेद कर दिया था. मेरा नाम एफयेल्ट्स रखा था, क्योंकि मुझे कहानियां सुनाने का शौक था. वह मुंह फाड़कर हंसा और फिर बोलने लगा, शर्माओ मत नफान्या, तब तो हम बच्चे ही थे. और, यह मेरी पत्नी है. क़रीब जाओ जरा...इसका नाम वांतसेनबैश है, यह लुथेरान की है...

नैफनेल ने फिर थोड़ा सोचा और अपने पिता की ओट में छिप गया. मोटे आदमी ने उत्साह से अपने दोस्त की ओर देखा और बोला, और सुनाओ दोस्त, तुम्हारा क्या हाल-चाल है? कोई नौकरी करते हो? किस पद तक पहुंचे?

मैं तो दोस्त, जज का असिस्टेंट हो गया हूं. सैलरी तो अच्छी नहीं है, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता. मेरी वाइफ म्यूजिक सिखाती है. नौकरी के अलावा मैं लकड़ी के सिगरेट-केस बनाने का काम करता हूं. तुम्हें पता है, एक केस एक रूबल का बिकता है. हां, अगर कोई दस से ज़्यादा लेता है, तो मैं थोड़ा कन्सेशन दे देता हूं. इस तरह काम चल ही जाता है. पहले तो मैं क्लर्क था, अब मेरा तबादला इस शहर में हो गया है और मुझे उसी डिपार्टमेंट में हेडक्लर्क बना दिया गया है. और तुम बताओ...मुझे यकीन है, अब तक तो तुम सिविल काउंसलर बन गए होगे..है ना?

नहीं मेरे दोस्त, उससे भी ऊंचा...अब तो मैं प्रिवी काउंसलर हो गया हूं. दो सितारे मिले हैं मुझे, मोटे ने कहा.

पतले का चेहरा उसी वक्त पीला पड़ गया. वह एकदम सख्त हो गया, लेकिन जल्दी ही उसके चेहरे ने कई दिशाओं में मुड़ते-तुड़ते हुए एक चौड़ी-सी मुस्कुराहट फेंकी. ऐसा लगा, मानो उसके चेहरे और आंखों में चमक आ गई हो. वह आधा-सा रह गया. सिकुड़ गया. उसके संदूक और बंडल भी जैसे सिकुड़ गए थे...उसकी पत्नी की ठोड़ी और लंबी हो गई. नैफनेल भी सावधान हो गया और उसने अपनी यूनिफॉर्म के सारे बटन बंद कर लिए.

योर एक्सिलेंसी...मैं...मैं तो बहुत खुश हूं. एक दोस्त... जिसे मैं अपने बचपन का दोस्त कह सकता हूं, इतना बड़ा आदमी बन गया है, खिखियाते हुए पतले ने कहा.

अरे यार छोड़ो, मोटा थोड़े गुस्से-से बोला, इस टोन की क्या ज़रूरत है? हम बचपन के दोस्त हैं और इस सरकारी जी-हुजूरी की कोई ज़रूरत नहीं है.

खुदाया खैर , योर एक्सिलेंसी! यह आप क्या कह रहे हैं ....? पतला रिरियाया. वह थोड़ा और झुक गया था, आप हमारी ओर देखें, यह तो हमारे लिए...योर एक्सिलेंसी, यह मेरा बेटा है नैफनेल...और यह मेरी पत्नी है लूसी, यह पक्का लूथरन से है...

मोटा इसके ख़िलाफ़ कुछ बोलने ही वाला था, तभी उसने देखा कि पतले के चेहरे पर मिठास और सम्मान के अजीबोग़रीब-से भाव आ गए थे. उन भावों को देखकर प्रिवी काउंसलर को घिन आने लगी. उसने पतले की ओर हाथ हिलाया और दूसरी तरफ़ मुड़ गया.

पतले ने अपनी तीन उंगलियां दबाईं. उसका पूरा शरीर झुक गया था. वह खिखिया रहा था. उसकी पत्नी भी मुस्कुराई. नैफनेल ने अपना पांव थोड़ा घिसा और कैप उतार दी. तीनों ही बहुत-बहुत उद्वेलित नज़र आ रहे थे.■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
CHAUTHI DUNIYA

चौथी दुनिया की हर खबर अब आपके Android फोन पर भी उपलब्ध,
Play Store से Download करें | CHAUTHI DUNIYA APP

मोटोरोला की स्मार्ट वॉच

स्मार्ट वॉच की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए जानी-मानी मोबाईल निर्माता कंपनी मोटोरोला बाजार में स्मार्टवॉच लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. मोटो 360 नाम की ये स्मार्ट वॉच इस महीने लॉच होगी. मोटोरोला का ये स्मार्ट वॉच एंड्रॉयड वियर सिस्टम पर काम करती है. मोटोरोला की स्मार्टवॉच के बाजार में आने के बाद कई कंपनियों की स्मार्टवॉच को कड़ी टक्कर दे सकती है. गौरतलब है कि हाल के दिनों में मोटोरोला के मोटो एक्स, मोटो जी, और मोटो इ फोन ने स्मार्टफोन बाजार में सनसनी मचा दी थी. कंपनी ने अपनी इस सफलता को और भुनाने के लिए मोटो 360 स्मार्टवॉच बाजार में उतारने का निरणय किया है. इसकी कीमत लगभग 14,000 रुपये हो सकती है.■

फिटनेस बैंड

फिटनेस बैंड की मांग बाजार में बढ़ती जा रही है, इसी को देखते हुए भारत में चीनी कंपनी जिओमी ने एमआई-3 स्मार्टफोन की धूम के बीच ही फिटनेस बैंड उतारने की घोषणा की है. जिओमी जल्द ही एमआई फिटनेस बैंड को अपनी डिवाइस लिस्ट में जोड़ने जा रही है. जिओमी एमआई बैंड एक रिस्टबैंड फिटनेस ट्रैकर है. इसकी कीमत 790 रुपये होगी. कीमत कम होने के कारण कंपनी को इसकी जबरदस्त बिक्री होने की उम्मीद है. कंपनी का कहना है कि इसमें वे सभी सुविधाएं दी गई हैं जो अन्य रिस्टबैंड्स में होती हैं. कंपनी को आशा है कि उनका यह उत्पाद भारत में भी सफल होंगा.■

सोनी ने लॉन्च किए दो नए हेडफोन्स

सोनी इंडिया ने भारतीय बाजार में दो नए हेडफोन्स उतारे हैं. इनका मॉडल नंबर है एमडीआर-एक्सबी-450 और एमडीआर-एक्सबी-250. ये हेडफोन्स भारतीय म्यूजिक प्रेमियों के लिए लॉन्च किए गए हैं. सोनी के की एमडीआर-एक्सबी450 कीमत 1490 रुपये है और एमडीआर-एक्सबी250 की कीमत 2190 रुपये रखी गई है. ऑनलाइन स्टोर के अलावा, ये हेडफोन्स जल्द ही रिटेल में भी बिक्री के उपलब्ध होंगे. ये हेडफोन्स रेड, ब्लैक, व्हाइट, यलो और ब्लू रंग में मिलेंगे. एमडीआर-एक्सबी450 में 30 एमएम के ड्राइवर्स लगे हुए हैं. ये हेडफोन 5 गीगाहट्र्ज से लेकर 22000 गीगाहट्र्ज तक फ्रिक्वेंसी दे सकता है.■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

फॉक्सवैगन की नई कार

पैकेज में जीपीएस नेविगेशन, ब्लूटूथ टेलीफोनी और सोशल नेटवर्क कनेक्टिविटी की पेशकश की गई है.

फॉक्सवैगन ने सेडान कार वेंटो कनेक्ट को लॉन्च की है. इसमें ब्लापंक्ट इन्फोटेनमेंट सिस्टम, जीपीएम नैविगेशन आदि शामिल हैं. पैकेज में जीपीएस नेविगेशन, ब्लूटूथ टेलीफोनी और सोशल नेटवर्क कनेक्टिविटी की पेशकश की गई है. वेंटो कनेक्ट का पेट्रोल संस्करण 7.84 लाख रुपये से 9.8 लाख रुपये के बीच, जबकि डीजल संस्करण 8.99 लाख रुपये से 9.8 लाख रुपये के बीच उपलब्ध है.■

महिंद्रा का 125सीसी स्कूटर

महिंद्रा ने स्पोर्टी न्यू रोडियो यूजेडओ 125 स्कूटर को भारतीय बाजार में लॉन्च किया है. कंपनी ने नए स्कूटर को पहले से ज्यादार स्टाइलिश, ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस और यूनिक फीचर्स के साथ लॉन्च किया है.

महिंद्रा रोडियो यूजेडओ स्टैंडर्ड स्कूटर रोडियो का प्रीमियम वर्जन है. नए वर्जन में कंपनी ने टू टोन डुअल टेक्स्चर सीट और रंगीन व्हील का इस्तेमाल किया है. रोडियो यूजेडओ एडवांस डीसीडीआई टेक्नोलॉजी और एटीएलए सिस्टम पर काम करता है. इस स्कूटर में मोबाइल चार्जिंग प्वाइंट और एंटी-थेफ्ट लॉक जैसे फीचर्स आपको मिलेंगे. साथ ही, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो स्पीडोमीटर, टेकोमीटर, ट्रिप मीटर, क्लॉक, हाई स्पीड वॉर्निंग अलार्म और ओडोमीटर साथ है. कंपनी का दावा है कि 59 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देगा. इसकी कीमत 49,957 रुपये रखी गई है. ■

इस स्कूटर में मोबाइल चार्जिंग प्वाइंट और एंटी-थेफ्ट लॉक जैसे फीचर्स आपको मिलेंगे.

रिलायंस डिजिटल ने लॉन्च किया नया रीकनेक्ट स्मार्टफोन

रिलायंस डिजिटल ने अपना तीसरा रीकनेक्ट स्मार्टफोन मॉडल नंबर आरपीएपीइ-4701 लॉन्च किया है. इस फोन में 1.3 गीगाहट्र्ज का क्वार्ड-कोर प्रोसेसर दिया गया है. इस फोन में एंड्रॉयड 4.2.2 जेलीबीन ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है. इस फोन की स्क्रीन 4.7 इंच की है जो 720 गुणा 1280 पिक्सल का रेजोल्यूशन देती है. इसमें 13 मेगापिक्सल का कैमरा है और इसकी बैटरी 2000 एमएएच की है. इस फोन की कीमत 12999 रुपए रखी गई है.■

1200 सीसी इंजन की इंडियन स्कॉट बाइक

मशहूर यूएस ब्रांड इंडियन मोटरसाइकिल की बाइक स्कॉट भारत में जल्द ही लॉन्च होने वाली है. इंडियन स्कॉट मोटर साईकिल की सबसे खास बात इसका पावर है जो किसी को भी आकर्षित कर सकता है. कंपनी ने इसमें 1133 सीसी वी-ट्विन लिक्विड कूल्ड इंजन दिया है, जो 100 बीएपी का पावर और 98 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है. इस बाइक में 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स लगे हैं. जबकि इंजन का पावर पहियों तक एक बेल्ट ड्राइव के तहत पहुंचता है और इसमें चेन नहीं लगी है. सेफ्टी फीचर्स के तौर पर इसमें एबीएस स्टैंडर्ड तौर पर दिया गया है. इसकी कीमत यूएस में 6.5 लाख रुपये के लगभग है, लेकिन भारत में यह कितने में मिलेगी इसके बारे में कोई खुलासा नहीं किया गया है.■

माइक्रोमैक्स कैनवास नाइट कैमियो 290

भारतीय कंपनी माइक्रोमैक्स ने एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है. यह एक डुअल सिम फोन है और ओक्टा कोर प्रॉसेसर से लैस है. इस फोन की स्क्रीन 4.7 इंच की है और इसका रियर कैमरा 8 मेगापिक्सल का है जिसमें एलईडी फ्लैश है. इसका फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल का है. इस स्मार्टफोन का डिजाइन कैनवास नाइट 350 की ही तरह है. यह डुअल सिम फोन है और इसमें 1 जीबी रैम और 8 जीबी इंटरनल स्टोरेज है. इसमें कई तरह के एप्लीकेशंस पहले से लोड हैं जैसे क्यूब 26, ऐमेजॉन, बुक माई शो, हाइक, एमएडी, ओपरा मिनी, यात्रा, जैपर. यह फोन 3जी, वाई-फाई 802.11, ब्लूटुथ से लैस है. इस फोन की बैटरी 2,000 एमएएच की है इसकी कीमत 11,490 रुपये है.■

"इस फोन की स्क्रीन 4.7 इंच की है और इसका रियर कैमरा 8 मेगापिक्सल का है जिसमें एलईडी फ्लैश है. इसका फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल का है."

गूगल का स्पियर कैमरा ऐप

गूगल ने अपने लोकप्रिय फोटो स्पियर कैमरा ऐप को अब एप्पल डिवाइसेस के लिए भी लॉन्च कर दिया है. पहले ये ऐप सिर्फ एंड्रॉयड यूजर्स के लिए ही उपलब्ध था. नया कैमरा ऐप आईओएस 7 पर काम करता है और आईफोन 5 या उससे ऊपर के आईफोन पर काम कर सकता है. कंपनी का ये ऐप 19 अगस्त (वर्ल्ड फोटोग्राफी डे) के दिन लॉन्च हुआ. ये ऐप सबसे पहले नेक्सस 4 में 2012 में लॉन्च किया गया था. ये ऐप गूगल स्ट्रीट व्यू जैसे इफेक्ट्स ऐप के द्वारा ली गई तस्वीरों में जोड़ देता है. ऐप की मदद से पिक्स इंटरनेट पर भी अपलोड की जा सकती हैं. इस ऐप के अलावा, स्पियर 360 डिग्री फोटोग्राफी ऐप का इस्तेमाल भी यूजर्स कर सकते हैं.

म्यूजिक के दीवानों के लिए गैजेट

कार में लंबे सफर पर संगीत सुनना सभी को पसंद होता है. मगर संगीत में खोकर अगर आप रास्ता भूल जाएं तो मुश्किल हो सकती है. इस समस्या से निपटने के लिए पायनियर इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स ने एविक-एफ60 बीटी इन-कार एंटरटेनमेंट सिस्टम लॉन्च किया है. यह एक प्रीमियम ऑडियो-वीडियो सिस्टम है, जो मैप माइ इंडिया के नए नेविगेशन मैप्स से युक्त है. इसमें हाइब्रिड नेविगेशन सॉल्युशन सिस्टम के साथ-साथ 13 बैंड ग्राफिक इक्वालाइजर, पर्सनलाइज्ड से लेकर डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर और हाई टॉलरेंस अकाउस्टिक कैपेसिटर सिस्टम जैसे फीचर्स भी शामिल हैं.

इसे ऑपरेट करना भी काफी आसान है. एंड्रॉयड और आईओएस यूजर्स इसे अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट करके आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें बिल्ट-इन मिरर-लिंक है. लर्निंग स्टीयरिंग व्हील रिमोट कंट्रोल, डुअल बैकअप कैमरा ऑप्शन, एचडी वीडियो प्लेबैक जैसे फीचर्स भी इसे खास बनाते हैं. इसकी कीमत लगभग 50 हजार रुपये रखी गई है.■

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

भारतीय क्रिकेट टीम जिस तरह इंग्लैंड के खिलाफ शुरूआती बढ़त लेने के बावजूद हारी है, ऐसे में बोर्ड की काफी किरकिरी हो रही है. इस बात को दबाने के लिए उन्होंने यह दिखाने की कोशिश की है कि देखिए हमने रवि शास्त्री को डायरेक्टर बना दिया है, लेकिन रवि शास्त्री के आने से टेस्ट सीरीज के शर्मनाक परिणाम तो नहीं बदल जाएंगे. क्रिकेट में डायरेक्टर का क्या रोल है यह समझ से पर है.

आईपीएल बना टेस्ट क्रिकेट का काल ?

फोटो-सुनील मल्होत्रा

टेस्ट मैचों में भारत की भद पिटने का सबसे बड़ा और प्रमुख कारण आईपीएल है. युवा खिलाड़ी टेस्ट टीम के बजाए आईपीएल टीम में जगह बनने की कोशिश करते हैं, यहीं से खिलाड़ी की गुणवत्ता में फर्क आने लगता है. आईपीएल में आए अपार धन ने भारत को गहरी और ऐसी जगह चोट पहुंचाई है जिसे न तो वो दिखा सकता है न छिपा सकता है.

नवीन चौहान

भारतीय टीम की लगातार दूसरी बार इंग्लैंड दौरे पर शर्मनाक हार हुई है. इस बार भारतीय टीम को 3-1 से हार मिली है जबकि पिछले दौरे के दौरान भारत का सूपड़ा साफ हो गया था. भारतीय टीम चार मैंचों की सीरीज में 4-0 से हार हो गई थी. महेंद्र सिंह धोनी अपना कोई विकल्प न उपलब्ध होने की वजह से फिलहाल बच गए हैं, लेकिन कोच डंकन फ्लेचर के सिर पर तलवार लटक गई है. फिलहाल बीसीसीआई ने पूर्व कप्तान रवि शास्त्री को टीम का डायरेक्टर नियुक्त कर दिया गया है. बीसीसीआई के इन निर्णयों का सीधा मतलब यह है कि जल्दी ही डंकन फ्लेचर की भारतीय क्रिकेट टीम के कोच के पद से छुट्टी हो जाएगी. उनके पास टीम के कोच के रूप में गिने-चुने दिन ही बचे हैं. बीसीसीआई ने तत्काल फ्लेचर की छुट्टी का फरमान इसलिए जारी नहीं किया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में होने वाले विश्वकप में कुछ ही महीने का समय बाकी है. ऐसे में एक ही झटके में कोच को पद से हटा देने से भारतीय टीम की तैयारियों पर बुरा असर पड़ेगा और विश्व चैंपियन का खिताब बचाना टीम इंडिया के लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा. ऐसे में उसने ऐसे भारतीय खिलाड़ियों की टीम में प्रशिक्षकों के रुप में नियुक्ति कर दी है, जिन्हें भारतीय क्रिकेट में सचमुच दिलचस्पी है. इन लोगों को किसी व्यावसायिक हित में दिलचस्पी नहीं है. फ्लेचर की छुट्टी होने से पहले ये लोग टीम की दूरदर्शी नीतियों और खिलाड़ियों की जरुरतों को समझ पाएंगे. इस लिहाज से बीसीसीआई ने सही निर्णय लिया है.

विश्वकप खिताब बचाने के लिए भारतीय टीम को गुरु ग्रैग की तरह टीम को एक जुट करने और टीम को प्रोत्साहित करने वाले कोच की अदद जरूरत है. टीम जिस बुरे दौर से गुजर रही है उसमें बदलाव अचानक नहीं होगा, इसके लिए प्रशंसकों को थोड़ा धैर्य बरतना होगा. फ्लेचर का इंग्लैंड दौरे के बाद वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली घरेलू सीरीज तक उनका टीम के साथ बने रहना मुश्किल हो सकता है. रवि शास्त्री के डायरेक्टर बनने बाद उनके पास को कोई अधिकार नहीं बचे हैं. टीम से जुड़े फैसले रवि करेंगे और फ्लेचर को भी यह बात अच्छी तरह पता है. इस समय सहायक स्टाफ में उनकी कोई पसंद नहीं है और डंकन को पीछे हटना पड़ेगा. यदि फ्लेचर इस्तीफा देते हैं, तो बीसीसीआई उन्हें रोकेगा नहीं. ऐसे भी फ्लेचर को पद छोड़ने के संकेत दिए जा चुके हैं. अब रवि शास्त्री और कप्तान महेंद्र सिंह धोनी मिलकर टीम की रणनीति बनाएंगे. शास्त्री के अलावा जिन लोगों की टीम में बतौर कोचिंक स्टाफ नियुक्ति की गई है, वो खुद को साबित कर चुके हैं. पिछले आईपीएल सीजन में संजय बांगड़ किंग्स इलेवन पंजाब के कोच के रुप में खुद को उपयोगी साबित कर चुके हैं. उनकी सूझबूझ और प्रशिक्षण की बदौलत ही किंग्स इलेवन पंजाब आईपीएल के फाइनल तक पहुंची थी. बांगर टीम के युवा सदस्यों को भी जानते हैं. बतौर गेंदबाजी कोच अरुण की नियुक्ति भी जायज है, क्योंकि टीम में अभी जो भी तेज़ गेंदबाज हैं उन्होंने एनसीए में अरुण के मार्गदर्शन में ही गंदबाजी के गुर सीखे हैं. इसके साथ ही आर श्रीधर को फील्डिंग कोच की भूमिका दी गई है ऐसे में डंकन के विदा होने के बाद अलग-अलग लोग मिलकर टीम की जिम्मेदारी संभालेंगे. वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू सीरीज के दौरान नए स्टाफ को टीम के साथ घुलने-मिलने और समझने का मौका मिलेगा. फ्लेचर के साथ बीसीसीआई का अनुबंध 2015 विश्वकप के बाद तक है, लेकिन अनुबंध में उन्हें उससे पहले भी हटाए जाने का प्रावधान है. हालांकि राहुल द्रविड़ को टीम का कोच बनाए जाने पर भी बीसीसीआई ने विचार किया था, लेकिन राहुल इसे लेकर अधिक उत्साहित नहीं थे, क्योंकि बतौर कोच परिवार को छोड़कर काफी यात्रा करनी पड़ती है.

रवि शास्त्री एन श्रीनिवासन के बेहद करीबी हैं इसलिए हार के कारणों पर लीपा-पोती करने की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है. हकीकत में यह भद्दा मजाक है. इस वक्त बात तो टेस्ट क्रिकेट में भारत की बदहाली की होनी चाहिए. क्या बोर्ड की जिम्मेदारी नहीं है कि वह पिछले तीन-चार साल में टीम की हालत की जिम्मेदारी खुद ले.

बीसीसीआई के इस निर्णय से भारतीय क्रिकेट की बदहाली को लेकर उठे सवाल शांत नहीं हुए हैं. खेल के जानकर जहां इस नियुक्ति से हैरान हैं, वहीं उन्हें लगता है कि रातों-रात कुछ नहीं बदलने वाला है. खेल पंडितों का कहना है कि रवि शास्त्री डायरेक्टर बनकर कौन सा तीर मार लेंगे. वह रातों-रात टीम को प्रदर्शन सुधारने के लिए ऐसा कौन सा मंत्र दे देंगे. टेस्ट मैचों में हार के बाद टीम इंडिया वनडे सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करेगी, तो वह अपने बल बूते पर खेलेगी. इसलिए शास्त्री की नियुक्ति को हार के कारणों को छुपाने के लिए की गई है. रवि शास्त्री एन श्रीनिवासन के बेहद करीबी हैं, इसलिए हार के कारणों पर लीपा-पोती करने की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है. हकीकत में यह भद्दा मजाक है. इस वक्त बात तो टेस्ट क्रिकेट में भारत की बदहाली की होनी चाहिए. क्या बोर्ड की जिम्मेदारी नहीं है कि वह पिछले तीन-चार साल में टीम की हालत की जिम्मेदारी खुद ले. इसके लिए वह कोच को कसूरवार न ठहराएं. मैदान पर खिलाड़ी खराब या अच्छा खेलते हैं, उसके लिए बीसीसीआई की नीतियां खिलाड़ियों के खराब प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार हैं. पैसा पैसा और पैसा बीसीसीआई केवल यही मंत्र जप रहा है.

भारतीय क्रिकेट टीम जिस तरह इंग्लैंड के खिलाफ शुरूआती बढ़त लेने के बावजूद हारी है, ऐसे में बोर्ड की काफी किरकिरी हो रही है. इस बात को दबाने के लिए उन्होंने यह दिखाने की कोशिश की है कि देखिए हमने रवि शास्त्री को डायरेक्टर बना दिया है, लेकिन रवि शास्त्री के आने से टेस्ट सीरीज के शर्मनाक परिणाम तो नहीं बदल जाएंगे. क्रिकेट में डायरेक्टर का क्या रोल है यह समझ से परे है. क्रिकेट में हेड कोच, सहायक कोच, फील्डिंग, बैटिंग, गेंदबाजी कोच सहायक कोच होते हैं, लेकिन डायरेक्टर नहीं. रवि शास्त्री के पास कितनी ताक़त होगी, वह कैसे काम करेंगे, क्या उनके पास कप्तान और कोच के फैसलों के खिलाफ वीटो पावर होगी?अभी ऐसा कुछ भी कह पाना मुश्किल है. किसी भी चीज के बनने और बिगड़ने में वक्त लगता है. चाहे वह रवि शास्त्री हों, संजय बांगड़ हों, भारत अरुण हों या फिर श्रीधर. उन्हें समय देना पडेगा. एक सिरीज़ से किसी भी बदलाव की उम्मीद अभी करना बेमानी है. भारतीय क्रिकेट में जो विकृति पिछले 4-5 सालों में आई है, उसे बदलने में वक्त लगेगा. सब कुछ एक झटके में ठीक हो जाएगा यह सोच गलत है.

लोगों को इस बात की शंका होने लगी है कि भारतीय खिलाड़ी टेस्ट मैच खेलना चाहते भी या नहीं. टेस्ट क्रिकेट एक खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होते हैं. टेस्ट मैच खेलने के लिए कड़ी मेहनत, कौशल और लगन की आवश्यकता होती है. टेस्ट मैच खिलाड़ी की शारीरिक, मानसिक और तकनीकि क्षमता का टेस्ट होते हैं. भारतीय खिलाड़ी इन तीनों फ्रंट पर लगातार फेल हो रहे हैं. इसके साथ ही भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के दौरान दोयम दर्जे की फील्डिंग की है. कैचेज विन मैचेज, यह कहावत भारतीय टीम के परिपेक्ष्य में बिलकुल सही साबित हुई है. किसी भी टीम पर आप कैच छोड़कर दबाव नहीं बना सकते हैं. जीतने के लिए आपको कैच लपकने होंगे. एक गेंदबाज मेहनत करके आपके लिए मौके बनाता है आप कैच छोड़ दें तो यह बहुत निराशाजनक होता है. इसके बाद गेंदबाज गेंदबाजी की प्लानिंग को छोड़कर काम करने लगता है, यह प्रयास गेंदबाज की लाइन लेंथ को प्रभावित करता है. भारतीय खिलाड़ियों को एक बार फिर से बेसिक्स पर ध्यान देना होगा. पहले भारतीय टीम जब विदेश दौरे पर जाती थी तो उसे वहां के वातावरण और पिचों के अनुकूल ढ़लने में थोडा वक्त लगता था. शुरूआती मैचों में भारतीय खिलाड़ी संघर्ष करते दिखाई देते थे, लेकिन जैसे-जैसे सीरीज आगे बढती थी भारतीय खिलाड़ी परिस्थितियों के अनुकूल ढ़ल जाते थे, लेकिन इस बार आगाज अच्छा हुआ, लेकिन अंजाम बहुत बुरा. ऐसा किसी ने सोचा नहीं था. पहले दो टेस्ट में बढ़त बना लेने के बाद लगातार तीन टेस्ट मैच बिना संघर्ष किए हार जाना बहुत निराशाजनक है. खिलाड़ियों को शर्म आनी चाहिए कि देश का प्रतिनिधित्व करने गए खिलाड़ी देश के लिए संघर्ष भी नहीं कर सके, अधिकांश समय वो घुटने के बल चलते दिखाई दिए.

टेस्ट मैचों में भारत की भद पिटने का सबसे बड़ा और प्रमुख कारण आईपीएल है. युवा खिलाड़ी टेस्ट टीम के बजाए आईपीएल टीम में जगह बनने की कोशिश करते हैं, यहीं से खिलाड़ी की गुणवत्ता में फर्क आने लगता है. आईपीएल में आए अपार धन ने भारत को गहरी और ऐसी जगह चोट पहुंचाई है जिसे न तो वो दिखा सकता है न छिपा सकता है. दिखा इसलिए नहीं सकता है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है, तो आईपीएल से होने वाली आमदनी बंद हो जाएगी. छिपा इसलिए नहीं सकता, क्योंकि आईपीएल भारतीय खिलाड़ियों की कमजोरियां टेस्ट मैचों में दिखाई देने लगती हैं. भारतीय खिलाड़ी सीमित ओवर का क्रिकेट खेलने के लिए फिट हैं, लेकिन पांच दिन तक टेस्ट मैच खेलना उनके बस में नज़र नहीं आ रहा है. खिलाड़ियों मे न तो पिच में टिकने का संयम है न ही खेल की बेहतर तकनीक. टी-20 क्रिकेट का किसी भी तरह रन बना लेने वाला अंदाज बल्लेबाजों के लिए घातक हो गया है. गेंदबाज विकेट लेने से ज्यादा रन बचाने में लगे रहते हैं. स्पिनर्स गेंद को फ्लाइट कराने से बचते दिखते हैं. टेस्ट क्रिकेट में जीत दर्ज करने के लिए विपक्षी टीम को दो बार आउट करना होता है. ये क्रिकेट के बेसिक्स हैं. अर्जुन रणतुंगा जैसे खिलाड़ियों ने आईपीएल की शुरूआत के दौरान ही इसका विरोध किया था. तब उनके जैसे कई खिलाड़ियों ने आशंका जताई थी की टेस्ट क्रिकेट को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी. आज ये नौबत आ गई है कि देश में अच्छे टेस्ट खिलाड़ियों का अकाल पड़ गया है. आईपीएल में खेलने वाले बहुत से खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट की वैल्यू की बात करने लगे हैं. इसका सीधा अर्थ है कि खिलाड़ी एक बार फिर जड़ों की ओर लौटना चाहते हैं. लेकिन पैसे और बाजार के दबाव में खिलाड़ियों के अरमान कुचले जा रहे हैं. आईपीएल भारतीय टेस्ट क्रिकेट का काल बन गया है.■

navinonline2003@gmail.com

कम बजट और बग़ैर किसी बड़े स्टार की फिल्में क्यों असफल होती हैं, दरअसल इसके कई कारण हैं. पहला कारण यह है कि बॉलीवुड में काफ़ी फिल्में बन रही हैं. इस वजह से फिल्म इंडस्ट्री में प्रतिस्पर्धा काफ़ी बढ़ गई है. बड़े बजट की फिल्मों के सामने छोटी बजट की फिल्में नहीं टिक पातीं, क्योंकि मगरमच्छ के सामने छोटी मछली का न आना ही उसके अस्तित्व के लिए अच्छा होता है.

यह इश्क नहीं आसान

संजीव कमल जुल्का

भारत जैसे देश में फिल्म निर्माण कोई आसान नहीं, बल्कि बेहद जोखिम भरा काम है. ख़ास तौर पर कम बजट और बग़ैर किसी बड़े स्टार की ज़्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस में असफल रहती हैं. साल 2014 आधा बीत चुका है, लेकिन कम बजट की कोई भी फिल्म अभी तक सफलता का स्वाद नहीं चख सकी हैं. ऐसी स्थिति पिछले कई वर्षों से लगातार देखी जा सकती है. ग़ौरतलब है कि छोटी और कम बजट की फिल्मों की सफलता का ट्रेंड फिल्म भेजा फ्राई से शुरू हुआ था. बग़ैर किसी बड़े फिल्मी स्टार के इस फिल्म ने अपनी सफलता के नए मुक़ाम तय किए थे. भेजा फ्राई के बाद खोसला का घोंसला और फंस गए ओबामा जैसी फिल्मों ने भी खूब कमाई की. इस फ़ेहरिस्त में शामिल होने वाली हालिया फिल्म इरफान खान की किरदार वाली लंच बॉक्स थी. हालांकि, बॉलीवुड में ऐसी फिल्में काफ़ी कम हैं.

कम बजट और बग़ैर किसी बड़े स्टार की फिल्में क्यों असफल होती हैं, दरअसल इसके कई कारण हैं. पहला कारण यह है कि बॉलीवुड में काफ़ी फिल्में बन रही हैं. इस वजह से फिल्म इंडस्ट्री में प्रतिस्पर्धा काफ़ी बढ़ गई है. बड़े बजट की फिल्मों के सामने छोटी बजट की फिल्में नहीं टिक पातीं, क्योंकि मगरमच्छ के सामने छोटी मछली का न आना ही उसके अस्तित्व के लिए अच्छा होता है. छोटी फिल्मों के निर्माता बड़ी फिल्मों की होड़ में ख़ुद के लिए ऐसी जगह तलाशते हैं, जहां कम से कम वे अपनी लागत निकाल लें. वॉलीवुड में लगातार बन रही फिल्मों के बीच छोटी फिल्मों के निर्माताओं के लिए स्पेस नहीं मिल पाता. यदि कोई सप्ताह खाली मिल भी जाए, तो छोटी फिल्मों की बाढ़ आ जाती है. ऐसे में दर्शकों के लिए यह चयन कर पाना मुश्किल होता है कि वह कौन सी फिल्म देखे. इतना ही नहीं, छोटी बजट वाली फिल्मों को छोटे पर्दे यानी टेलीविजन से भी कड़ी टक्कर मिल रही है. फिल्म इंडस्ट्री की शब्दावली में शुक्रवार से रविवार तक के समय को बिजनेस वीक एंड कहा जाता है. इस दौरान बड़े फिल्मी स्टारों की फिल्में और कार्यक्रम भी छोटे पर्दे पर प्रसारित होती हैं. यही वजह है कि ज़्यादातर दर्शक छुट्टियों के दिनों में भी घर में टीवी पर फिल्म देखना अधिक पसंद करते हैं. जानकारों की मानें, तो फिल्मों को अब खेलों से भी टक्कर मिलने लगी है. हाल के कुछ वर्षों में इंडियन प्रीमियर लीग और इंडियन बैडमिंटन लीग जैसी प्रतियोगिता शुरू होने से दर्शकों का रुझान फिल्मों के प्रति घटा है. अगर हफ्ते में एक बार कोई दर्शक फिल्म देखने के लिए वक्त निकाल भी लें, तो उनकी रूचि बड़ी बजट और बड़े स्टारों की फिल्म देखने में होती है. आईपीएल के दौरान तो बड़े निर्माता भी अपनी फिल्म रिलीज करने से कतराते हैं. जिस समय बड़ी फिल्में रिलीज नहीं होती हैं, उन दिनों कम बजट वाले फिल्म निर्माता अपनी फिल्म रिलीज करते हैं. दुर्भाग्य की बात यह है कि छोटी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट जाती हैं. मध्यम या बड़े बजट की फिल्में अच्छी मार्केटिंग की वजह से चल जाती हैं, चाहे वह फिल्म कितनी भी ख़राब क्यों न हो. भारत जैसे देश में दर्शकों की काफ़ी बड़ी संख्या है. मल्टीप्लेक्स बनने के बाद फिल्म देखने के प्रति लोगों की रूचि बढ़ी है. हालांकि, मल्टीपलेक्स में फिल्म देखने वालें दर्शकों का वर्ग दूसरा है. इन सिनेमाघरों में बड़ी बजट की फिल्म प्रदर्शित होती हैं, जो अमूमन कामयाब भी होती हैं.

फिल्मों की कामयाबी का एक ही मंत्र है इंटरटेन्मेंट. इसके लिए फिल्म की कहानी, संगीत और अभिनय बेहतरीन होना चाहिए. पटकथा ऐसी, जो दर्शक को पूरे समय बांधे रखे. अन्य

उद्योगों की अपेक्षा फिल्म निर्माण में जोखिम ज़्यादा है. यहां कोई भी ऐसा एसेट नहीं होता है, जिससे घाटे की भरपाई की जा सके. अब प्रश्न यह उठता है कि इतने जोखिम के बाद भी लोग फिल्म क्यों बनाते हैं. एक तरफ टेलीविजन इसके लिए चुनौती भी बना है, तो दूसरी तरफ यह फिल्मों को राहत भी देता है. आजकल फिल्मों के ब्राडकास्टिंग राइट्स फिल्मों की रिलीज से पहले ही बिक जाते हैं, ऐसे में निर्माता को लागत का 50 से 60 प्रतिशत पैसा पहले ही मिल जाता है. ऐसे में उन पर दबाव कम हो जाता है. कई बार फिल्मों की कुल लागत का 80 प्रतिशत तक पैसा टीवी राइट्स बेचने से ही वसूल हो जाता है. ■

प्लेब्वॉय में शर्लिन का न्यूड पोस्टर

जानी मानी प्लेब्वॉय पत्रिका ने मॉडल शर्लिन चोपड़ा का न्यूड फोटो जारी किया है. यह फोटो शूट उन्होंने दो साल पहले करवाया था. इसके साथ ही वह भारत की ऐसी पहली मॉडल बन गईं हैं जिसका न्यूड फोटो प्लेब्वॉय में छापा गया है. शर्लिन कामसूत्र 3-डी से चर्चा में आईं थीं. प्लेब्वॉय में फोटो जारी होने के बाद शर्लिन ने कहा कि वह बहुत खुश हैं कि दो साल के इंतजार के बाद उनका फोटो सार्वजनिक हुआ है. सबसे अच्छी बात यह कि उनकी यह तस्वीर स्वतंत्रता दिवस के दिन सार्वजनिक की गई. प्लेब्वॉय के लिए फोटो शूट आजादी का अनुभव करने वाला सबसे बढ़िया पल था. शर्लिन चोपड़ा अपने को चर्चा में रखने के लिए हमेशा इस तरह का काम करती रही हैं. वे अपने ट्विटर अकाउंट के जरिये अपने फैंस तक अपनी तस्वीरें पहुंचाती रहती हैं. इसके पहले एक घोड़े पर न्यूड राइडिंग करती हुई उनकी तस्वीर ने बहुत सुर्खियां बटोरी थीं. ■

क्या है करीना की ख़ुशी का राज़

अभिनेत्री करीना कपूर का कहना है कि शादी करने से उनके फिल्मी करियर पर कोई असर नहीं पड़ा है. उनका कहना है कि वह शादी करके खुश हैं. करीना ने 2012 में छोटे नवाब सैफ अली खान के साथ शादी की थी. इसके बाद भी उन्होंने बॉलीवुड के सबसे बड़े कलाकारों सलमान, अजय देवगन और आमिर जैसे कलाकारों के साथ फिल्मे की हैं. करीना कहती हैं कि वह दूसरी शादीशुदा अभिनेत्रियों की तुलना में लकी हैं. वह कहती हैं कि उन्हें नहीं लगता कि बहुत सारी शादीशुदा अभिनेत्रियों को ऐसे मौके मिल पाते हैं. उन्हें फिल्मों में मुख्य भूमिका नहीं मिल पाती है या कई बार वो अच्छी स्क्रिप्ट का इंतजार करती हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ. शादी ने मेरे करियर को बिल्कुल प्रभावित नहीं किया. मैं खुशनसीब हूं कि ऐसे अभिनेताओं के साथ काम कर रही हूं जो अभिनेता एक 18 साल की अभिनेत्री के साथ काम कर सकते हैं. ■

राजकपूर पर फिल्म बनाना चाहते है रणवीर कपूर

बॉलीवुड के रॉकस्टार, शो मैन के नाम से विख्यात अपने दादा राजकपूर के जीवन पर एक शार्ट फिल्म बनाना चाहते हैं. रणवीर का कहना है कि मेरे दादा की जिंदगी रोमांचक और मनोरंजन से भरपूर थी. हम इसपर एक अच्छी लघु फिल्म का निर्माण कर सकते है. उल्लेखनीय है कि भारतीय सिनेमा जगत में राज कपूर को पहले शो मैन का दर्जा हासिल है. राजकपूर ने न सिर्फ अपने अभिनय से बल्कि फिल्म निर्माण और निर्देशन से भी दर्शकों को अपना दीवाना बनाया है. ■

मैं अच्छा काम करना चाहता हूं: शरमन जोशी

सोचाइल फिल्म से अपना फिल्मी करियर शुरू करने वाले शरमन जोशी को फिल्मों में काम करने की जल्दी नहीं है. वो फिल्मों की सामग्री को ध्यान में रखते हैं. फरारी की सवारी, वार छोड़ न यार और गैंग ऑफ घोस्ट जैसी फिल्मों में काम करने वाले शरमन का कहना है कि वह उन फिल्मों में काम करना चाहते हैं जिसमे आनंद आता है. मैं अच्छा काम करना चाहता हूं और पूरी मेहनत करता हूं. मैं दूसरे अभिनेताओं की तरह बॉक्स ऑफिस का सामना करना पसंद करता हूं. लेकिन मैं अपनी धुन में काम करता हूं. शरमन कुछ ही समय में विक्रम भट्ट की फिल्म 1920 लंदन में मीरा चोपड़ा और फिल्म रेखा नानी में रेखा के साथ नजर आएंगे. ■

हैप्पी न्यू इयर सभी लूजर्स को समर्पित है : शाहरुख

बॉलीवुड सुपर स्टार शाहरुख खान ने अपनी आगामी फिल्म हैप्पी न्यू इयर का ट्रेलर लांच करते वक्त कहा कि उनकी फिल्म सभी लूजर्स को समर्पित है. इस फिल्म का निर्देशन फराह खान ने और निर्माण शाहरुख की कंपनी रेड चिलीज इंटरटेनमेंट ने किया है. यह फिल्म छह लूजर्स की कहानी है. सिक्स लूजर्स वन मिशन. शाहरुख ने फिल्म का ट्रेलर 15 अगस्त को लांच किया और कहा कि यह इसके लिए सही दिन है क्योंकि फिल्म में देश भक्ति का जज्बा भी है. फिल्म में शाहरुख के अलावा दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, सोनू सूद, बोमन इरानी, विवान शाह और जैकी श्राफ भी हैं. यह फिल्म दीवाली में रिलीज होगी. शाहरुख का कहना है कि यह फिल्म त्यौहार के मौके को ज्यादा खुशनुमा बना देगी. यह फिल्म एक लंबे अंतराल के बाद शाहरुख की रिलीज हो रही फिल्म है. इसके पहले शाहरुख पिछले साल दीपिका पादुकोण के साथ चेन्नई एक्सप्रेस में नज़र आए थे. शाहरुख और दीपिका की यह तीसरी फिल्म है. ओम शांति ओम, चेन्नई एक्सप्रेस के बाद यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सफलता की नई इबारत लिखेगी. ■

सलमान की किक का सीक्वल बनाने की चाह

बॉलीवुड के दबंग स्टार सलमान खान अपनी सुपर हिट फिल्म किक का सीक्वल बनाना चाहते हैं. हाल ही में रिलीज हुई यह फिल्म सलमान के करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म है. फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 374 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की है. इसकी सफलता को देश सलमान इस फिल्म का सीक्वल बनाना चाहते हैं. हालांकि सलमान को फिल्म का सीक्वल बनाना पसंद नहीं है. इसके पहले वह दबंग के सीक्वल दबंग 2 में काम कर चुके हैं. फिलहाल वह नो एंट्री के सीक्वल में काम कर रहें हैं. वह किक की सफलता से वहुत उत्साहित हैं और चाहते हैं कि इस सुपरहिट फिल्म की सीक्वल जल्द बनाई जाए. सलमान ने अपने डेविल के किरदार को बेहतरीन बताया है और उनका मानना है कि उस किरदार को लेकर और फिल्में बनाई जा सकती हैं. इसके लिए सलमान ने किक के निर्माता निर्देशक साजिद नाडियाडवाला बात की है. ■

चौथी दुनिया
CHAUTHI DUNIYA
चौथी दुनिया की हर खबर अब आपके Android फोन पर भी उपलब्ध, Play Store से Download करें | CHAUTHI DUNIYA APP |

चौथी दुनिया

01 दिसंबर-07 दिसंबर 2014

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHI/2009/30467

बिहार-झारखंड

ख्वाब पीएम का

देश का अगला पीएम कौन होगा? इसे लेकर अभी चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है तो आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि जीतन राम मांझी ने पीएम बनने से संबंधित अपना बयान दिया. गौरतलब है कि सीएम के विवादस्पद बयानों ने इन दिनों सूबे की राजनीति को गरम करके रखा हुआ है. जदयू के सूत्र बताते हैं कि जीतन राम मांझी मानने वाले नहीं हैं. इस तरह की बयानवाजी जारी रहेगी. दरअसल वह अपने महादलित समाज की मजबूत गोलबंदी चाहते हैं. वे चाहते हैं कि महादलितों की भावनाओं पर अपने बयानों से मलहम लगाते रहें और उनका समर्थन मजबूत करते रहें.

सरोज सिंह

मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी अपने तरह-तरह के विवादस्पद बयानों को लेकर इन दिनों चर्चा में हैं. इन चर्चाओं के बीच उन्होंने एक बार फिर यह कह कर सनसनी फैला दी कि ठोकर खाते-खाते मैं मुख्यमंत्री बन गया और अगर इसी तरह ठोकर लगती रही तो मैं देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता हूं. यह पहली बार है जब नीतीश कुमार के अलावा और कोई नाम पीएम के लिए जदयू में आया है. सबसे दिलचस्प बात यह है कि अपने नाम को खुद जीतनराम मांझी ने ही आगे किया है. आप सभी को याद होगा कि कैसे लोकसभा चुनाव के पहले नीतीश कुमार के तथाकथित समर्थकों ने उन्हें पीएम मैटिरियल बताकर और देश का अगला नेता बताकर उनका सबसे ज्यादा नुकसान करा दिया. पीएम बनना तो दूर लोकसभा में संख्या दो ही रह गई. अब सवाल उठता है कि आखिर यह सब जानते समझते आखिर किस वजह से सीएम इस तरह की बातें कर रहे हैं.

देश का अगला पीएम कौन होगा, इसे लेकर अभी चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है तो आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि जीतन राम मांझी ने पीएम बनने से संबंधित अपना बयान दिया. गौरतलब है कि जीतन राम के विवादस्पद बयानों ने इन दिनों सूबे की राजनीति को गरम करके रखा हुआ है. जदयू के सूत्र बताते हैं कि जीतन राम मांझी मानने वाले नहीं है. इस तरह की बयानवाजी जारी रहेगी. दरअसल वह अपने महादलित समाज की मजबूत गोलबंदी चाहते हैं. वे चाहते हैं कि महादलितों की भावनाओं पर अपने बयानों से मलहम लगाते रहें और उनका समर्थन मजबूत करते रहे. उन्हें अब यह सपना दिखाया जाए कि जैसे उनके बीच का एक आदमी मुख्यमंत्री बन गया तो अब आगे प्रधानमंत्री भी बन सकता है. इसलिए किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है और पूरी तरह जीतन राम मांझी की बात सुननी है और पूरी ताकत के साथ इनका समर्थन करना है. जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव कहते हैं कि मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी तकलीफों से गुजरे हैं ऐसे में इनके बयानों का कोई मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए.

उनसे बात की जायेगी, उलूल -जुलूल बयान देने से बचने को कहा जायेगा. शरद यादव जब सीएमा के तकलीफों से गुजरने की बात कहते हैं तो उनका इशारा इस पूरे महादलित समाज की ओर होता है जो तकलीफों में अपना जीवन गुजारते हैं. दरअसल सीएम तकलीफों की अपनी इसी जीवन गाथा को अपना हथियार बना रहे हैं और अपने समाज में इसका पूरा असर भी हो रहा है. लेकिन दूसरी तरफ राजद के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह कहते हैं कि मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का बयान जदयू-राजद गठबंधन के लिए सही नहीं है, उन्होंने कहा कि जदयू को इस पर विचार करना चाहिए. सीएम के बयानों से गठबंधन को नुकसान पहुंच रहा है.

जदयू के एक बड़े नेता नाम न छापने की शर्त पर बतलाते हैं कि सीएम ऐसे खिलाड़ी हैं जो केवल अपने रिकार्ड के लिए खेल रहे हैं, टीम हारे या जीते इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है. यह बात कुछ हद तक सही है लेकिन जीतन राम मांझी जो भी कह रहे हैं उसका लाभ तो जदयू के वोट बैंक को ही मिलना है भले ही इसकी कमान किसी दूसरे के हाथ में क्यों न हो. अगर महादलित जीतन राम मांझी के कहने पर जदयू को वोट देते हैं तो फिर इससे पार्टी को कैसे नुकसान पहुंच सकता है? ■

feedback@chauthiduniya.com

मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम के विवादस्पद बयान

अगस्त - पटना
बिजली बिल सुधारने के लिए मुझे भी घूस देना पड़ा था.

अगस्त - दानापुर
चूहा खाने में बुरी बात नहीं है, मैंने भी चूहा खाया है, एससी-एसटी के लोग शराब कम पीएं, रात में सोते समय थोड़ी-थोड़ी शराब पीएं.

22 अगस्त -पटना सिटी
अनुसूचित जाति, अनुसूजित जनजाति के लोग अपनी जनसंख्या को बढ़ाएं इसके लिए अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा दें.

16 सितंबर - मोतिहारी
काम नहीं करने वाले डॉक्टरों के हाथ काट देंगे.

28 सितंबर - पटना
मधुबनी के अंधरठारी प्रखंड में परमेश्वरी देवी मंदिर में 18 अगस्त को पूजा की थी. मेरे पूजा करने के बाद मंदिर को धुलवाया गया.

अक्तूबर - पटना
कोई थोड़ी बहुत कालाबाजारी करता है, तो वह कर सकता है.

11 नवंबर - बगहा
अधिकारी रंगरेलियां मनाते पकड़े गये, तो होगी कार्रवाई, आदिवासी ही बिहार के मूलवासी हैं, बाकी सब विदेशी हैं.

11 नवंबर - गोपालगंज
जो युवक बाहर कमाने जाते हैं, साल में एक बार ही आ पते हैं, उनकी पत्नी यहां अकेली रहती हैं, वे क्या करती हैं, यह सोंचनेवाली बात है.

राजद और जदयू के विलय का मिथक

क्या नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए बिहार में राजद और जदयू का विलय हो सकता है. इस गंभीर सवाल पर इन दिनों दोनों ही खेमों में होमवर्क जारी है. भले ही नीतीश कुमार ने इस तरह की संभावनाओं को खारिज कर दिया पर अंदरखाने की खबर है कि जदयू के रणनीतिकार राजद के साथ सीटों के तालमेल से बेहतर दोनों दलों के विलय को ज्यादा हितकारी मान रहे हैं. जदयू की सोच बहुत ही सीधी है. दोनों दलों के विलय की स्थिति में पहले तो सीटों को लेकर कोई झगड़ा नहीं होगा और नेता के तौर पर नीतीश कुमार को स्थापित करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी. इसके अलावा दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के लिए भी यह जरूरी हो जाएगा. वह दल के प्रत्याशी के लिए अपना सौ फीसदी योगदान दें. जदयू इसका तीसरा फायदा यह देख रहा है कि विलय के हालात में यादव व मुस्लिम वोटरों का पूरी तरह ध्रूवीकरण नीतीश कुमार के पक्ष में हो सकता है. लेकिन अगर सीटों का तालमेल हुआ तो फिर समस्याओं का अंबार लग जाएगा. सबसे विकट काम तो टिकटों का बंटवारा ही है. अगर येन केन प्रकारेण यह निपट भी गया तो फिर विश्वासघात का सामना करना तय है. यादव वोटर पूरी तरह कुर्मी और कुशवाहा प्रत्याशी को और कुर्मी और कुशवाहा वोटर पूरी तरह यादव प्रत्याशी को वोट देंगे, इसमें शक है. बिहार का समाजिक ताना बाना इस तरह के वोटिंग के लिए इस समय उपयुक्त नहीं है या कहें तो इसके लिए अभी माहौल नहीं है. अगर यह समस्या बनी रही तो जदयू और राजद को भारी नुकसान हो सकता है. इसलिए जदयू की पूरी कोशिश है कि विलय हो जाए और पूरी मजबूती से चुनाव लड़ा जाए ताकि नरेंद्र मोदी के विजय रथ को बिहार में रोका जा सके.

एक नज़र

शैक्षणिक संस्थान ने चलाया स्वच्छता अभियान

'स्वच्छ शहर, स्वच्छ भारत' नीति के तहत शैक्षणिक संस्था शिशु भारती फॉरबिसगंज द्वारा शहर में स्वच्छता अभियान चलाया गया. इस अभियान की शुरुआत विद्यालय के सचिव हरिहर बांयवाला एवं संचालिका ललिता बांयवाला द्वारा स्वयं झाड़ू लगाकर की गई. इस अभियान में विद्यालय के शिक्षक, शिक्षिकाओं, छात्र-छात्राओं एवं अन्य कर्मचारियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई. यह अभियान विद्यालय प्रांगण से निकल कर एस. के. रोड, हनुमान मंदिर, राममनोहर लोहिया पथ, स्टेशन चौक, सदर रोड, आर. बी. लेन होते हुए पुन: विद्यालय प्रांगण में आकर समाप्त हुआ. कार्यक्रम के दौरान बच्चों एवं शिक्षक-शिक्षिकाओं ने स्वयं झाड़ू लगाकर, कूड़े-कचड़े उठाकर पूरे शहर को साफ-सुथरा किया एवं शहरवासियों को यह संदेश दिया यदि हमलोग अपने को एवं शहर को साफ-सुथरा रखेंगे तभी स्वच्छ भारत का सपना साकार होगा, क्योंकि स्वच्छ शरीर में ही स्वच्छ मन का वास होता है एवं सभी काम स्वच्छतापूर्वक सम्पन्न होते हैं. कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने अपने-अपने हाथों में विभिन्न नारों की तकथियां ली हुईं थीं एवं विभिन्न तरह के नारे लगा रहे थे. इस अभियान में नगरपालिका की तरफ से सफाई वाहन की व्यवस्था की गई थी. कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय के प्राचार्य मोहन साह वरीय शिक्षक श्यामानंद झा, दीनानाथ झा, रमण मिश्र कार्यालय प्रभारी दिलीप कुमार अग्रवाल, शिक्षिकाओं में प्रमिला ठाकुर, यासमीन शमीम, नीलम देवी, संगीता भारती, रत्ना डे, सविता चक्रवर्ती, पल्लवी अग्रवाल, एकता कुमारी, गुलनाज खान, अंजली कुमारी, गीता दास, गीता देवी, अनुप्रिया, राजू मालाकार छात्रों में जितेन्द्र कुमार, गौरवदास, वेनसगर्ग, यश अग्रवाल, रीतिक सेठिया, अग्रवाल छात्राओं में गरिमा जैन, तृप्ति गुप्ता, शिखा कुमारी, श्रेया, बियानी, श्रेया संजय, आरती एवं अन्य ने अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई. कार्यक्रम को शहरवासियों को काफी सहारा एवं अपनी तरफ से विभिन्न तरह की सामग्रियां देकर बच्चों को प्रोत्साहित किया.

– अमित ठाकुर

रालोसपा का सदस्यता कार्यक्रम

अररिया जिले में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने अपने संगठन की मजबूती की दिशा में एक कदम आगे बढ़ा दिया है. इसके तहत न सिर्फ पार्टी में नये चेहरों को शामिल किया जा रहा है वरन दूसरे दलों के लोगों को भी प्राथमिकता दी जाने लगी है. इसके तहत पिछले दिनों पार्टी के जिला उपाध्यक्ष अधिवक्ता देवेन्द्र मिश्र की अध्यक्षता में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष मो. सरवर आलम के निवास पर एक बैठक आयोजित की गयी. इस बैठक में भाजपा-लोजपा, राजद व कांग्रेस छोड़कर रालोसपा की सदस्यता ग्रहण करने वालों में मो. सरवर आलम, नौशाद आलम, प्रभुनाथ पासवान, दयानंद रजक फौजी, रंजीत पासवान, श्यामलाल विश्वास, मुमताज अहमद, मो. जाहिद, आजम अली, राजकुमार सिंह, मौलाना मंजूर, संतोष श्रीवास्तव एवं मो. रज्जाक शामिल हैं. भाजपा-लोजपा, राजद व कांग्रेस छोड़ रालोसपा में शामिल हुये इन नेताओं को पार्टी के जिलाध्यक्ष रमेश मेहता एवं जिला उपाध्यक्ष देवेन्द्र मिश्र के द्वारा माला पहना कर स्वागत किया गया. इस अवसर पर महासचिव चंदन यादव, बबन यादव, युवा जिलाध्यक्ष रंजीत कुमार सिंह, रणविजय कुमार विश्वास सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे.

– कुमार विशाल

गया

तस्करों की सक्रियता ने किया जंगल को बेहाल

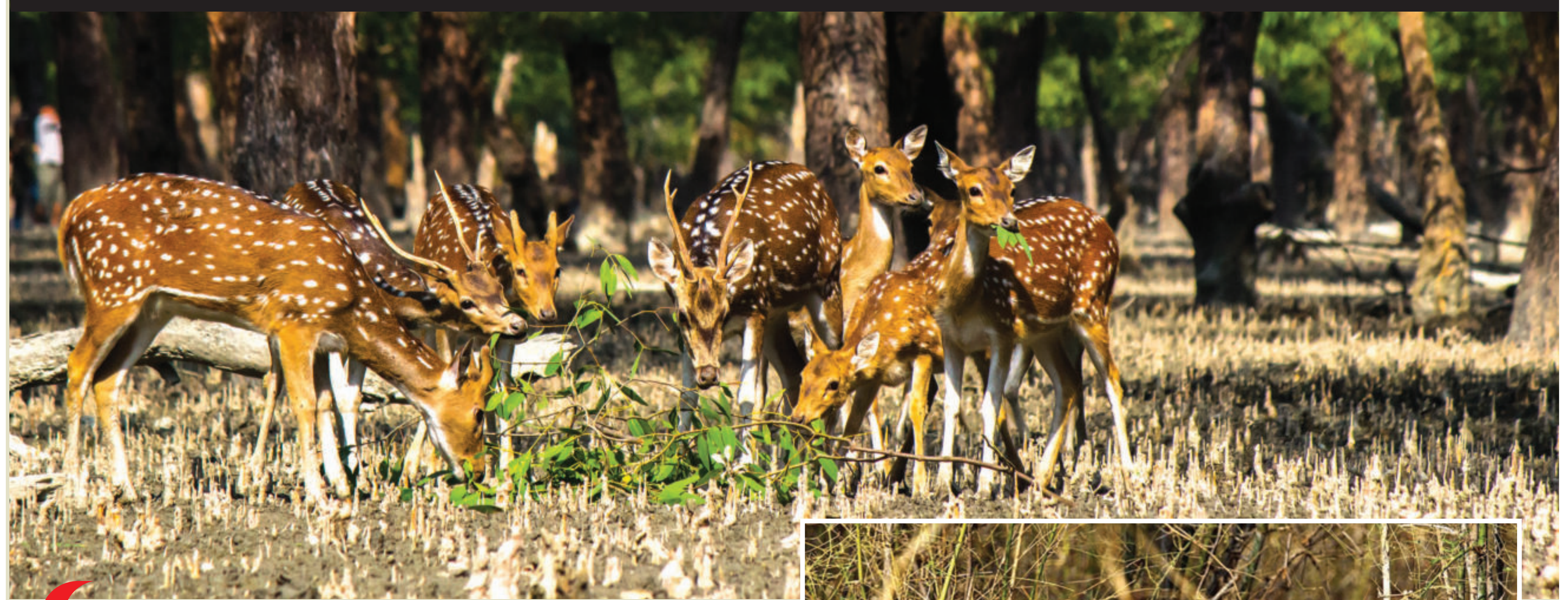

भारत में बाघों की घटती संख्या को देखते हुए भारत सरकार की ओर से 1994 में वाल्मीकि बाघ परियोजना का स्वरूप करीब 899 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के जंगल को दिया गया था. इसमे 335 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान तथा 545 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र बाघों के रहने के लिए सुरक्षित क्षेत्र निर्धारित किया गया. बताया जाता है कि तब यहां के जंगल में बाघों की संख्या 80 थी. दो दशक में बाघों की संख्या बढ़ने की बजाय घटकर एक दहाई के नीचे आ गया. इसी से आप अदाजा लगा सकते हैं कि टाइगर रिजर्व होने के बाद बाघों को कितना संरक्षण मिला. हालांकि वन विभाग का दावा बाघों की संख्या के मामले में कुछ और है.

सुनील सौरभ

पूरी दुनिया में बाघों को बचाने की मुहिम चल रही है. अपने देश में भी बाघों को बचाने के गंभीर प्रयास किये जा रहे हैं. लेकिन बिहार के एकमात्र वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की हालत को देखने से ही पता चल जाता है कि वन विभाग के पदाधिकारी या सरकार बाघों को बचाने के लिए कितनी गंभीरता से काम कर रही है. बाघों को बचाने, संरक्षण देने के लिए प्रतिवर्ष इस टाइगर रिजर्व पर करोड़ों रुपये खर्च किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर प्रतिवर्ष बाघों की संख्या कम होती जा रही है. सच कहा जाये तो बिहार के इस एकमात्र वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में कुछ भी रिजर्व नहीं है. इस जंगल में आप जो चाहें वो कर सकते हैं. कहने को तो बहुत सारी बंदिशें लिखी मिलेंगी इस टाइगर रिजर्व के जंगल में लेकिन व्यवहारिक रूप में कहीं कोई रोक-टोक नहीं है. नेपाल तथा उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे पश्चिम चंपारण के बगहा पुलिस जिले के अन्तर्गत 899.38 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पर भारत तथा बिहार सरकार का प्रतिवर्ष वन्य जीव, जन्तुओं को बचाने के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च आता है. लेकिन इस खर्च को पानी में बह जाना कहा जाये तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी . तमाम प्रयास के बाद भी बाघ, हिरन समेत अन्य वन्य जीव -जन्तुओं का शिकार यहां के जंगल में जारी है. यहां के जंगल से प्रतिबंधित बेंत की भी तस्करी की जाती है .

भारत में बाधों की घटती संख्या को देखते हुए भारत सरकार की ओर से 1994 में वाल्मीकि बाघ परियोजना का स्वरूप करीब 899 वर्ग किलोमिटर क्षेत्र के जंगल को दिया गया था. इसमे 335 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान तथा 545 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र बाघों के रहने के लिए सुरक्षित क्षेत्र निर्धारित किया गया. बताया जाता है कि तब यहां के जंगल में बाघों की संख्या 80 थी. दो दशक में बाघों की संख्या बढ़ने की वजाय घटकर एक दहाई के नीचे आ गया. इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टाइगर रिजर्व होने के बाद बाघों को कितना संरक्षण मिला. हालांकि वन विभाग का दावा बाघों की संख्या के मामले में कुछ और है. यहां बाघों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होने का एक बड़ा कारण गर्मी के दिनों में यहां के घने बेंत के जंगल में आग लग जाना है. बताया जाता है कि बेंत के तस्करों के द्वारा जंगल के क्षेत्र के गांवों के ग्रामीण को लालच देकर बेंत के जंगल में आग लगा दिया जाता है, जिससे बेंत के पत्ते जल जाते है और बेंत तस्करों के गुर्गे वनकर्मियों की मिलीभगत से बेंत को काटकर नेपाल तथा उत्तर प्रदेश की सीमा पहुंचा देते हैं. जिससे जंगल घना नहीं हो पाता है. जबकि बाघों के प्रजनन के लिए बेंत का जंगल अच्छा माना जाता है, जानकारों का कहना है कि यदि वन विभाग द्वारा प्रयास कर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व क्षेत्र के जंगल में सिर्फ एक वर्ष बेंत के जंगल को आग लगाने से बचा लिया जाये तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या में बढ़ोतरी नजर आयेगी. बेंत के तस्करों के साथ बाघों को मारकर इसके अंगो की तस्करी करने वाले भी यहां के जंगल में सक्रिय देखे जाते हैं.

दो दशक में करीब एक दर्जन बाघों की मौत विभिन्न कारणों से हो चुकी है. अवैध रूप से बाघों का शिकार करने का आंकड़ा इसमे शामिल नहीं है. वाल्मीकि टाइगर रिजर्व व वन विभाग के लोग यहां के जंगल में बाघ के अलावा गेंडा, काला भालू, जंगली भैंसा, जंगली सुअर, लिपोयार्ड हिरणों की कई प्रजाति, लंगूर, बंदर , जलीय जीव मे राइनों, घड़ियाल, उदबिलाव, कोबरा तथा सांपों की दर्जनों प्रजाति देखने को मिलते हैं. कुछ वर्ष पूर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में शॉर्ट ट्रैक की व्यवस्था की गई थी. साथ ही पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सफारी पैकेज तैयार किया गया था. बिहार के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने इसका उद्घाटन किया था. लेकिन प्रचार-प्रसार का अभाव तथा समुचित व्यवस्था नहीं देखकर पर्यटक नहीं आकर्षित हो सके. ऐसे जीप सफारी चार पर्यटक (ढाई घंटे) का छह सौ रुपये, हाथी सफारी तीन पर्यटक (ढाई घंटे) तीन सौ रुपये, बैलगाड़ी सफारी चार पर्यटक (तीन घंटे) चार सौ रुपये का पैकेज तैयार किया गया था. बताया जाता है कि एक निजी व्यक्ति को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गयी थी. लेकिन सफारी योजना सफल नहीं हो सकी. इसी प्रकार वाल्मीकि नगर स्थित वाल्मीकि विहार होटल का जीर्णोद्धार कर इस होटल के संचालन के लिए निजी व्यक्ति को दिया गया है. इस होटल का किराया भी प्रतिदिन एक हजार रुपया है. जबकि सुविधाएं नगण्य है. इसलिए कोई व्यक्ति दिनभर घूमकर वापस बगहा, बेतिया लौट जाना चाहता है. करोड़ों रुपये खर्च कर इस होटल का जीणाद्धार तो किया गया है लेकिन रख-रखाव में बेहद कमी है. वाल्मीकि विहार होटल जहां है, वहां से प्रकृति की अनुपम छटा देखने को मिलती हैं, किन्तु होटल के सामने के पार्क की दयनीय स्थिति तथा वहां फैले गंदगी को देखकर हर पर्यटक का मन दुखी हो जाता है. ऐसे इस टाइगर रिजर्व में बाघों या अन्य वन्य जीव जन्तुओं की संख्या में वृद्धि नहीं होने के कारण जंगल के बीच दर्जनों गांव का होना भी बताया जाता है. वन पदार्थो तथा वन्य जीवो के तस्कर गांवो के भोले-भाले ग्रामीणों को लालच देकर अपना काम कराने मे सफल हो जाते हैं. हालांकि इसमे ग्रामीणों को जान पर खेलना भी पड़ता है. कई बार तो वन विभाग तथा सुरक्षा कर्मियों के हाथों पकड़े जाने पर ग्रामीणों को जेल जानी पड़ती है. लेकिन तस्कर नही पकड़े जाते हैं. क्योंकि प्रत्यक्ष रुप से जंगल में ग्रामीण वन पदार्थो या वन्य जीव-जन्तुओं की तस्करी में पकड़े जाते हैं. बिहार सरकार, वन विभाग तथा अन्य संबंधित विभाग यदि दृढ़ संकल्प कर ले तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को भी इड़ीसा के नंदन कानन वन तथा सुन्दर वन की तरह विकसित कर बिहार का सर्वक्षेष्ठ पर्यटन स्थल बना सकता है. फिलहाल वाल्मीकि नगर तथा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को अपने उद्धार के लिए तलाश है किसी उद्धारक की.■

feedback@chauthiduniya.com

मगध मे रालोसपा की होगी मजबूत दावेदारी

सुनील सौरभ

अगले साल होने वाले बिहार विधान सभा चुनाव की तैयारी में सभी राजनीतिक दल लग गये हैं. दक्षिण बिहार या मगध क्षेत्र बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है. जिस किसी की भी बिहार में सरकार बनी इस दल की पकड़ मगध में मजबूत रही तभी सत्ता मिली. इसीलिए हर दल का किसी भी चुनाव मे यह प्रयास रहता है कि मगध क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्रों मे इसकी पकड़ मजबूत रहें.

इसीलिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के दलों तथा दूसरी ओर महागठबंधन वाले राजद, कांग्रेस, जदयू का प्रयास है कि आने वाले विधान सभा चुनाव में मगध मे उसकी अच्छी स्थिति रहे. इसी प्रयास मे एनडीए में शामिल राष्ट्रीय लोक समता पार्टी भी है. इसका कारण भी वाजिब है. राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केन्द्रीय मंत्री उपेन्द्र कुशवाहा मगध के काराकट से सांसद है तो प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अरुण कुमार जहानाबाद से सांसद है. राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अन्य बड़े नेता विधान पर्षद संजीव श्याम सिंह गया शिक्षक निर्वाचक क्षेत्र से हैं. इसीलिए राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की मगध क्षेत्र मे विधान सभा चुनाव मे मजबूत दावेदारी बनती है. ऐसे मगध क्षेत्र के राजनीतिक जानकारों का मानना है कि विधान सभा चुनाव मे रालोसपा को भाजपा गठबंधन में अधिक से अधिक 15 से 18 सीटें मिल सकती है. इसमे कम से कम आधी सीटें की दावेदारी मगध की जरूर बनती है. ऐसे शाहाबाद और मगध क्षेत्र के रालोसपा नेताओं की मांग करीब दर्जन भर सीटों पर की जा रही है.

जिनमें शाहाबाद के जगदीशपुर, डुमरांव, राजपुर, कारगहर, चेनारी मगध के ओबरा, रफीगंज, षेरघाटी, बेलागंज, कुर्था, जहानाबाद, अतरी और गाविन्दपुर विघान सभा क्षेत्र षामिल है. ऐसे राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के कोई भी नेता सीटें मिलने तथा चुनावी समीकरण पर अभी से कुछ भी नही कहना चाह रहें है. सभी नेता यह कहते मिले कि गठबंधन के दलों के नेताओं का जो संयुक्त निर्णय होगा, हम सभी इसी के तहत कार्य करेगें. विधान पार्षद संजीव श्याम सिंह ने कहा कि चुनाव में अभी एक वर्ष देर हैं. लेकिन हम सभी चुनावी तैयारी में लग गये हैं. हम सभी गठबंधन के सभी दलों के सभी प्रत्याशियों के लिए कार्य करेंगे, जिससे कि बिहार मे एनडीए की सरकार बन सके. एनडीए मे शामिल दलों लोजपा या रालोसपा की दावेदारी भी इसी सीट पर है जहां से जदयू, कांग्रेस या राजद के विधायक हैं. हां किसी विशेष परिस्थिति में किसी सीट के लिए भाजपा से अदला-बदली हो सकती है. मगध के रालोसपा नेताओं को उम्मीद है कि इनके बड़े नेताओं मगध से निर्वाचित होने के कारण यहां की दावेदारी मजबूत होगी. देखें विधान सभा चुनाव आते आते दोनो गंठबंधन के दलों के किस प्रत्याशी की किस्मत खुलती है या बंद होती है.■

feedback@chauthiduniya.com

पूर्णिया

गुलाबबाग बना पीडीएस अनाजों के अवैध कारोबार का केन्द्र

कुछ लोगों का मानना है कि पहले एक ही स्थान से सरकारी अनाज के डीलर उठाव करते थे जिससे कालाबाजारी की कम आशंका रहती थी लेकिन अब प्रखंड स्तर के गोदामों से डीलर अनाज का उठाव करते हैं जिससे सरकारी अनाज की कालाबजारी का दायरा बढ़ गया है. बंगाल के नजदीकी बिहार के प्रखंड सरकारी अनाज के कालाबजारी मामले में अव्वल है. सम्पूर्ण किशनगंज जिला, पूर्णिया का बायसी अनुमंडल, कटिहार का बारसोई अनुमंडल के गोदामों से अनाज उठाव के साथ ही बंगाल में प्रवेश कर जाते हैं.

नीरज कुमार

सरकार समय-समय पर समाज के सबसे नीचले तबके के गरीब लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाती रहती है लेकिन बड़े पैमाने पर व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण इसका कम ही लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुंच पाती है. योजना का अधिकांश हिस्सा प्रशासनिक महकमे से लेकर बिचौलियों की भेट चढ़ रहा है.सरकार ने गरीब जरूरतमंद भूखे लोगों को भोजन उपलब्ध कराने एवं खाद्य गारंटी स्कीम के तहत सभी लोगों को जोड़ने के उद्देश्य से जनवितरण प्रणाली के माध्यम से 2 रुपये प्रति किलो के भाव से गेहूं एवं 3 रुपये प्रति किलो के भाव से चावल देने की योजना को चालू किया है जिसके तहत प्रति व्यक्ति प्रति यूनिट महीने में 2 किलो गेहूं एवं 3 किलो चावल मिलता है. लेकिन वर्तमान में इस योजना का लाभ गरीब जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है और योजना का अधिकांश अनाज बिचौलिये के माध्यम से खुले बाजारों में बिक रहा है. मिली जानकारी के अनुसार पूर्णिया जंक्शन में सरकारी अनाज का रेक लगने के साथ ही घालमेल का खेल शुरू हो जाता है रेक से अनाज बेलौरी स्थित एफसीआई गोदाम में जाता है. कुछ अनाज रेक प्वांइट से सीधे स्टेट फूड कॉरपोरेशन के गोदामों एंव गुलाबबाग स्थित बीवरेज के गोदामों में एफसीआई द्वारा सीधे भेज दिया जाता है. रेक प्वांइट से एफसीआई, बीवरेज एंव स्टेट फूड कारर्पोरेशन के गोदामों में पहुंचने के दौरान भी बिचौलिये ट्रांसपोर्टर एवं प्रशासनिक मिलीभगत से कभी-कभी गेहूं एवं चावल रास्ते से ही गायब हो जाता है. ऐसा ही एक मामला विगत जुलाई 2014 में प्रकाश में आया जब बेलौरी उच्च विद्यालय के निकट स्थित एक मोहल्ले में दो ट्रकों से लगभग दो सौ बोरा गेहूं इतारते स्थानीय पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा वही सितंबर माह में मुस्सफिल थाना रानीपतरा अन्तर्गत पूर्णिया-कटीहार रोड पर बेलौरी से कटिहार की और जाने वाली सड़क पर सरकारी गेहूं से लदे ट्रक को पकड़ा था. इस संबंध में स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह के मामले समय बीतने के साथ धीरे-धीरे थाने की फाइलों में ही दबकर ही रह जाते हैं. फरवरी 2014 में ही गुलाबबाग मंडी के अंदर अनाज पट्टी में लगभग 500 बोरा सरकारी अनाज को प्रशासन ने पकड़ा था जबकि नवंबर 2013 में ही मार्केटिंग यार्ड के अंदर दो ट्रैक्टर पर लदे अनाज को प्रशासन ने पकड़ा था. मिली जानकारी के अनुसार इस धंधे मे एक अनाज सिंडीकेट कार्य कर रहा है जो गुलाबबाग मंडी के अंदर चौतालों, यहां स्थित गोपनीय गोदामों, पूर्णियां स्थित चावल मिलों के माध्यम से कागजात तैयार करके सरकारी अनाजों को पड़ोसी बंगाल समेत पूर्वोत्तर एवं अन्य राज्यों को भेजते है दूसरी तरफ सरकारी गेहूं का एक अहम हिस्सा पूर्णिया एंव गुलाबबाग स्थित आटा मिलों में सहज ही खपत हो जा रही है. मालूम हो कि हाल के वर्षो में पूर्णिया समेत कोशी प्रमंडल में मकई की खेती ने जोर पकड़ा है और मकई का बंपर उत्पादन हो रहा है वहीं यहां के किसान गेहूं की खेती से विमुख होकर मकई की खेती में अधिक आकर्षित हुए है जिससे गेहूं की खेती सिमटते जा रही है. हाल के दिनों में सीमांचल समेत निकटवर्ती बंगाल में आटा मिलों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है.

अपना नाम नहीं छापने के शर्त पर कुछ व्यवसायियों एवं मजदूरों ने जानकारी दी की पी डीएस के अनाज को निजी एंव किसानों का अनाज बनाने के लिए स्थानीय गोपनीय गोदामों, डीलर के घर पर राइस मिलों में छिपे रूप से सरकारी पैकिंग सील को तोड़कर बोरा पलटी धड़ल्ले से किया जा रहा है. कभी-कभी डीलर, एसएफसी के कर्मचारियों के मिलीभगत से चावल, गेहूँ एसएफसी गोदाम पर ही बिचौलिये के हाथो में बेच लेते हैं, जहां से इसे गोपनीय स्थान पर भेज दिया जाता है. कुछ लोगों का मानना है की पहले एक ही स्थान से सरकारी अनाज का डीलर उठाव करते थे जिससे कालाबजारी की कम आशंका थी लेकिन अब प्रखंड स्तर के गोदामों से डीलर अनाज का उठाव करते है जिससे सरकारी अनाज का कालाबजारी का दायरा बढ़ गया है. बंगाल से सटे बिहार के प्रखंड सरकारी अनाज के कालाबजारी मामले में अव्वल है. संपूर्ण किशनगंज जिला, पूर्णिया का बायसी अनुमंडल, कटिहार का बारसोई अनुमंडल के गोदामों से अनाज उठाव के साथ ही बंगाल में प्रवेश कर जाते है. मालूम हो की इन इलाकों में गेहू की कम खपत है और उत्पादन भी कम होता है. यहां का गेहूं दार्जिलिंग एवं उत्तर दिनाजपुर में पहुंच जाते हैं. कभी-कभी स्थानीय पुलिस इस तरह के मामले पकड़ में आने पर मामला रफा-दफा भी हो जाता है. चौथी दुनिया ने भी एक आटा मिल में सरकारी गेहूं ले जाते एक टेम्पू की तस्वीर को कैद किया. कैमरा देखते ही मिल मालिक ने गेहूं समेत टेम्पू को भगा दिया.

पीडीएस अनाज की कालाबजारी को लेकर जब पूर्णिया सदर के अनुमंडल पदाधिकारी कुंदन कुमार से जब चौथी दुनिया ने संर्पक किया तो उनका कहना था कि पूर्णिया सदर में अनुमंडल प्रशासन अनाज की कालाबजारी रोकने के लिए सतर्क है. मेरे कार्यकाल में अनुमंडल प्रशासन द्वारा 6 मामलें कालाबजारीयों के खिलाफ में दर्ज किये गये है. हाल का मामला श्रीनगर प्रखंड का है. इस तरह की अगर कोई गोपनीय सूचना हमें मिलती है तो हम तुरंत कार्रवाई करते है.■

feedback@chauthiduniya.com

समस्तीपुर : समिति परिसर में व्यवसाय बना मुश्किल

समस्तीपुर बाजार समिति कभी आस-पास के गांव के लोगों के लिए प्रमुख व्यवसाय का केंद्र हुआ करता था. परंतु जब से बाजार समिति का अस्तित्व समाप्त हुआ है, तब से यह परिसर स्थानीय व्यवसायियों के लिए सिरदर्द साबित होकर रह गया है. राज्य खद्य निगम का गोदाम समिति परिसर में बनाये जाने के बाद इसकी दशा और भी दयनीय होकर रह गयी है...

अमृता कुमारी

समस्तीपुर-दरभंगा मुख्य पथ के किनारे स्थित समस्तीपुर बाजार समिति की स्थापना वर्ष 1988 में की गयी थी. तब इस परिसर में प्रतिदिन अहले सुबह से ही आस-पास के ग्रामीण व व्यवसायी अपने सामानों की खरीद बिक्री के लिए आया करते थे. करीब 56 एकड़ जमीन पर स्थित परिसर में हजारों को दैनिक रोजगार का अवसर भी मिलता था. परंतु सरकारी स्तर पर जैसे ही बाजार समिति के अस्तित्व को समाप्त किया गया, वैसे ही बाजार समिति परिसर में वीरानगी छाने लगी. बाद में जिला कृषि कार्यालय व ओपी भी इस परिसर में खोल दिया गया. अब हालात ऐसा हो गएं हैं कि बचे खुचे स्थानीय व्यवसायियों के लिए व्यवसाय भी एक चुनौती बन कर रह गयी है. पिछले साल बाजार समिति प्रांगण के दक्षिण-पूर्व कोना पर एफसीआई के गोदाम का निर्माण करा दिया गया. इसके कारण दिन भर बाजार समिति परिसर ट्रक के धूल से सराबोर रहा करता है. सड़क की स्थिति बदतर रहने के कारण व्यवसायियों को जहां दिन भर अपने प्रतिशठान पर बैठना मुश्किल बना रहता है, वहीं अन्य आवश्यक सुविधा नहीं रहने के कारण भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है. हाल है कि करीब दो सौ छोटे-बड़े व्यवसायियों को पेयजल व शौचालय जैसी समस्याओं का दैनिक सामना करना पड़ता है. जबकि बाजार समिति परिसर में दुकान करने वाले व्यवसायी प्रति माह 25 सौ रुपये से लेकर 10 हजार रूपये तक मासिक किराया देते है. स्थानीय व्यवसायी इंद्रदेव व सचिन की माने तो जब से एफसीआई का गोदाम बना है, तब से समिति परिसर के सडकों का हाल बदतर होकर रह गया है. बरसात में पानी के जमा होने पर परेषानी का सामना करना पडता है तो अन्य दिनों में धूल मुसीबत बनी रहती है. अत्यधिक धूल का नतीजा है कि परिसर में काम करने वाले अधिकांश दैनिक मजदूर सांस के बीमारी से ग्रस्त होकर रह गये हैं. लेकिन जीवन यापन की जरीया होने की बजह से कार्य करने की विवशता उन्हें आने को मजबूर कर रहा है.

ऐसा भी नहीं है कि इस समस्या को लेकर व्यवसायियों ने जिला प्रशासन तक फरियाद नहीं पहुंचाया है. लेकिन प्रशशसनिक स्तर पर इस दिशा में अब तक किसी भी प्रकार की पहल नहीं की जा सकी है. समस्तीपुर बाजार समिति के व्यवसायियों का कहना है कि अगर अविलंब समस्या निदान की दिशा में पहल नहीं की गयी तो जिला प्रशासन व जनप्रतिनिधियों के खिलाफ शीघ्र आंदोलन किया जायेगा.■

feedback@chauthiduniya.com

एक नज़र

प्रेस दिवस पर कार्यक्रम आयोजित

जनता की चेतना को जगाने में मीडिया की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है. इसलिए खबरों में पारदर्शिता एवं निष्पक्षता बेहद आवश्यक है. उपरोक्त उद्गार जिला मुख्यालय अररिया में राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में जिला एवं सत्र न्यायधीश रमेश तिवारी ने व्यक्त किये हैं. उन्होंने कहा कि समाचारों को राजनीति एवं दूसरी बातों से अलग रखना चाहिए ताकि संविधान की भावना के अनुरूप सकारात्मक कार्य हो सकें. इस अवसर पर जिलाधिकारी नरेन्द्र कुमार सिंह ने भी पत्रकारों के निष्पक्षता एवं स्वतंत्रता की जरूरत पर बल दिया. उन्होंने कहा कि प्रेस का समाज पर काफी प्रभाव होता है इसलिए मीडिया को हमेशा अपने आप को भी सावधान रखना चाहिए. एडीजे मनोज कुमार सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रेस जैसी प्रभावी संस्थाओं से पारदर्शिता की उम्मीद रहती है इसलिए इस दिशा में हमेशा सजग रहना आवश्यक है. कार्यक्रम में जिला पत्रकार संघ के संरक्षक डॉ. नवल किशोर दास ने पत्रकारों की भूमिका को रेखांकित करते हुए विस्तृत रूप से अपनी बात रखी. इस अवसर पर अपर आरक्षी अधीक्षक राजीव रंजन, अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार, एडीजे पी.एन. सिंह, रामाकांत यादव, संजय कुमार सिन्हा, डीएन यादव, सीजेएम राकेश कुमार मिश्र, सब जज सुनील कुमार, जेएम संजय सिंह, फैमिली कोर्ट के न्यायधीश विजय कुमार सिन्हा सहित कई मीडियाकर्मी एवं अधिकारी उपस्थित थे.

– सुमित प्रियदर्शी

बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन

सीतामढ़ी शहर स्थित लक्ष्मी किशोरी उच्च विद्यालय के सभागार में साइंस फॉर ऑल एवं सायंस फॉर सोसायटी बिहार के तत्वावधान में 22 वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कार्यक्रम का आयोजन किया गया. समिति के अध्यक्ष मो. जियाउल्लाह की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन एसपी नवल किशोर सिंह ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया. कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मौसम व जलवायु को समझाना था. मौके पर डीइओ प्रेमचंद्र, डीपीओ शैलेंद्र कुमार, रमेशचंद्रा, जय शंकर ठाकुर, अध्यक्ष बीके मिश्रा, अराजपत्रित प्रारंभिक शिक्षक संघ के सचिव दिलीप कुमार शाही, आयोजन समिति के सदस्य ई. राज किशोर नारायण यादव, मो. शफीक खां, जय प्रकाश राय, वैद्यनाथ रमण व रंधीर कुमार मिश्रा ने अपना विचार व्यक्त किया. कार्यक्रम में विषय प्रवेश अभय कुमार झा एवं संचालन शिशिर कुमार व अवनींद्र भूषण ने संयुक्त रूप से किया. वहीं शिवहर जिले के कुशहर उच्च विद्यालय में साइंस फॉर सोसायटी के अंतर्गत आयोजित 22 वीं बाल विज्ञान कांग्रेस कार्यक्रम का उद्घाटन डीएम कुमार विनोद नारायण सिंह ने किया. मौके पर डीडीसी अशोक कुमार सिंह, एसडीओ लालबाबू सिंह, डीपीओ विनोद कुमार शर्मा, जिला परिषद सदस्य सुनील कुमार सिंह व समन्वयक अनिल कुमार सिंह समेत अन्य थे. अध्यक्षता अजबलाल चौधरी ने की.

– ब्रजेश

बैंको में रही हड़ताल

पिछले 12 नवंबर को यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल कार्यक्रम के तहत सीतामढ़ी व शिवहर जिले के वाणिज्यिक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की शाखाओं में हडताल रही. हड़ताली बैंक कर्मियों ने सिंडिकेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा के समक्ष धरना देकर आइबीए एवं वित्त मंत्रालय के रवैये पर रोष जताया. हड़ताल के कारण सीतामढ़ी जिले में करीब 150 करोड़ का लेन-देन प्रभावित हुआ. धरना-प्रदर्शन में दिनेशचंद्र द्विवेदी, अमरेंद्र कुमार चौधरी, कृष्ण कुमार ठाकुर, आदित्य कुमार, विजय कुमार मिश्र, सरोज कुमार सिंह, संजीव कुमार, आरके दास, राकेश कुमार रंजन, राघवेंद्र कुमार सिंह, नागेंद्र पूर्वे, संतोष कुमार झा, चंदन प्रभाकर, भूप नारायण सिंह, इंदू षेखर सिंन्हा, कृशण कुमार झा, अनवर अली, धनंजय कुमार, ष्यामबाबू कुमार, कामेश्वर प्रसाद सिंह, अजीत कुमार तिवारी, श्याम किशोर, लक्ष्मी राय, अजीत सिंह, गुंजेश सिंह, दीपक कुमार, प्रमोद कुमार व यशवंत राय समेत दर्जनों कर्मी शामिल थे.

– बाल्मीकि कुमार

मांगों के समर्थन में धरना

सीतामढ़ी जिले के रुन्नीसैदपुर प्रखंड सह अंचल कार्यालय में भाकपा मार्क्सवादी कार्यकर्ताओं ने नौ सूत्री मांगों के समर्थन में धरना दिया. अंचल सचिव देवेंद्र यादव की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में सैदपुर घाट पर बसे गरीब परिवारों को वासगीत परचा देने, खाद्य सुरक्षा के तहत सभी को 2 रूप्ये प्रति किलों की दर से 35 किलों अनाज की गारंटी देने, वृद्धा पेंशन का वितरण शीघ्र कराने समेत अन्य मांगों पर कार्यकर्ताओं ने चर्चा की. धरने में माकपा नेता लक्ष्मण पासवान, हरि मंडल, शुभ नारायण साह, रेणु देवी, शंकर पासवान, विनय महतो, विंदेश्वर महतो व महेंद्र पासवान समेत अन्य थे.

– विभा

केन्द्रीकृत प्रणाली का उद्घाटन

सीतामढ़ी जिला मुख्यालय डुमरा स्थित व्यवहार न्यायालय में जिला जज संजय प्रिय ने केन्द्रीय प्रणाली का फीता काट कर उद्घाटन किया. मौके पर प्रधान न्यायाधीश अजय कुमार शुक्ला, एडीजे प्रथम प्रभुनाथ सिंह, एडीजे तृतीय किशोर कुमार सिन्हा, एएडीजे मो इरशाद अली, सीजेएम अशोक कुमार गुप्ता, एसडीजेएम सदर आलोक कुमार पांडेय, एसडीजेएम पुपरी राज कुमार रविदास, प्रभारी न्यायाधीश सुधीर कुमार सिन्हा, न्यायिक अधिकारी मनीष द्विवेदी, मो. रुस्तम, लोक अभियोजक अरुण कुमार सिंह, जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद कुमार ठाकुर समेत अन्य थे.

– वाल्मीकि

बाल दिवस पर कार्यक्रमों की धूम

सीतामढ़ी जिले के बैरगनिया प्रखंड में पूर्व प्रधानमंत्री स्व.पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती अलग-अलग स्थानों पर बाल दिवस के रूप में मनायी गयी.प्रखंड के भटौलिया पीएस निकेतन में निदेशक अरविंद सिंह, इम्पेरियर एकेडमी बैरगनिया में निदेशक सोहन सर्राफ, विवेकानंद पब्लिक स्कूल अशोगी में निदेशक एमएल गुप्ता, न्यू सरस्वती शिशु निकेतन बेगाही बैरगनिया परिसर में निदेशक शशि कुमार चौधरी एवं मिषन बोडिंग स्कूल परिसर में निदेषक संजीव कुमार वर्मा, षिक्षक लक्ष्मी कुमारी, एसके झा, नवल किषोर झा, राज नारायण साह, चंदेष्वर राम व इंदू कुमारी के नेतृत्व में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया.■

– अरुण कोचर

बगहा के कैलाशनगर, शास्त्रीनगर, दीनदयालनगर, लौकरिया, पूजहा, घोड़हिया, मरचहिया, आदि जगहों के घाटों पर एक बार नहीं कई बार हादसें हो चुके हैं. कई लोगों की जानें जा चुकी है. उदाहरण तौर पर बगहा शहर के नजदीक कैलाशनगर घाट पर बारह जून 2012 में ज्योति कुमारी और छोटी कुमारी की जान नाव डूबने से गयी थी. वर्ष 2007 में शास्त्रीनगर घाट पर नाव डूबने से पांच महिलाओं और एक पुरुष का जान गई.

सीतामढ़ी

एमपी साहब, बरियारपुर गांव ही क्यों ?

ऐसी स्थिति में अब सवाल यह उठता है कि सांसद महज एक साल में योजना के तहत इतनी बड़ी आबादी वाले गांव में अलादीन का कौन सा चिराग जला सकेंगे? अगर समय सीमा के अंदर गांव में विकास का सितारा नहीं चमका तो पीएम की योजना माखौल बन कर रह जाएगी, जिसे लेकर आगामी विधानसभा चुनाव के मौके पर विरोधी दल जनता के बीच जाने में कोई कसर नही छोड़ेंगे. दूसरा यह कि संपन्न लोकसभा चुनाव में रालोसपा प्रत्याशी को भाजपा गठबंधन के तहत अन्य का भी पुरजोर समर्थन मिला है. तब सांसद का स्वजातीय प्रेम पाश में फंसना कहीं से भी उचित नहीं है.

वाल्मीकि कुमार

संपन्न लोकसभा चुनाव में 'मोदी मिशन 2014' की सफलता का आलम रहा कि भाजपा गठबंधन को भारी बहुमत मिला. भाजपा के घोषित प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद केंद्र की सत्ता संभालने का अवसर प्राप्त हुआ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घिसी-पीटी परिपाटी को ठेंगा दिखाते हुए अपने अंदाज में शासन की कमान थामी. मोदी मंत्रीमंडल में शामिल मंत्रियों को सख्त हिदायत दी गयी कि कोई भी मंत्री अपने विभाग में परिवार के लोगों को स्थान नही देंगे. जिस किसी ने भी पीएम के फरमान को नजरअंदाज करने की हिमाकत की उसे फौरन संभल जाने का हुक्म भी दिया गया. इन दिनों यह बात सीतामढ़ी जिले में जोर-शोर से चर्चा का केंद्र बनी है. कारण कि भाजपा गठबंधन से ही रालोसपा के राम कुमार शर्मा बतौर सांसद तकरीबन डेढ़ लाख मतों से निर्वाचित हुए हैं. केंद्र में भाजपा की सरकार गठन के करीब चार माह बाद सांसद की पहली प्रेस वार्ता हाल ही में स्थानीय परिसदन में हुई. तब सांसद ने बड़े ही उत्साह के साथ कहा कि प्रधानमंत्री ने सांसदों को अपने क्षेत्र से एक आदर्श गांव का चयन करने का अधिकार दिया है. इसके तहत डुमरा प्रखंड के बरियारपुर गांव का चयन किया गया है. योजना के तहत गांव का सर्वांगीण विकास कराया जाना है. यह भी बताया कि योजना के तहत अन्य गांवों का भी चयन आने वाले समय में किया जायेगा. जिससे जिले में गांवों की तस्वीर बदलेगी.

सांसद के घोषणा की खबर स्थानीय समाचार पत्रों में आने के अगले ही दिन से जिले में राजनीतिक चर्चा जोर पकड़ने लगी. इसमें मुख्यत: दो बाते प्रमुख रहीं. चल रही चर्चा में पहली बात यह है कि बरियारपुर गांव का चयन

मुखिया गीता देवी

सांसद राम कुमार शर्मा

इसलिए किया गया कि यह उनके मामा का गांव है तो दूसरी यह कि उनकी कुशवाहा बिरादरी का उक्त गांव में वर्चस्व है. लोगों का कहना है कि अगर सांसद द्वारा अपने रिश्तेदार के गांव का चयन किया गया है तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के फरमान को गठबंधन में रहते अंगूठा दिखाने का साहस किया गया है. वही दूसरी ओर जातीय राजनीति के तहत अगर अपनी बिरादरी का ख्याल रखा गया है तो इसका खामियाजा आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी गठबंधन को भुगतना पड़ सकता है. पार्टी सूत्रों की मानें तो सांसद ने योजना के तहत गांव का चयन किये जाने को लेकर जिले में गठबंधन दल के पार्टी कार्यकर्ताओं से किसी भी प्रकार का विचार-विमर्श तक करना मुनासिब नहीं समझा है. इसकों लेकर गठबंधन दल के पार्टी नेता से लेकर कार्यकर्ता तक में रोष गहराने लगा है. अब एक नजर चयनित आदर्श ग्राम बरियारपुर पर डालना आवश्यक है. सीतामढ़ी-सुरसंड एनएच-104 के करीब मौजूद इस गांव की आबादी तकरीबन 14 हजार है. इसमें कुल मतदाताओं की संख्या लगभग साढ़े 6 हजार बताई जाती है. पंचायत की मुखिया गीता देवी की मानें तो जातिगत आधार पर अल्पसंख्यक पहले एवं कुशवाहा जाति दूसरे स्थान पर है. जबकि अनुसूचित जाति का तीसरा तो यादवों का चौथा स्थान है. मुख्यत: लपटी, जवाबीपुर, गोट व टोला मिला कर कुल 4 टोला में बसे बरियारपुर में शिक्षा की स्थिति बेहतर है. यहां प्राथमिक, मध्य व उच्च विद्यालय के अलावा एक कॉलेज भी है. केवल बालिका उच्च विद्यालय की स्थापना अब तक नहीं की जा सकी है. स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल बेहाल है. गांव में मौजूद एक उप स्वास्थ्य केंद्र विभागीय उदासीनता के कारण वर्षों से नकारा बना है. केंद्र का लाभ गांव के लोगों को नहीं मिल पा रहा है. बिजली का हाल भी बेहाल है. गांव से गुजरने वाली मुख्य सड़क के किनारे तो बिजली के पोल से बल्ब जलता है, लेकिन गांव में अब भी बांस के सहारे ही लोग बिजली का उपयोग करने को विवश है. एनएच के किनारे बसे गांव में सड़कों की स्थिति बदहाल है. किसानों के लिए सिंचाई एक गंभीर चुनौती बनी है. सरकारी स्तर पर गांव में दो नलकूप मौजूद हैं, लेकिन पिछले एक दशक से किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है.

ऐसी स्थिति में अब सवाल यह उठता है कि सांसद महज एक साल में योजना के तहत इतनी बड़ी आबादी वाले गांव में अलादीन का कौन सा चिराग जला सकेंगे? अगर समय सीमा के अंदर गांव में विकास का सितारा नहीं चमका तो पीएम की योजना माखौल बन कर रह जायेगा, जिसे आगामी विधानसभा चुनाव के मौके पर विरोधी दल आसानी से जनता के बीच जाने में कोई कसर नही छोड़ेंगे. दूसरा यह कि संपन्न लोकसभा चुनाव में रालोसपा प्रत्याशी को भाजपा गठबंधन के तहत अन्य का भी पुरजोर समर्थन मिला है. तब सांसद का स्वजातीय प्रेम पाश में फंसना कहीं से भी उचित नहीं है. अगर सांसद जातीय राजनीति की नींव मजबूत करने की मंशा पाल रखे हैं तो निश्चित रूप से इसका खामियाजा रालोसपा को अगले चुनाव में भुगतना पड़ सकता है. जहां तक जिले में राजनीति की बात है तो लोकसभा चुनाव के बाद से ही विधानसभा चुनाव में भाजपा गठबंधन को सबक सिखाने की योजना बनायी जाने लगी है. भाजपा गठबंधन में भाजपा के अलावा रालोसपा अथवा लोजपा सीतामढ़ी में खुद ऐसी औकात में फिलहाल नहीं है कि राजद-जदयू-कांग्रेस गठबंधन से दो-दो हाथ कर सके. जबकि जदयू-राजद व कांग्रेस गठबंधन के तहत वोट बैंक अब भी मजबूत बताया जाता है. इस स्थिति में सांसद को फूंक-फूंक कर कदम उठाने की आवश्यकता है, अन्यथा भाजपा गठबंधन जिले में 'फिल गुड' का शिकार होकर गठबंधन की लुटिया भी डुबा सकती है. वैसे अभी विधानसभा चुनाव में वक्त है. पहले बरियारपुर गांव की नयी तस्वीर क्या होगी इस पर सभी की नजरें टिकी है.■

feedback@chauthiduniya.com

गंडक नदी में अवैध नाव परिचालन

प्रो. अरविन्द नाथ तिवारी

शिवालिक पहाड़ियों की कोख से निकलनेवाली गंडक नदी के घाटों पर प्रशासन के पाबंदी लगाने के बावजूद बेखौफ और अवैध ढंग से नावों का परिचालन करके धन उगाही इन दिनों किया जा रहा है. अवैध ढंग से नावों का परिचालन होने से कई बार नावें डूब चुकी है और सैकड़ों लोगों की जानें जा चुकी हैं. लोगों के डूबने और मरने के बाद प्रशासन की तन्द्रा भंग होती है, फिर ऐसे नावों के परिचालन पर रोक लगाने और प्राथमिकी दर्ज करने की बात प्रशासन द्वारा की जाती है. सूत्रों की बात अगर मानी जाय तो प चंपारण स्थित गंडक नदी के विभिन्न घाटों पर बेखौफ अवैध ढंग से नावों का परिचालन किया जा रहा है.

बगहा के कैलाशनगर, शास्त्रीनगर, दीनदयालनगर, लौकरिया, पूजहा, घोड़हिया, मरचहिया, आदि जगहों के घाटों पर एक बार नहीं कई बार हादसें हो चुके हैं. कई लोगों की जानें जा चुकी है. उदाहरण तौर पर बगहा शहर के नजदीक कैलाशनगर घाट पर बारह जून दो हजार बारह में ज्योति कुमारी और छोटी कुमारी की जान नाव डूबने से गयी थी. वर्ष दो हजार सात में शास्त्रीनगर घाट पर नाव डूबने से पांच महिलाओं और एक पुरुष का जान गई थी. सुशीला, पूनम, ज्ञांति, रमावती, किरण देवी महिला और किशोर सहनी नामक आदमी मरे थे. इसी घाट पर दो हजार आठ में नगीना यादव और विनोद सहनी नाव डूबने से मरे थे. सन दो हजार दस में इसी घाट पर दोबारा घटना हुई पर प्रशासन को कभी चेतना नहीं आई. सरकार के पदाधिकारी प्रतिबन्ध लगाने के घोषणा करते रहे. तत्कालीन जिलाधिकारी के आदेश पर अनुमण्डल पदाधिकारी रमण कुमार ने घाटों का सर्वेक्षण भी करवाया था.घटना को रोकने के लिए सरकारी नाव चलाने का बात कहा गया.पर कार्यवाही शिफर रही. कैलाशनगर घटना के पहले दो हजार पांच में सिंगही घाट पर नाव दुर्घटना में चौदह लोग मारे गये थे. सन दो हजार सात में बथना घाट पर दो लोग मरे थे.सन दो हजार दस में घोड़हिया घाट पर नाव डुबने से मदन भर, नगीना यादव, लक्ष्मीना देवी एक दर्जन से ज्यादा लोग मरे थे. दो हजार ग्यारह में पूजहा घाट पर बच्ची समेत महिला की मौत हुई थी. सूत्रों के अनुसार घटना होने का कारण है, प्रशिक्षित नाव चालकों का अभाव और जर्जर नावों का चलना. घाटों पर नाबालिग बच्चे भी नाव खेते हुए देखे जाते हैं. घटनायें होती गयी,सरकार का ध्यान केवल घटना होने के समय तक रहा. बुद्धिजीवियों का मानना है कि जर्जर नाव समेत अवैध ढंग से चल रही नावों के परिचालन पर सरकार को रोक लगानी चाहिए. गत माह लौकरिया घाट पर नाव हादसा हुआ है. पर प्रशासन इस व्यवस्था से बेखबर है. बहरहाल अभी जिला में बेखौफ अवैध ढंग से नाव का परिचालन किया जा रहा है.लोगों का मानना है कि इस पर रोक लगनी चाहिए.■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार
01 सितंबर–07 सितंबर 2014
Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

उत्तर प्रदेश – उत्तराखंड

कांग्रेसियों ने नेशनल हेरल्ड को नीलामी तक पहुंचाया

के. विक्रम राव

कैसरबाग चैराहे के पास की मिशन स्कूल वाली इमारत पर जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1938 में तिरंगा फहरा कर दैनिक अख़बार नेशनल हेरल्ड की शुरूआत की थी. आज उनके नवासे की पत्नी के रहते, नेहरू परिवार की इस सम्पत्ति की सरेआम बोली तहसीलदार सदर ने लगवा दी, ताकि चार सौ कार्मिकों के बाइस माह के बकाया वेतन के चार करोड़ रुपये वसूले जा सकें. यूपी प्रेस क्लब में एक बार अटल बिहारी वाजपेयी ने संवाददाताओं के पूछने पर कहा था कि जो हेरल्ड नहीं चला पाए, वे भला देश क्या चला पाएंगे? टिप्पणी सटीक थी, सच हो सकती है. देश की जंग-ए-आजादी को भूगोल का आकार देने वाला हेरल्ड आज खुद इतिहास में चला गया. जब इसके संस्थापक संपादक के. रामाराव ने सितंबर 1938 में प्रथम अंक निकाला था, तभी उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि लंगर उठाया है तूफान का असर देखने के लिए.

तूफान काफ़ी उठे, लेकिन हेरल्ड की कश्ती लंबा सफर तय करती रही. आज यदि डूबी भी तो किनारे से टकराकर. उसके प्रबंधक महज तमाशाई बने रहे. क्या वजह है कि पुनर्जीवित कांग्रेस के काल में हेरल्ड का अस्तित्व मिट गया, जबकि इसकी हस्ती उस ब्रिटिश राज के वक्त भी बनी रही थी. भले ही दौरे जमाना उसका दुश्मन था? वर्ष 1941 में एक बार अमीनाबाद के व्यापारी भोलानाथ ने अखबार छापने के लिए कागज देने से मना कर दिया था, क्योंकि उधार काफी हो गया था. नेहरू ने तब एक रुक्के पर दस्तखत कर हेरल्ड को बचाया था. हालांकि नेहरू ने कहा था कि सारे जीवन भर मैं ऐसा प्रामिसरी नोट न लिखता. पिता की भांति पुत्री ने भी हेरल्ड को बचाने के लिए गायिका एम एस सुब्बालक्ष्मी का कार्यक्रम रचा था, ताकि धनराशि जमा हो सके. इंदिरा गांधी तब कांग्रेस अध्यक्ष थीं.

रफी अहमद किदवई और चंद्रभानु गुप्त ने आपसी दुश्मनी के बावजूद हेरल्ड राहत के कूपन बेचकर आर्थिक मदद की थी. हेरल्ड ने आजाद भारत के समाचार पत्र उद्योग में क्रांति की थी. जब 1952 में संपादक की अध्यक्षता में सहकारी समिति बनाकर प्रबंध चलाया गया था. तब प्रधानमंत्री नेहरू ने प्रबंध निदेशक मोहन लाल सक्सेना (22 अप्रैल 1952) को लिखे पत्र में इस अभिनव श्रमिक प्रयोग की लालसा में पंजाब से पी. एल. सोंधी नाम के व्यवसायी को प्रबंधक बनाया था, जिसने दिवाला ही निकाल दिया. नौबत यहां तक आ गई कि नेहरू परिवार द्वारा स्थापित हेरल्ड जननिधि न्यास से छीनकर किसी सेठ जी के हाथ बेचने की विवशता भी तब आ पड़ी थी. उमाशंकर दीक्षित कुशल प्रबंध निदेशक बनकर आए और कश्ती बचा ली. प्रधानमंत्री के तीन मूर्ति आवास में वर्ष 1957 में निदेशकों की बैठक में सोंधी को बर्खास्त कर दीक्षित की नियुक्ति की गई. इस तरह नेशनल हेरल्ड, दैनिक नवजीवन और कौमी आवाज की बिक्री बढ़ी और विज्ञापनों का अंबार लग गया. यह भी एक विडंबना थी, क्योंकि श्रमिक संगठन का अगुवा हमेशा निदेशक मंडल की बैठक में शिरकत करता था. हेरल्ड तीन साल के अंदर ही (1941) बंदी के कगार पर था. पत्रकारों और अन्य कार्मिकों ने स्वेच्छा से अपना वेतन आधा करवा लिया था और तीन महीने तो बिना वेतन के ही काम किया. कई अविवाहित कर्मचारी हेरल्ड परिसर में ही सोते थे. कॉमन किचन भी चलता था, जहां चंदे से खाना पकता था.

वर्ष 1979 से 1986 तक इंदिरा गांधी के अत्यंत विश्वस्त सहायक यशपाल कपूर प्रबंध निदेशक रहे. साढे सात वर्ष तक यशपाल कपूर हेरल्ड पर छाए रहे. उस दौर में पटना, मुंबई, इंदौर, भोपाल आदि नगरों में कांग्रेसी सरकारों की अनुकंपा से महंगी जमीन प्रेस के लिए कौड़ियों के भाव खरीदी गई. जितना पैसा आता था वह खत्म हो जाता. श्रमिक भुगतते रहे. हाल की नीलामी उसी लूट की पराकाष्ठा है. यह नीलामी भी श्रमिकों के कारण नहीं, वरन निर्मम व ढीठ प्रबंधन के चलते हुई. दिलचस्प घटना है यह श्रमिक संघर्ष के इतिहास में अक्टूबर 24, 1998 को हाईकोर्ट के वकीलों ने हड़ताल रखी थी. इससे हेरल्ड के श्रमिकों का भाग्य खुल गया. उसी दिन साल भर से टलती जा रही उनकी रिट याचिका सुनवाई पर लगी थी. याचिका लखनऊ जिलाधिकारी की उदासीनता और निष्क्रियता के खिलाफ थी. श्रमिकों ने गत वर्ष उपश्रमायुक्त द्वारा वेतन भुगतान के लिए प्रबंधकों पर लागू रिकवरी प्रमाण पत्रा जारी कराया था. पर जिलाधिकारी ने इसे रूटीन मामला समझ कर दफना दिया था. हाईकोर्ट में भी व्यस्तता के कारण शीघ्र सुनवाई नहीं हो पा रही थी.

हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी की ढिलाई पर रोष व्यक्त किया और वेतन भुगतान के लिए फौरी कार्यवाही का आदेश दिया. जिला प्रशासन जगा और दिल्ली में हेरल्ड के प्रबंधकों को भी जगाया. बजाय वेतन भुगतान के प्रबंधकों ने नीलामी की कार्यवाही स्थगित कराने का असफल प्रयास किया. श्रमिकों से वे संवाद स्थापित कर सकते थे कि मिलकर समस्या का समाधन ढूंढें पर उन्हें परवाह नहीं थी. इसका बुनियादी कारण यह है कि मोहम्मद यूनुस, उमाशंकर दीक्षित आदि प्रबंध निदेशक लखनऊ के मुख्य कार्यालय से काम करते रहे, जबकि आज के प्रबंधक दिल्ली में सत्ता के गलियारे के निकट रहे जिससे मुख्यालय लखनऊ उपेक्षित रहा है.

नीलामी की नौबत आने के पूर्व लखनऊ के श्रमिकों ने जी-जान से काम किया. बिजली का बिल बत्तीस लाख रुपए हो गया था. कांग्रेस-विरोधी भाजपाई मुख्यमंत्री कल्याण सिंह से अनुरोध कर बिना भुगतान के बिजली सप्लाई श्रमिकों ने ही चालू रखाई ताकि मशीनें बंद न हों. टेलीफोन कट गए तो पीसीओ लगवाया ताकि संचार सम्पर्क बना रहे. संवाद समितियों ने भुगतान न होने पर अपनी लाइनें काट दीं तो हेरल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज के सारे रिपोर्टर शहर में घूम-घूम कर समाचार बटोरते रहे ताकि अखबार में पर्याप्त प्रकाशन सामग्री जुटाई जा सके. इस पर भी लखनऊ और दिल्ली का प्रबंधन चेता नहीं. जब चेता तो बोली लग चुकी थी. अंततः क्रमिक दशा ऐसी हुई कि चल संपत्ति की नीलामी के बाद अचल संपत्ति बिकेगी, जिसमें कैसरबाग चैराहे के दोनों ओर के भवन और फिर नई दिल्ली के बहादुरशाह जफर मार्ग की भव्य इमारत भी नीलाम होगी. तब भी बकाया रहा तो वसूली के लिए हेरल्ड की मालकिन सोनिया गांधी की अन्य सम्पत्ति की बिक्री की मांग उठ सकती है.

वह मशीनें भी थीं जिन्हें फिरोज गांधी अपने कुर्ते से कभी-कभी पोंछते थे. वह फर्नीचर जिस पर बैठकर इतिहास का क्रम बदलने वाली खबरें लिखी गई थीं. पिछले साठ वर्ष का हेरल्ड का दौर उत्तर प्रदेश और भारत के घटनाचक्र से अभिन्न रहा है. इसकी शुरुआती कड़ी 1938 के गर्मी के मौसम में बनी थी. संयुक्त प्रांत (तब यू.पी. का यही नाम था) में विधानसभा निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बहुमत मिल गया था. जवाहरलाल नेहरू ने सुझाया कि पार्टी को अपना दैनिक समाचार पत्र छापना चाहिए, क्योंकि तब के अंग्रेजी दैनिक अंग्रेजों के समर्थक थे.

एक कंपनी पंजीकृत हुई. नाम रखा गया एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड. नेहरू बने अध्यक्ष और निदेशक मंडल में थे फैजाबाद के आचार्य नरेंद्र देव (प्रख्यात समाजवादी चिंतक), बाराबंकी जिले के मसौलीवासी रफी अहमद किदवई (बाद में केंद्रीय मंत्री), आगरा के राजर्षि पुरुषोत्तमदास टंडन और डाक्टर कैलाशनाथ काटजू, नैनीताल के गोविंद वल्लभ पंत, गंगाघाट, उन्नाव के एम.ए. सोख्ता और अमीनाबाद, लखनऊ के मोहनलाल सक्सेना (बाद में केंद्रीय मंत्री). अब प्रश्न था संपादक कैसा हो? राष्ट्रवादी हो और वेतन के बजाय मिशन की भावना से काम करने वाला हो. पहला नाम था श्री पोथन जोसेफ, जो तब दिल्ली में हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक थे और बाद में जिन्ना के मुस्लिम लीग दैनिक दि डॉन के संपादक बने. उन्हीं दिनों अपने कराची अधिवेशन में राष्ट्रीय कांग्रेस ने तय किया था कि सारे कांग्रेसी सरकार के मंत्री सादा जीवन जिएंगे और मासिक आय पांच सौ रुपए से अधिक नहीं लेंगे. पोथन जोसेफ खर्चीली आदतों वाले थे. पांच सौ रुपए वेतन कैसे स्वीकारते. हेरल्ड के संपादक को कांग्रेसी मंत्री से अधिक वेतन देना वाजिब भी नहीं था. फिर नाम आया मुंबई दैनिक दि फ्री प्रेस जर्नल के संपादक के. श्रीनिवासन का. बांबे क्रानिकल के मशहूर संपादक सैय्यद अहमद बरेलवी से सुझाव मांगा. बरेलवी के साथ युवा के. रामाराव काम कर चुके थे. बरेलवी ने रफी साहब से कहा कि नया अखबार है तो आलराउंडर को संपादक बनाओ जो प्रूफ रीडिंग से लेकर संपादकीय लिखने में हरफनमौला हो. अतः रामाराव ही योग्य होंगे. तब वे दिल्ली में हिंदुस्तान टाइम्स में समाचार संपादक थे. तब केंद्रीय विधानसभा की प्रेस दीर्घा में बैठे रामाराव से सांसद मोहनलाल सक्सेना ने नेहरू के आग्रह को बताया. उन्हें इंटरव्यू के लिए रफी साहब ने लखनऊ के विधानभवन में अपने मंत्री कक्ष में बुलवाया. उन्होने पूछा कि आप वाकई में संपादन कार्य कर सकेंगे? रामाराव का जवाब संक्षिप्त था, बस, वही काम मैं कर सकता हूं. फिर हेरल्ड के संघर्षशील भविष्य की चर्चा कर, रफी साहब ने पूछा, जेल जाने में हिचकेंगे तो नहीं? रामाराव हंसे, बोले, मैं पिकनिक के लिए तैयार हूं. बाद में 1942 में रामाराव को उनके संपादकीय जेल और जंगल के लिए छह माह तक लखनऊ सेंट्रल जेल में कैद रखा गया था. रामाराव के संपादकीय सहयोगियों में तब थे त्रिभुवन नारायण सिंह (बाद में संविद सरकार के मुख्यमंत्री), अंसार हरवानी (बाद में लोकसभा सदस्य), आर.डी. क्वाटरा और एम. चलपति राव. एक सादे समारोह में नेशनल हेरल्ड की शुरुआत हुई. जवाहरलाल नेहरू अपने भाषण को खुद आकर रिपोर्ट के रूप में लिखते थे. उनका पहला वाक्य होता था, प्रमुख कांग्रेस नेता जवाहरलाल नेहरू ने आज एक सार्वजनिक सभा में कहा.... आदि. सीमित संसाधनों के कारण हेरल्ड कई संवाद समितियों की सेवा से वंचित रहता था. तभी की बात है शनिवार, सितंबर 3, 1939 को हिटलर पर ब्रिटेन ने युद्ध की घोषणा कर दी. यह सदी की सबसे बड़ी खबर थी. देर से ऑल इंडिया रेडियो ने सूचना प्रसारित की. नेहरू के जीजा (विजयलक्ष्मी के पति) आर.एस. पंडित ने टेलीफोन पर हेरल्ड के संपादकीय विभाग को यह बात बताई. रेडियो से खबर प्रकाशित करना कानूनी जुर्म था. संवाद समिति से यह खबर आई नहीं थी. उन दिनों रविवार को अखबार नहीं छपता था. अर्थात यदि उस शनिवार की रात युद्ध की खबर न छपती, तो अगला संस्करण तीन दिन बाद मंगलवार को होता. रामाराव ने खबर छाप दी. उधर दिल्ली में स्टेट्समैन ने भी यही किया. दूसरे दिन तफ्तीश हुई. स्टेट्समैन के संपादक ने कहा कि पाठकों के प्रति दायित्व निभाने के लिए रेडियो से खबर लेना उचित था. हेरल्ड से जवाब तलब करने की हिम्मत ब्रिटिश शासन जुटा नहीं पाया.

महात्मा गांधी ने हेरल्ड के पक्ष में अपनी पत्रिका हरिजन में लिखा कि ऐसा वित्तीय अन्याय बंद होना चाहिए. अक्सर जवाहरलाल नेहरू ऐसे अवसरों पर खुद अपील निकालते थे. हेरल्ड की एक परंपरा शुरू से रही है और आजादी के बाद भी बनी रही. वह थी समाचार प्रकाशन में निष्पक्षता बरतना तथा तनिक भी राग-द्वेष न रखना. तब आर्य समाज ने निजाम के खिलाफ आंदोलन चलाया था. सारे अखबार हैदराबाद की खबरों को खूब छापते रहे. अचानक हेरल्ड के अलावा सभी ने बिल्कुल चुप्पी साध ली. एक दिन निजाम का एक दूत संपादक रामाराव के कैसरबाग स्थित दफ्तर में आया. पहले उसने आर्य समाज कि बुराइयां बताईं. फिर उसने कुछ हेरल्ड के लाभ की बातें कीं. इसके पहले कि वह नोटों का बंडल खोलता, संपादक ने उसे खदेड़ा और फाटक तक दौड़ाया. आर्य समाज ने रामाराव को आंदोलन की खबर छापने पर एक आभार-पत्रा लिखा था. त्रिपुरा अधिवेशन में गांधी-नेहरू के विरोध के बावजूद सुभाष बोस कांग्रेस अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे. हेरल्ड ने बोस के समर्थन में काफी लिखा. कार्यालय पर सुभाष बोस आए और बोले, यह नेहरू का अखबार मेरे प्रति बड़ा संवेदनशील रहा. ईमानदार रहा.

आजादी के बाद का किस्सा है. बात 1960 की है. इमरजेंसी के दौरान जब संजय गांधी को सारे समाचारपत्रा वली अहद के रूप में पेश कर रहे थे तो लखनऊ हेरल्ड के स्थानीय संपादक सी.एन. चित्तरंजन ने संजय गांधी की तस्वीर छापने पर रोक लगा दी थी. तब के कांग्रेसी मुख्यमंत्री ने प्रबंध निदेशक मोहम्मद यूनुस से इसकी शिकायत की तो उन्हें जवाब मिला हेरल्ड संपादक की आत्मा हमेशा उसकी अपनी रही. हाईकोर्ट ने इंसाफ कर दिया. अब नीलामी की बोली गोमती पार कर यमुना के उस तट बहादुरशाह मार्ग तक गूंजेगी जहां नेहरू ने कैसरबाग के बाद हेरल्ड हाउस की नींव डाली थी. ■

घेरे में सोनिया-राहुल

वर्ष 2008 में नेशनल हेरल्ड को बंद करने के बाद उसका मालिकाना हक एसोसिएटड जर्नलिस्ट को दे दिया गया था. हेरल्ड को चलाने वाली कंपनी एसोसिएट जर्नल्स ने कांग्रेस पार्टी से बिना ब्याज के 90 करोड़ का कर्ज लिया. कांग्रेस ने कर्ज तो दिया और उसकी वजह बताई कि कर्मचारियों को बेरोजगार होने से बचाना. यहां सवाल खड़ा होता है कि आखिर कर्ज देने के बाद भी अखबार क्यों नहीं शुरू हुआ. इसके बाद 26 अप्रैल 2012 को नेशनल हेरल्ड का मालिकाना हक यंग इंडिया को दे दिया गया. यंग इंडिया कंपनी में 76 प्रतिशत शेयर सोनिया और राहुल गांधी के हैं. यंग इंडिया ने हेरल्ड की 1600 करोड़ की परिसम्पत्तियां महज 50 लाख में हासिल कीं. भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप है कि गांधी परिवार ने हेरल्ड की सम्पत्तियों का अवैध ढंग से उपयोग किया है. बाद में सुब्रमण्यम स्वामी इस विवाद को लेकर 2012 में कोर्ट पहुंच गए.

स्वामी का आरोप है कि कांग्रेस के धन को निजी सम्पत्ति में लगाकर अपने निजी हित के लिए इस्तेमाल किया गया. हेराल्ड हाउस के नाम से जो 1600 करोड़ रुपए की सम्पत्ति है, उसका इस्तेमाल निजी फायदे के लिए हुआ है. दावा किया जाता है कि नई दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग स्थित हेरल्ड हाउस की कीमत तकरीबन 1,600 करोड़ रुपए है. इस बिल्डिंग पर टीएजेएल का मालिकाना हक है. कांग्रेस ने 26 फरवरी, 2011 को टीएजेएल की 90 करोड़ रुपए की देनदारियों को अपने जिम्मे ले लिया. सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के कुछ अन्य नेताओं ने यंग इंडिया लिमिटेड नाम से एक कंपनी बनाई. यंग इंडियन में सोनिया और राहुल की 38-38 फीसदी हिस्सेदारी है. इसकी शेष हिस्सेदारी कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास है. टीएजेएल को 50 लाख रुपए देकर यंग इंडिया लिमिटेड ने कंपनी से 90 करोड़ रुपए वसूलने का अधिकार प्राप्त कर लिया. हेरल्ड हाउस को पासपोर्ट ऑफिस के लिए किराये पर दिया गया है. स्वामी का कहना है कि हेरल्ड हाउस को केंद्र सरकार ने समाचार पत्र चलाने के लिए जमीन दी थी. उसे व्यावसायिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता.

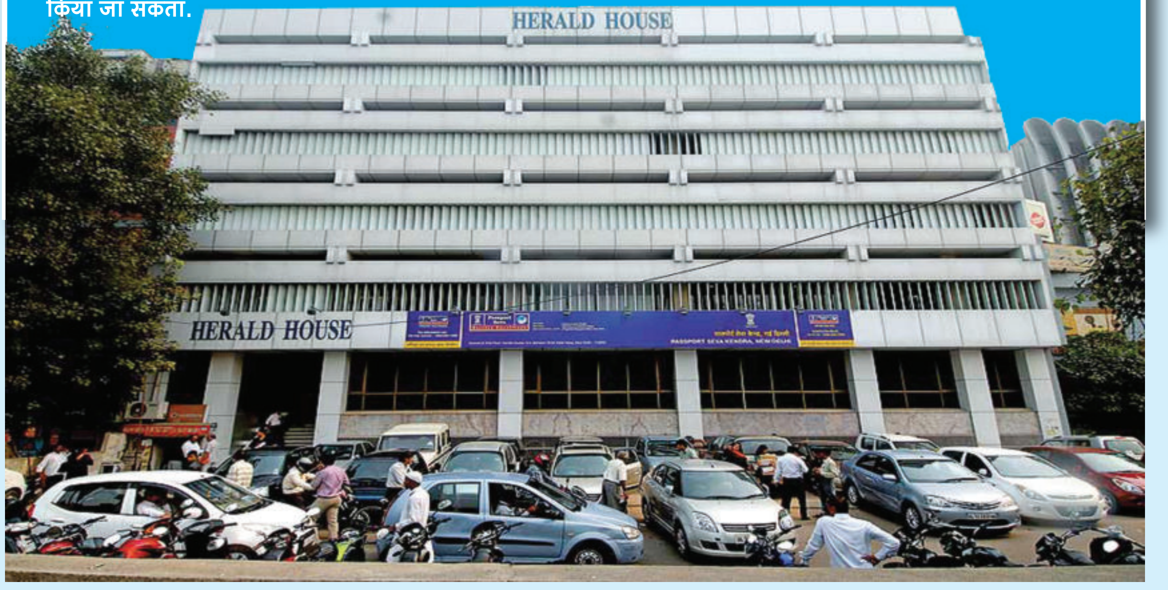

मुलायम-मायावती में नहीं हुआ गठजोड़

प्रभात रंजन दीन

राजनीति कब क्या शक्ल ले लेगी कहा नहीं जा सकता. कौन जानता था कि लालू के अराजक राज की मुखालफत की सियासत कर सत्ता तक पहुंचे नीतीश कुमार लालू के साथ ही गलबहियां खेलने लगेंगे. लिहाजा, हजार तर्कों और प्रति-तर्कों के बावजूद अभी यह निर्णायक तौर पर नहीं कहा जा सकता कि मुलायम और मायावती कभी मिलेंगे ही नहीं. मायावती नहीं मिलेंगी तो उनकी पार्टी मिलेगी. राजनीति में कुछ भी हो सकता है. नीतीश के साथ मिल कर व्यापक राजनीतिक समीकरणों का सपना बुन रहे लालू यादव ने जैसे ही कहा कि उत्तर प्रदेश में भी मुलायम और मायावती मिल सकते हैं, वैसे ही देशभर में यह संदेश गया कि जितनी भी भाजपा विरोधी पार्टियां हैं, वे सब अपना-अपना मतभेद भुला कर बड़ी एकता की व्यूह रचना करें, अन्यथा पुरजोर ताकत के साथ उभरी भाजपा का मुकाबला नहीं किया जा सकता. लालू ने उत्तर प्रदेश में मायावती और मुलायम को भी हाथ मिलाकर भाजपा के खिलाफ लड़ने की अपील कर डाली.

लोकसभा चुनाव में करारी हार से बौखलाए सपा नेता मुलायम सिंह यादव ने लालू यादव का दूरगामी इशारा समझते हुए फौरन ही यह कह दिया कि लालू समझौता कराएं तो वे मायावती से हाथ मिलाने को तैयार हैं. अमर सिंह से हाथ मिला कर मुलायम ने भविष्य की तैयारियों के संकेत दे ही दिए हैं. यह भी स्पष्ट कर दिया है कि राजनीति में कोई स्थाई दोस्त और कोई स्थाई दुश्मन नहीं होता. यह बात बिहार में नीतीश-लालू भी साबित कर चुके हैं. सपा सुप्रीमो मुलायम ने कहा कि वो मायावती से हाथ मिलाने को तैयार हैं अगर लालू मध्यस्थता करें तो. इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए. अभी हुए लोकसभा चुनाव में बसपा को एक भी सीट नहीं मिली थी, जबकि समाजवादी पार्टी पांच सीटों पर सिमट कर रह गई. इनमें दो सीटें मुलायम ने ही जीतीं, जिनमें से एक मैनपुरी सीट उन्हें छोड़नी पड़ी. स्पष्ट है मुलायम कोई चमत्कारिक समीकरण की तलाश में हैं, इसीलिए उन्हें मायावती से हाथ मिलाने से भी परहेज नहीं है.

मायावती से हाथ मिलाने की बात मुलायम सिंह यादव के मुंह से निकलते ही उत्तर प्रदेश की सियासत गरमा गई. यहां तक कहा जाने लगा कि मुलायम के संकेत पर बसपा भी इस दिशा में सोचने लगी है, लेकिन दलित वोट बैंक के खिसक जाने की आशंका इस गठजोड़ के रास्ते में आड़े आ रही है. लेकिन फौरन ही मायावती ने कह दिया कि उन्हें एकता का यह प्रस्ताव मंजूर नहीं है. मायावती ने कहा कि मुलायम के लिए सत्ता सब कुछ है लेकिन मेरे लिए मान-सम्मान से बढ़ कर नहीं है. उन्होंने मुलायम सिंह के साथ किसी भी गठबंधन से इनकार कर दिया और कहा कि वो सत्ता के लिए किसी भी तरह का समझौता नहीं करने वाली हैं. मायावती ने कहा कि मुलायम से हाथ मिलाने का सवाल ही नहीं उठता. उल्टा उन्होंने मुलायम पर साम्प्रदायिक हिंसा फैलाने का आरोप भी मढ़ डाला. मायावती ने कहा मेरे लिए मान-सम्मान पहले है और सत्ता बाद में. इस तरह उत्तर प्रदेश में दलित-पिछड़ा समीकरण बनाने के राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के सुझाव और सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव की पहल पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने पानी फेर दिया. सपा पर भाजपा से हाथ मिलाने का आरोप लगाते हुए और दुश्मनी का मुख्य कारण गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाकर मायावती ने साफ कर दिया कि वह किसी भी कीमत पर मुलायम सिंह को माफ नहीं करेंगी. मायावती का यह स्वर सुनते ही मुलायम ने भी पैंतरा बदला और कहा कि समाजवादी पार्टी बसपा से कोई रिश्ता नहीं चाहती. जबकि इससे पहले उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में भाजपा का मुकाबला करने के लिए उन्हें बसपा से हाथ मिलाने से कोई गुरेज नहीं है.

मेलजोल के प्रस्ताव पर खंडन और मंडन के समानान्तर, समाजवादी पार्टी के अंदरूनी गलियारे की खबर यही है कि पार्टी नेतृत्व ताकतवर तरीके से पिछड़ा-दलित-मुस्लिम समीकरण तैयार करना चाहता है. लिहाजा, मायावती के ऐलान के बावजूद बसपा से मेलजोल बढ़ाने की कोशिशें जारी हैं. इसके लिए बसपा नेताओं पर लगे भ्रष्टाचार के मुकदमे वापस भी लिए जा सकते हैं या मामलों को ठंडे बस्ते में भी भेजा जा सकता है. मुलायम से मिलने आए अमर सिंह ने जब एक सवाल के जवाब में कहा कि अगर मायावती अल्पसंख्यकों की हितैशी हैं, तो फिर नसीमुद्दीन सिद्दीकी को मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित करें, तो उत्तर प्रदेश के तमाम राजनीतिक समीक्षक इस वक्तव्य के राजनीतिक निहितार्थ निकाल रहे थे. बस अभी इतना ही समझ लें कि व्यापक एकता के लिए बसपा नेताओं को राजी करने और बसपा में एक ताकतवर समानान्तर दबाव पैदा करने की कोशिशें चल रही हैं जिसके आगे मायावती विवश हो जाएं. बहरहाल, यह राजनीति और यह कोशिश भविष्य में कौन सा शक्ल लेगी, इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता. लेकिन इतना साफ-साफ कहा जा सकता है कि मुलायम ने गठजोड़ की बात किसी बचकानेपन में नहीं कही थी. मुलायम इस प्रस्ताव के जरिए मुसलमानों को यह संदेश देने में सफल रहे कि वे भाजपा की जीत से मर्माहत हैं और उसका मुकाबला करने के लिए वे बसपा जैसी दुश्मन पार्टी से भी हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं. इसके साथ ही उन्होंने यह भी साबित किया कि लोकसभा चुनाव में पांच ही सीटें जीतने के बावजूद सपा ही उत्तर प्रदेश में भाजपा का मुकाबला करने वाली अकेली पार्टी बची है. ■

प्रदेश में झगड़ते हैं, केंद्र में मिलते हैं

सपा और बसपा की राजनीति उत्तर प्रदेश से चलती है. उत्तर प्रदेश में तो ये पार्टियां एक दूसरे की धुर-विरोधी बनती हैं, पर केंद्र में ये साथ मिलकर अपना राजनीतिक हित साधती हैं. राजनीति का ऐसा अवसरवादी उदाहरण सपा और बसपा के सिवा किसी और दल में नहीं मिलता. मौकापरस्ती के इस खेल में दोनों दलों की राजनीतिक मजबूरियां क्या हो सकती हैं, यह जनता की समझ से परे नहीं है, दोनों दल खुद को चाहे कितनी भी चालाक समझती रहें. केंद्र में मिल कर कांग्रेस को समर्थन देना और प्रदेश में झगड़ा करने का माया-मुलायम का खेल किसी खास एजेंडे के तहत था. प्रदेश के लोगों को यह बखूबी समझ में आया कि दोनों दल राजनीतिक स्वार्थ या भय में कभी भी हाथ मिला सकते हैं. सपा, बसपा केंद्र की उस सरकार को बचाने के लिए एक साथ खड़े रहे, जिस सरकार ने देश को भ्रष्टाचार और महंगाई के नरक में धकेल दिया था. दोनों दलों ने जनता के हित को नजरअंदाज किया. सवाल उठता रहा कि प्रदेश के धुर-विरोधी आखिर केंद्र में गले क्यों मिलते रहे, लेकिन उनकी तरफ से इसका कभी कोई जवाब नहीं आया, लेकिन आम लोग सीबीआई के चंगुल से बाहर रहने के तिकड़म और उपक्रम को अच्छी तरह समझते रहे.

मायावती नहीं भूल पाईं गेस्ट हाउस कांड

स्टेट गेस्ट हाउस कांड का जिक्र कर मुलायम से दोस्ती की संभावनाओं को मायावती द्वारा खारिज किए जाने के बाद फिर यह साबित हुआ कि न केवल मायावती की मानसिकता बल्कि प्रदेश की राजनीति पर भी गेस्ट हाउस कांड का भूत अब तक नाच रहा है. पंचायत चुनाव में एक दलित महिला प्रत्याशी को नामांकन नहीं भरने देने की घटना ने गेस्ट हाउस कांड का सूत्रपात किया था. पंचायत चुनावों के जरिए मुलायम अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे, जबकि कांशीराम की इच्छा सत्ता में भागीदारी के सहारे पंचायतों में भी अपनी जमीन तलाशने की थी. कांशीराम बीमार थे और यह काम मायावती के ऊपर था. मुलायम के अड़े रहने पर बसपा ने मुलायम से समर्थन वापस लेने का ऐलान कर दिया. मायावती लखनऊ में मीराबाई मार्ग स्थित स्टेट गेस्ट हाउस में थीं. सपाइयों ने गेस्ट हाउस घेर लिया. जमकर हंगामा हुआ. मायावती ने खुद को कमरे में बंद कर लिया तो दरवाजा तोड़ने की कोशिश हुई. घटना की सूचना मिलने पर भाजपा नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी और लालजी टंडन मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कतों से मायावती को वहां से सुरक्षित निकाला. बाद में भाजपा ने बसपा को समर्थन देकर मायावती के नेतृत्व में सरकार बनवाई. जून 1995 में हुए स्टेट गेस्ट हाउस कांड ने प्रदेश की राजनीति को बदल कर रख दिया. इस घटना ने प्रदेश की राजनीति को तीन धुरों में बदल दिया. पहला धुर समाजवादी पार्टी, दूसरा मायावती के नेतृत्व वाली बहुजन समाज पार्टी और तीसरा धुर भाजपा की हिंदुत्व और राम मंदिर वाली राजनीति बन गई. मायावती और भाजपा कभी पास तो कभी दूर होती रही. सत्ता में रहने के लिए दोनों पार्टियों ने आपस में खूब पेंच लड़ाए और स्वार्थ टकराया तो दूर भी हटे. बसपा ने भाजपा को मोहरा बनाकर उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक जमीन और पकड़ मजबूत कर ली. जबकि भाजपा को इसका भीषण नुकसान ही उठाना पड़ा.

feedback@chauthiduniya.com

जल्द ही सामने आएगा बदायूं का असली सच

वैष्णवी वंदना

बदायूं कांड अपराध की वारदात नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी की सरकार को बदनाम करने की सुनियोजित साजिश थी, इसका आधिकारिक खुलासा जैसे-जैसे हो रहा है, वैसे-वैसे बदायूं-कांड पर जरूरत से ज्यादा हाय तौबा मचाने वाले नेता, समाजसेवी और मीडियाकर्मी अपना चेहरा छुपाने में लग गए हैं. इस घटना को लेकर जिस तरह का हौवा खड़ा किया गया और जिस तरह की मनगढ़ंत कहानियां रची गईं, सीबीआई जांच में उसके बिल्कुल विपरीत तथ्य सामने आ रहे हैं. यह मामला इस तरह सामने आ रहा है कि सीबीआई जल्दी ही एक राजनीतिक दल और उसके विधायक की संदिग्ध भूमिका को सामने ले आए और बदायूं कांड का पटाक्षेप हो जाए.

आपको याद ही होगा कि बदायूं कांड के बाद यूपी और दिल्ली के नेता और मीडिया वाले अखिलेश सरकार के खिलाफ कूद पड़े थे और सामाजिक मंचों से लेकर अखबारों-चैनेलों के जरिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की खूब छीछालेदर की गई. मीडिया ने इस बात पर भी मुख्यमंत्री की खिंचाई की थी कि घटना के बाद वो बदायूं क्यों नहीं गए! पहले तो मारी गई युवतियों को दलित बताने की भी सियासत की गई, लेकिन जल्दी ही यह रहस्य खुल गया कि वे दलित नहीं बल्कि पिछड़े वर्ग से आती थीं. फिर मामले को सीबीआई जांच के सुपुर्द करने का दबाव बना. सामूहिक बलात्कार के बाद हत्या की थ्योरी से इनकार करने वाली पुलिस रिपोर्ट को किनारे रख कर अखिलेश सरकार ने मामले की सीबीआई से जांच कराने का फैसला किया. आज यह साबित हुआ कि मामले की सीबीआई जांच कराने का फैसला अखिलेश सरकार का उचित फैसला था.

मामले की जांच कर रही सीबीआई अब उस विधायक को अपने घेरे में ले रही है जिसने मामले को राजनीतिक रंग देने के लिए दोनों बहनों की पेड़ से टंगी लाश को मीडिया के आने तक उतारने नहीं दिया था. एजेंसी को मामले से जुड़े ऐसे सटीक सुराग मिले हैं कि उसने दोनों बहनों की लाशों को कब्र से निकाल कर दोबारा पोस्टमॉर्टम कराने की जरूरत नहीं समझी. आधिकारिक तौर पर भले ही यह कहा गया कि दफ्न वाली जगह बाढ़ क्षेत्र में चले जाने के कारण यह संभव नहीं हो पाया. सीबीआई की जांच में यह पता चला कि दोनों बहनों के साथ बलात्कार हुआ ही नहीं था. एजेंसी की आधिकारिक रिपोर्ट अभी नहीं आई है, लेकिन स्थितियां करीब-करीब साफ हो चली हैं. आप याद करें कि इन लड़कियों के साथ दुष्कर्म नहीं होने की बात उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ने भी कही थी. इस मामले में पांच आरोपियों की गिरफ्तारी भी साजिश का ही परिणाम साबित हो रही है. इस मामले के पांच आरोपियों को लड़कियों के पिता और दो गवाहों के कहने पर गिरफ्तार किया गया था.

सीबीआई को सीडीएफडी (सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नॉस्टिक्स) की जो रिपोर्ट मिली है, उसमें भी बताया गया है कि जिन्हें आरोपी बनाया गया है, उन्होंने अपराध किया ही नहीं था. यह रिपोर्ट अब मेडिकल बोर्ड को भेजी गई है. गौरतलब है कि 28 मई 2014 को उत्तर प्रदेश के बदायूं में दो बहनों के शव पेड़ से लटके मिले थे. इसके बाद जांच एसआईटी और फिर सीबीआई को सौंपी गई. सीबीआई ने भी हाल ही में कहा था कि पांचों आरोपियों के लाई डिटेक्टर टेस्ट में कुछ भी पॉजिटिव नहीं मिला, जबकि दोनों पीड़िता के पिताओं का यह टेस्ट हुआ तो वे संदिग्ध निकले. दोनों बहनों के पिताओं ने आरोप लगाए थे कि पुलिस इस मामले में संदिग्ध यादव समुदाय के लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है. स्थानीय डॉक्टर के पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में बताया गया था कि बलात्कार करने के बाद दोनों बहनों को जिंदा ही फांसी पर लटका दिया गया था. फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक आरोपियों का डीएनए पीड़ित बहनों के कपड़ों पर मिले सैंपल से मैच नहीं हुआ है. यानी, प्राथमिक तौर पर जो पोस्टमॉर्टम हुआ उसकी रिपोर्ट फर्जी तरीके से गढ़ी गई. लिहाजा, अब संबद्ध डॉक्टर के सीबीआई के घेरे में आने की पूरी संभावना है. सीबीआई के मुताबिक यह केस ऑनर-किलिंग का हो सकता है. डीएनए रिपोर्ट के बाद अब सीबीआई को यह कहने का मजबूत आधार मिल गया है.

सीबीआई इस मामले में एक स्थानीय नेता को शक के घेरे में रख रही है. इस नेता ने ही कथित रूप से पारिवारिक सदस्यों को सारा दोष पांचों आरोपियों, पप्पू, अवधेश, उर्वेश यादव, कांस्टेबल छतरपाल और सर्वेश यादव पर मढ़ने के लिए उकसाया था. यह सभी आरोपी यादव जाति से ताल्लुक रखते हैं. घटना के बाद लड़की के परिवार के सदस्यों ने आरोप लगाया था कि यूपी सरकार दोषियों को बचा रही है. यूपी के डीजीपी एएल बनर्जी ने तभी दावा किया था कि दोनों लड़कियों में से एक लड़की का बलात्कार होने की पुष्टि नहीं हुई है. अब तो सीबीआई भी उत्तर प्रदेश पुलिस के उस दावे को सही मान रही है. पीड़ित लड़कियों के कपड़ों व अन्य सामान की हैदराबाद की फॉरेंसिक लैब में हुई थी, जांच की रिपोर्ट के बाद ही सीबीआई इस नतीजे पर पहुंची कि लड़कियों के साथ बलात्कार नहीं हुआ था. इस रिपोर्ट को विश्लेषण के लिए मेडिकल बोर्ड को सौंप दिया है. अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि दोनों लड़कियों की हत्या किसने की थी. इस मामले में गिरफ्तार पांचों आरोपियों को पॉलीग्राफिक टेस्ट के बाद पहले ही क्लीन चिट दी जा चुकी है. सीबीआई इन आरोपियों की जमानत अर्जी का अदालत में विरोध नहीं करेगी.

बदायूं कांड को लेकर जिस समय हाय तौबा मचाई गई उस समय भी कहा गया था कि यह घटना समाजवादी पार्टी की सरकार के लिए ऐतिहासिक नकारात्मक घटना साबित होगी. बदायूं कांड ऐतिहासिक तो साबित होगा, लेकिन उसकी नकारात्मकता विरोधी पार्टी के शर्मनाक अध्याय साबित होगी. अब सरकार को सीबीआई की रिपोर्ट दाखिल होने और उस पर अदालत का फैसला आने की प्रतीक्षा है, क्योंकि निश्चित तौर पर जिस कांड को राजनीतिक नुकसान के लिए रचा गया था, वह कांड अब समाजवादी पार्टी की सरकार को फायदा पहुंचाएगा. विधानसभा और लोकसभा के उपचुनाव जल्दी ही होने वाले हैं और संभव है कि बदायूं कांड के सुनियोजित रहस्य से भी उसी समय पर्दा उठे. हर बात को बतंगड़ बनाने वाले मीडिया के लिए भी यह घटना सीख लेने वाली घटना ही साबित होने वाली है. ■

बदायूं कांड को लेकर जिस समय हाय तौबा मचाई गई उस समय भी कहा गया था कि यह घटना समाजवादी पार्टी की सरकार के लिए ऐतिहासिक नकारात्मक घटना साबित होगी. बदायूं कांड ऐतिहासिक तो साबित होगा, लेकिन उसकी नकारात्मकता विरोधी पार्टी के शर्मनाक अध्याय साबित होगी. अब सरकार को सीबीआई की रिपोर्ट दाखिल होने और उस पर अदालत का फैसला आने की प्रतीक्षा है, क्योंकि निश्चित तौर पर जिस कांड को राजनीतिक नुकसान के लिए रचा गया था, वह कांड अब समाजवादी पार्टी की सरकार को फायदा पहुंचाएगा.

feedback@chauthiduniya.com

दैवीय आपदा से सरकार हलकान

राजकुमार शर्मा

उत्तराखंड सरकार का आपदा प्रबंधन की सारी व्यवस्था एक बार फिर ऊट के मुंह में जीरा साबित हुई है. राज्य में हुई मुसलाधार बारिश ने सरकारी व्यवस्था की एक बार फिर से पोइ खोल कर रख दी है. राज्य सरकार की ओर से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हो पायी कि प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को तुरंत राहत प्रदान की जा सके. सूबे में तबाही ने अपना दिखाना शुरू किया तब सरकार ने आनन-फानन में दो हेलीकॉप्टर के जरिए मदद पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू की.

प्रदेश में आई भीषण आपदा को एस साल से अधिक हो गए हैं, अब तक ऐसी कोई व्यवस्था सरकार द्वारा नहीं की गयी है कि यदि भविष्य में पहल की तरह यदि कोई आपदा आती है, तो इससे बचाव के लिए राज्य सरकार किस तरह का कदम उठाएगी. पौड़ी के बैरागढ़ गांव में सबसे पहले दोनों हेलीकॉप्टर उतारे गए तब तक तो बारिश से जान-माल का नुकसान काफी हो चुका था. बीते एक माह पहले आपदा प्रबंधन की सचिवालय में हुई एक आवश्यक बैठक में यह तय किया गया कि संवेदनशील 20 से अधिक क्षेत्रों में यदि मूसलाधर बारिश होती है, तो ज्यादा तबाही पैदा हो सकती है. इन क्षेत्र के जिलाधिकारियों को इस समय भी विशेष अलर्ट के निर्देश जारी किये गये और साफ-साफ कहा गया कि किसी भी तरह की आपदा से निपटने के लिये एक टीम बना ली जाए. साथ ही इसकी भी प्लानिंग कर ली जाये कि यदि प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को हटाने की आवश्यकता पड़ेगी, तो इन्हें कहां हटाया जाएगा. प्रदेशवासी आपदा से खुद ही जूझने को मजबूर हैं. यह हालत तब हैं जब सरकार आपदा से निपटने के लिए तमाम दावे कर रही है और सारे दावे मुख्यमंत्री हरीश रावत स्वंय कर रहे है. इसके लिए केंद्र से करोड़ों रुपये की मदद दी जा रही है. उपलब्धि के नाम पर एसडीआरएफ का गठन हुआ है. गत वर्ष आपदा के बाद हुई बैठकों में आपदा से निपटने के लिए नीतियां तो बनीं, लेकिन उन्हें धरातल पर आने में काफी समय लग गया. पौड़ी में बादल फटने की घटना को ही देखें तो वहां घटना के कई घंटों बाद प्रशासनिक अमल के पहुंचने पर राहत और बचाव कार्य शुरू हो पाए. मुख्य मार्ग और संपर्क मार्ग अवरुद्ध होने के कारण कई प्रभावित स्थानों का संपर्क टूटा हुआ है. वहां प्रभावितों को बचाने और राहत मुहैया कराने का काम हेलीकॉप्टर के जरिए ही हो सकता है. इसके लिए प्रशासन पूरी तरह मौसम पर निर्भर है. बचाव दलों को मौके पर तुरंत भेजना सरकार के सामने चुनौती बना है. इस घटना ने सरकार की ओर से आपदा प्रबंधन के लिए ग्राम पंचायत स्तर तक पुख्ता इंतजाम किए जाने के दावों की पोल खोल दी है. राजधानी में भी हालात बेहतर नहीं है, घटना के कुछ घंटों बाद मौके पर पहुंचा प्रशासनिक अमला उपकरणों के अभाव में केवल तमाशबीन ही बना रहा. साफ है कि आपदा प्रबंधन के लिए अभी भी ठोस कदम उठाए जाने शेष हैं.

केवड़ इतना ही नहीं एक माह पहले हुई बैठक में यह भी तय किया गया कि मदद के लिये आवश्यक खाद्य सामग्री भी जिला मुख्यालयों में सुरक्षित रखी जाये और आवश्यकता पड़ने पर जिला मुख्याइयों से ही राशन और कैरोसिन की सप्लाई की जाए. सरकारी बैठक में बनायी गई रणनीति कागजों पर ही सिमट कर रह गई. उसके बाद भी आपदा को लेकर कई बैठकें हुई , किसी भी अधिकारी ने यह जानने की कोशिश नहीं कि पहले दिए गये सुझावों पर किस-किस जिलाधिकारियों ने आपदा से बचाव के डिए क्या-क्या उपाय किये हैं. विशेष परिस्थिति में प्राथमिक उपचार के लिये आवश्यक दवाइयां भी इन उपचार केंद्रों में पहले से रिजर्व में रखी जानी चाहिए. दुर्भाग्य यह है कि इस दिशा में भी आवश्यक कदम नहीं उठाए गए. सबसे अचरज वाली बात यह है कि किसी भी उच्च नौकरशाह या मंत्री ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा अभी तक नहीं किया है.

मुख्यमंत्री हरीश रावत स्वयं आपदा प्रबंधन विभाग का दायित्व भी रखे हुए है और कहते है कि आपदा प्रबंधन पूरी तरह से अलर्ट है. जो भी आवश्यक राहत है. उपलब्ध कराया जा रहा है. स्थिति अब सुधर रही है. दो हेलीकॉप्टर भी लगाए हैं. ■

प्रदेश में आई भीषण आपदा को एस साल से अधिक हो गए हैं, अब तक ऐसी कोई व्यवस्था सरकार द्वारा नहीं की गयी है कि यदि भविष्य में पहल की तरह यदि कोई आपदा आती है, तो इससे बचाव के लिए राज्य सरकार किस तरह का कदम उठाएगी. पौड़ी के बैरागढ़ गांव में सबसे पहले दोनों हेलीकॉप्टर उतारे गए तब तक तो बारिश से जान-माल का नुकसान काफी हो चुका था.

feedback@chauthiduniya.com

नीलकंठ धाम में बारिश और भूस्खलन का कहर

रेनु शर्मा

उत्तराखंड के पौराणिक नीलकंठ धाम में भी बारिश और भूस्खलन ने कहर बरपाया है. दर्जनभर से अधिक दुकानें पहाड़ी मलबे की चपेट में आकर तबाह हो गई. महादेव मंदिर में भी बारिश का पानी और मलबा घुस गया. जिसे साफ कर लिया गया है. वहीं धाम तक पहुंचने वाले मार्ग भी कई जगह भूस्खलन के चलते पूरी तरह से अवंरुद्ध हैं. धाम में अभी भी खतरा बरकरार है. भारी बारिश के कहर से नीलकंठ भी अछूता नहीं रहा. पौराणिक पंकजा नदी अचानक उफना गई. जिसके साथ बहकर आए मलबे ने समीप ही एक दुकान को ढहाने के साथ दो दुकानों और मंदिर को भी चपेट में ले लिया. दुकानों और मंदिर में नदी के पानी के साथ मलबा भर गया. जिसके चलते मंदिर में पूरे दिन दर्शन बंद रहा. ज्योतिर्लिंग मंदिर के समीप पीपलकोटी मार्ग पर खतरे की आशंका से दुकानें खाली करते समय अचानक भारी भरकम बोल्डर गिर पड़े. जिससे जान का नुकसान तो नहीं हुआ, लगभग 12 दुकानें जमींदोज हो गईं. मंदिर समिति सदस्य धनसिंह राणा ने बताया कि मंदिर से मलबा साफ कर दर्शन शुरू हो गए जबकि क्षेत्र में अन्य जगहों पर लोग निजी प्रयासों से मलबा हटाने में जुटे हुए हैं. क्षेत्र में अभी भी खतरा बना हुआ है. वहीं सरकार की उदासीनता के कारण धाम तक का मार्ग भी कई जगह मलबे के कारण बंद है. जिससे शिवधाम में दर्शनार्थियों की संख्या सीमित रह गई है.

शिवधाम नीलकंठ कई दिनों से अंधेरे में है. वहीं क्षेत्र में भारी बारिश के कारण पेयजल आपूर्ति पर भी असर पड़ा है. बताया गया कि नीलकंठ में पिछले कई दिनों से विद्युत आपूर्ति ठप है. इसके चलते लोगों को अंधेरे में गुजारा करना पड़ रहा है. लगातार भारी बारिश और जगह-जगह भूस्खलन के कारण स्थिति और भी भयावह हो गई है. पेयजल सप्लाई की भी कमी बनी हुई है. कई स्थानों पर लाइनें टूटने के कारण पेयजल आपूर्तिठप हो गई है. लोगों को आसपास के श्रोतों से पीने का पानी जुटाना पड़ रहा है. ■

feedback@chauthiduniya.com

खंडूड़ी को नहीं चाहिए कोई पद

राजकुमार शर्मा

भाजपा के नायक रहे पूर्व मुख्यमंत्री जनरल भूवनचन्द्र खण्डूड़ी को साहब जैसे पद की जरूरत नहीं है. वे अपेन जीवन का एक एक दिन जनता की सेवा में अर्पित करना चाहते हैं. इसी मंसा से उन्होंने मीडिया में खुद को गर्वनर बनाए जाने की खबर पर पुरी तरह बिराम लगा दिया है. जनरल खण्डूड़ी दो बार उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री, अटल जी के सरकार में मंत्री रह चुके है, उनकी छवि पुरे देश में एक ईमानदार नेता की है. उन्हें शोभा का पद नहीं चाहिए वे सांसद रह कर जनता की सेवा कर अपने को जादा खुश रखना चाहते है. सेना में रहकर श्रेष्ठ सेवा का इतिहास रचने वाले जनरले खण्डूड़ी ने राजनीति में भी एक अलग पहचान के साथ जनसेवा का इतिहास रचा है, उत्तराखंड की जनता को मोदी सरकार से अपेक्षा थी की आपदा, भ्रष्टाचार की दोहरी मार झेइ रही जनता को नई रोशनी के रूप में अनुभवी, चरित्रवान एवं कर्मठ राजनेता को मोदी अपनी सरकार में सेवा का मौका देंगे. योगगुरू बाबा रामदेव के दबाव में उम्र के बहाने उत्तराखंड के नायक को किनारे लगा दिया गया. जनरल को अपनी पहली पसंद मानने वाली उत्तराखंड की जनता ने मोदी को अब आइना दिखाने की ठान ली है. आम चुनाव के पांच माह बाद ही राज्य में हुए उप चुनाव में जनता ने मोदी की लोकप्रियता की हवा निकाल दी. संपन्न तीन उप चुनाव में भाजपा एक भी सीट नहीं जीत पाई. राज्य की पांच की पाचों सीट भाजपा की झोली में डालने वाली जनता के मिजाज को न समझ पाना भाजपा को भारी पड़ा. कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने में अग्रणी भूमिका निभाने वाले जनरल को ही अब पार्टी में निपटाने का कुचक्र चल रहा है. भाजपा के बड़े नेता इन्हें राज्यपाल बना कर इनके सीट से सतपाल महराज को सांसद बनवाना चाहते है. इन दिग्गजों को यह बात ध्यान रखना चाहिए कि जनरल खंडूड़ी ने अपने अनुशासन पूर्ण जीवन का परिचय देते हुए उनके दबाव में आ भी जाते हैं, तो इस क्षेत्र की जनता हिसाब लेने से भी नहीं चुकेगी. ■

जीएसआई ने केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण की रिपोर्ट सौंपी

रेनु शर्मा

उत्तराखंड सरकार केदानाथ धाम को जीएसआई की रिपोर्ट के आधार पर आबाद करेगी. पावन मोक्षधाम में पूर्व की भांति बस्ती बसाने की मंसा पर रिपोर्ट ने पुरी तरह से पानी फेर दिया है. सरकार द्वारा केदारनाथ धाम को नए सिरे से स्थापित करने में एक कदम आगे और बढ़ाया गया है. जीएसआई (जियोलाजिकल सर्वे आफ इंडिया) ने मुख्य सचिव को केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण से संबंधित रिपोर्ट भी सौंप दी. रिपोर्ट में जीएसआई ने केदारनाथ मंदिर के पिछले हिस्से में आए बोल्डरों से कोई छेड़छाड़ न करने की सलाह दी है. जीएसआई ने वर्तमान में केदारनाथ मंदिर के आसपास के टाउनशिप को ध्वस्त करने की सलाह भी दी है. अब यह बात साफ हो गई है कि केदारधाम के आस-पास घनी आबादी बसाने पर पुरी तरह रोक लगी रहेगी. आस्थावान जनता को बाबा को मत्थाटेक कर वापस होना पड़ेगा. यह बात सचिवालय में मुख्य सचिव को जीएसआई के उप महानिदेशक टीएसपांगती की रिपोर्ट से साफ हो गया है.

रिपोर्ट में मंदिर के पिछले हिस्से में आये बोल्डर से छेड़छाड़ न करने का सुझाव दिया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक इन बोल्डरों को अपने स्थान पर ही मजबूति से रहने के लिए आधार तैयार किया जा सकता है. जीएसआई ने वर्तमान में क्षतिग्रस्त टाउनशिप को ध्वस्त करने का भी सुझाव दिया है. केदारनाथ मंदिर के सामने निचले हिस्से में पुजारियों और कर्मचारियों के लिए प्री फैब्रिकेटेड आवास बनाए जाएं. नीचे की ओर जो दो बड़े मैदान हैं इनमें पानी का रिसाव होता रहता है. इसके लिए पानी की निकासी की व्यवस्था करने को भी कहा गया है. रिपोर्ट में मंदाकिनी नदी के बायें तट पर कटाव को रोकने को भी कहा गया है.

जीएसआई ने पांचों आपदा प्रभावित जिलों के डिए टास्क फोर्स का गठन किया है. इसी तरह की एक टास्क फोर्स केदारनाथ के लिए भी गठित की गई थी. इस टास्क फोर्स की संस्तुतियों के आधार पर ही जीएसआई ने केदारनाथ के पुर्ननिर्माण का खाका तैयार किया है. जीएसआई की यह दूसरी रिपोर्ट है. इस रिपोर्ट का सरकार भी बेसब्री से इंतजार कर रही थी. कारण यह भी था कि सरकार को अभी यह तय करना है कि केदारनाथ मंदिर के आसपास के क्षेत्र में ध्वस्त मकानों और मलबे का क्या किया जाए. मंदिर से छेड़छाड़ न करने का इरादा सरकार पहले ही जाहिर कर चुकी है और यह काम एएसआई के जिम्मे है. इसी तरह केदारनाथ धाम से अलग हटकर टाउनशिप बनाने का इरादा सरकार पहले ही कर चुकी है. इसके डिए लिचौंली का सुझाव भी है. जीएसआई की इस रिपोर्ट से जाहिर है कि सरकार को अब केदारनाथ में बहुत अधिक निर्माण की लागत नहीं मिल पाएगी. इसी तरह केदारनाथ धाम के मंदाकिनी वाले हिस्से की तरफ बाढ़ नियंत्रण और स्लोप स्टेबलालेशन का काम भी सरकार को करना होगा. कुछ हद तक यह काम शुंरू किया भी जा चुका है. केदारनाथ में एक वर्ग दुकानों और लॉज मालिकों के लिए पुराने हिस्से पर ही निर्माण करने के पक्ष में है. जीएसआई की इस रिपोर्ट से इस वर्ग को झटका लगा है. इस रिपोर्ट ने सरकार को कई मायने में केदारनाथ मामले में आइना दिखाने का काम किया है. ■

feedback@chauthiduniya.com

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं
अजय वर्मा, प्रधान
ग्राम पंचायत, मऊदाउद पुर
विकास खण्ड लखीमपुर
कौशल किशोर वर्मा
ग्राम विकास अधिकारी
विकास खण्ड-लखीमपुर

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं
कक्षा 6-12 तक सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त
गुरुकुल विद्या पीठ
मढ़िया सड़क, गोला गोकर्ण नाथ, लखीमपुर खीरी
प्रबन्धक-धर्मेन्द्र कुमार
अशोक कुमार
जिला विद्यालय निरीक्षक
लखीमपुर खीरी